(आरक्षित निर्णय)

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (आपराधिक) नं. 2020 का 1182

उमेश कुमार शर्मा याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी

साथ मे,

रिट याचिका (आपराधिक) नं. 2020 का 1187

उमेश कुमार शर्मा याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी

साथ में

रिट याचिका (आपराधिक) नं. 2020 का 1285

शिव प्रसाद सेमवाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य प्रतिवादी

उपस्थित :- श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अरुणव चौधरी, श्री अंकुर चावला और श्री आदित्य सिंह, अधिवक्ताकर्ताओं के अधिवक्ता।श्री P.S. पटवालिया वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गुप्ता, उप महाधिवक्ता और श्री J.S. विर्क, राज्य के उप महाधिवक्ता।श्री रामजी श्रीवास्तव और श्री नवनीत कौशिक, प्रतिवादी हरेंद्र सिंह रावत के वकील

निर्णय

माननीय रवींद्र मैथानी, जे.

इन रिट याचिकाओं में कानून का एक सामान्य प्रश्न उठाया गया है, इसलिए, उनका निर्णय इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 07.07.2020 के संचार, दिनांक 30.07.2020 की जांच रिपोर्ट और प्राथमिकी संख्या को रद्द करने की मांग की। 2020 का 265, भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469,471,120 बी, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून के से।

3. इस निर्णय में, पक्षों और सामग्री को रिट याचिका (आपराधिक) [डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल.] सं. 2020 का 1187।

तथ्य

4. 24.06.2020 को, प्रतिवादी ने सोशल मीडिया पेज ("सोशल मीडिया प्रकाशन") पर एक वीडियो अपलोड किया और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ बैंक खातों के साथ दस्तावेज दिखाए।2 डॉ. हरेंद्र सिंह रावत (इसके बाद "मुखबिर" के रूप में संदर्भित) और उनकी पत्नी श्रीमती सविता रावत।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के पश्चात मुखबिर और उसकी पत्नी के खातों में पैसा जमा किया गया था, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (संक्षेप में "टीएसआरसीएम") के लिए रिश्वत के रूप में था।वीडियो में याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि श्रीमती. सविता रावत टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की असली बहन है और टी. एस. आर. सी. एम. ने मुखबिर और उसकी पत्नी के बैंक खातों में जमा के माध्यम द्वारा रिश्वत का पैसा प्राप्त किया।

5. 09.07.2020 को, मुखबिर ने सोशल मीडिया प्रकाशन में याचिकाकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच के अनुरोध के साथ पुलिस को दिनांक 07.07.2020 ("दिनांक 07.07.2020 का संचार") का एक आवेदन दिया।दिनांक 09.07.2020 को भेजे गए पत्र में सूचना देने वाले ने लिखा कि वह एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

उनकी पत्नी डॉ. सविता रावत एसोसिएट प्रोफेसर हैं।मुखबिर ने सोशल मीडिया प्रकाशन में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया किः

5.1.यह पूरी तरह से गलत है कि वह टीएसआरसीएम का रिश्तेदार है। 5.2.यह पूरी तरह से गलत है कि उसकी पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की बहन है।

5.3.यह पूरी तरह से गलत है कि विमुद्रीकरण के दौरान झारखंड से कोई भी पैसा उनके या उनके परिवार के सदस्य के खाते में जमा किया गया था।

6. सूचना देने वाले का दिनांक 07.07.2020 का संचार बैंक के प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित था और सूचना देने वाले के अनुसार याचिकाकर्ता इन दावों को करके जनता को गुमराह कर रहा था और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा था।

7. मुखबिर ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया प्रकाशन में लगाए गए झूठे आरोपों की जांच की जा सकती है।

8. दिनांक 07.07.2020 के इस संचार पर, सुश्री पल्लवी त्यागी, सर्कल अधिकारी, नेहरू नगर, जिला देहरादून (संक्षेप में "सीओ") द्वारा एक जांच की गई थी और जांच के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया था किः

8.1.विमुद्रीकरण के दौरान झारखंड से सूचना देने वाले या उसके परिवार के सदस्यों के खातों में पैसा जमा नहीं किया गया था

8.2.मुखबिर टी. एस. आर. सी. एम. का रिश्तेदार नहीं है और मुखबिर की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की बहन नहीं है।
8.3.कि जिन दस्तावेजों के आधार पर यह दावा किया गया है कि सूचना देने वाले और उसके परिवार के सदस्यों के खातों में पैसे जमा किए गए थे, वे निश्चित रूप से जाली हैं।
9. यह रिपोर्ट सीओ द्वारा 30.07.2020 को तैयार की गई थी।सूचना देने वाले ने दिनांक 07.07.2020 और 31.07.2020 को अपने संचार पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "आरटीआई अधिनियम") से सूचना देने वाले को 30.07.2020 की रिपोर्ट की एक प्रति दी गई थी।
इसके आधार पर, उसी दिन, प्राथमिकी नं 2020 की 265 भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469,471 और 120 बी, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून सूचना देने वाले के द्वारा दर्ज की गई थी ("तत्काल प्राथमिकी")।यह (अनुवाद) इस प्रकार हैः
"सेवा में,
स्टेशन प्रभारी, P.S. नेहरू कॉलोनी, देहरादून सर,
विनम्र प्रस्तुतीकरण यह है कि मैं, डॉ. हरिंदर सिंह रावत, मैं एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूं, और वर्तमान में मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मियांवाला, देहरादून का प्रबंधक हूं।मैं डेयरी फर्मों के संघों का अध्यक्ष हूं।पिछले साल (एसआईसी महीने) जब मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी तो मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।मेरी पत्नी डॉ सविता रावत B.Ed विभाग डीएवी (पीजी) कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।पिछले साल मेरे जान पहचान वाले श्री ज्योति विजय रावत ने मुझे बताया कि उमेश कुमार शर्मा नाम का एक व्यक्ति जो आम तौर पर ब्लैकमेलर के रूप में जाना जाता था और अतीत में उसे जेल हो चुकी थी।उन्होंने फेसबुक पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी के विरुद्ध आरोप लगाया है कि विमुद्रीकरण के दौरान श्री अमरेश सिंह चौहान नाम के एक व्यक्ति ने मेरे, मेरी पत्नी और प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन के विभिन्न बैंक खातों में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भुगतान करने के लिए जमा किया है, जिसे श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री अमरेश चौहान को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए रिश्वत के रूप में लिया था।उन्होंने मेरी पत्नी डॉ. सविता रावत को वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पत्नी की वास्तविक बड़ी बहन के रूप में पेश करने की पुरजोर कोशिश की।महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कथित प्रसारित वीडियो में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, आधारहीन और धोखाधड़ी वाले हैं। या तो मेरा या मेरी पत्नी का श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कोई संबंध नहीं है।कथित प्रसारित वीडियो में कहा गया है कि उमेश कुमार शर्मा बैंक खातों में जमा नकदी से संबंधित एक मनगढ़ंत दस्तावेज दिखा रहे हैं।वह दावा कर रहा है कि उन दस्तावेजों में कहा गया है कि झारखंड निवासी अमरेश चौहान ने मेरे और मेरी पत्नी के बैंक खातों में नकदी जमा की है।उमेश कुमार शर्मा और अमरेश चौहान ने अपने सहयोगियों के माध्यम द्वारा एक पूर्व नियोजित

साजिश के से एक-दूसरे के साथ मिलकर अवैध रूप द्वारा मेरे और मेरी पत्नी के बैंक खातों द्वारा संबंधित जानकारी प्राप्त की है और हमारी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक किया है, जिसके कारण हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी की जा सकती है।उन्होंने नकद राशि जमा करने और दस्तावेजों को छिपाने की साजिश रची है और अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आम जनता को सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत दस्तावेज दिखाए हैं।

उमेश कुमार शर्मा ने दावा किया कि मनगढ़ंत दस्तावेज मूल हैं और जनता को विश्वास दिलाया कि रिश्वत का पैसा मेरे और मेरी पत्नी के खातों में जमा हो गया है, जिसके कारण मुझे और मेरी पत्नी को मानसिक सदमा लगा और जनता हमारे बारे में अलग-अलग तरह की बातें कर रही है।मेरी बाईपास सर्जरी 24.08.2019 को हुई थी, जिससे मेरी सेहत पर भी बुरा असर पड़ा और मेरी तबीयत बिगड़ गई।मेरी तबीयत बिगड़ने के कारण, इसने मेरी जान को खतरे में डाल दिया, इसलिए मुझे इलाज के लिए फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ा।07.07.2020 को मैंने पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल क्षेत्र कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को उक्त उमेश कुमार शर्मा द्वारा मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए एक आवेदन दिया।मेरे आवेदन पर, एक राजपत्रित अधिकारी ने जाँच की और जाँच के दौरान, उन्होंने मेरे सभी बैंक खातों का बैंक विवरण प्राप्त किया और पाया कि मेरे किसी भी बैंक खाते में, अमरेश चौहान नाम के किसी भी व्यक्ति द्वारा झारखंड से कोई पैसा जमा नहीं किया गया था।लेकिन, जब जांच अधिकारी ने ई-मेल के माध्यम द्वारा उमेश कुमार शर्मा द्वारा जमा किए गए धन की प्राप्ति और बैंक द्वारा संबंधित दस्तावेजों के बारे में सवाल पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं, जो साबित करता है कि बैंक खातों में जमा किए गए धन द्वारा संबंधित सभी धोखाधड़ी वाले दस्तावेज उमेश कुमार शर्मा के पास पड़े हैं।हमारे वीडियो को सनसनीखेज बनाने के लिए उमेश कुमार शर्मा ने अपने वीडियो में संबोधित किया है कि इस रिश्वत घोटाले के बारे में लीक आदेश के पश्चात क्या आपकी समझ और सोचने की शक्ति ध्वस्त हो गई है, ये हरिंदर सिंह रावत और सविता रावत कौन हैं।सविता रावत माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी की बड़ी बहन हैं।इसके अलावा, उसके अन्य सहयोगी, जो सभी उसके ब्लैकमेलिंग के व्यवसाय में शामिल हैं और समाचार पोर्टल और समाचार पत्र चला रहे हैं, जिसमें प्रह्लाद टीवी, क्राइम स्टोरी और परवत जान शामिल हैं। इस सब के कारण, मुझे और मेरे परिवार को मानसिक यातना और क्रूरता का सामना करना पड़ रहा है।इसलिए, यह आपकी भलाई के लिए प्रार्थना की जाती है कि आवेदक की रिपोर्ट उपरोक्त अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की जाए और उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे सुरक्षा भी प्रदान की जाए, क्योंकि ये व्यक्ति आपराधिक प्रकृति के हैं।

आवेदक

(डॉ. हरिंदर सिंह रावत)

(रिट याचिका का अनुलग्नक 2)

(जोर दिया गया)

पृष्ठभूमि

10. तत्काल मुकदमा याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक मामला नहीं है।उनके विरुद्ध कई मामले हैं और उनके अनुसार, वर्तमान याचिका टीएसआरसीएम के विरुद्ध एक अमरेश सिंह चौहान द्वारा लगाए गए आरोपों से निकलती है कि उन्होंने गौ सेवा आयोग, झारखंड के अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए टीएसआरसीएम को Rs.25,00,000/- का भुगतान किया था क्योंकि टीएसआरसीएम प्रासंगिक समय में झारखंड का पार्टी राज्य प्रभारी था।

याचिका के अनुसार, अमरेश सिंह चौहान ने दावा किया थाः
"8. कि, प्रतिवादी संख्या. 3 ने निम्नानुसार दावा किया हैः----------श्री अमरेश सिंह चौहान का दावा है कि वह श्री T.S. रावत (उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री) के करीब थे। जो झारखंड के भाजपा के राज्य प्रभारी थे।
2. यह श्री चौहान द्वारा दावा किया जाता है कि उनका श्री T.S. रावत (सीएम) के साथ सौदा था। और अमरेश चौहान चाहते थे कि वे भाजपा राज्य सरकार के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करें और अमरेश को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करें।
3. यह दावा किया जाता है कि उक्त उद्देश्य के लिए T S रावत और A.S. चौहान के बीच एक सौदा तय किया गया था।चूंकि राशि भारी थी और इसके लिए टी. एस. रावत को कुछ अग्रिम देना पड़ता है।
4. इसके बाद, A.S. चौहान ने दिनांक 07.11.2016 को मुख्यमंत्री झारखंड श्री रघुवर दास को दिनांक 07.11.2016 को, विमुद्रीकरण से एक दिन पहले 08.11.2016 को एक पत्र लिखा। । ए एस चौहान द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को दिनांक 07.11.2016 को भेजे गए पत्र की प्रति 08.11.2016 को विमुद्रीकरण से एक दिन पहले दिनांक 07.11.2016 को रघुवर दास को इसके साथ संलग्न किया गया है और "अनुलग्नक यूआरई-3" के रूप में चिह्नित किया गया है।
5. इसके बाद उत्तराखंड राज्य के भीतर विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई और राज्य के भीतर आचार संहिता लागू की गई।
6. डोईवाला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सीएम टीएस रावत ने ए. एस. चौहान से कुछ राशि मांगी थी।
7. A. S. चौहान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष (अध्यक्ष), झारखंड के पद के लिए रिश्वत देने के लिए तैयार थे क्योंकि पॉइंट A के बारे में यह स्पष्ट था कि T.S. रावत उस समय भाजपा झारखंड के राज्य प्रभारी थे।

8. यह रिश्वत राशि यथा, श्री T.S. रावत, के करीबी रिश्तेदारों और करीबी परिचित लोगों के खातों में नकद में जमा की गई थी।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	नाम.	खाता संख्या	आईएफएससी कोड
1.	पीएनबी विधानसभा देहरादून	हरेंद्र सिंह रावत और सविता (ध्यान दें वे मुख्यमंत्री के बहनोई और साली हैं। सुश्री सविता रावत मुख्यमंत्री की पत्नी सुश्री सुनीता रावत की वास्तविक बहन हैं)	4422000101007449	PUNB0442200
पीएनबी विधानसभा देहरादून	राजेंद्र सिंह रावत (वे मुख्यमंत्री के करीबी दोस्त हैं)	44220001010 1143	PUNB0442200	
एसबीआई डिफेंस कॉलोनी, देहरादून	& सविता रावत (ध्यान दें- वे जीजा और साली हैं।	मुख्यमंत्री के हरेंद्र सिंह रावत। सुश्री सविता रावत, सुश्री सुनीता रावत की वास्तविक बहन हैं, जो मुख्यमंत्री की पत्नी हैं		
	10014685495	एसबीआईएन 00 0822		

			मंत्री)
4.	केनरा बैंक मियांवाला देहरादून	हरेंद्र सिंह रावत और सविता रावत (ध्यान देंवे मुख्यमंत्री के बहनोई और साली हैं।सुश्री सविता रावत मुख्यमंत्री की पत्नी सुश्री सुनीता रावत की वास्तविक बहन हैं)	4463101000800
CNRB0004463	5.	पीएनबी विधानसभा देहरादून	हरेंद्र सिंह रावत एंड संस (एचयूएफ) (ध्यान दें- वे मुख्यमंत्री के जीजा और साली हैं।सुश्री सविता रावत मुख्यमंत्री की पत्नी सुश्री सुनीता रावत की वास्तविक बहन हैं)
4422000101066080	PUNBV0442200	इलाहाबाद बैंक नेहरू कॉलोनी देहरादून	हरेंद्र सिंह (ध्यान दें- वे मुख्यमंत्री के जीजा और जीजा हैं।सुश्री सविता रावत मुख्यमंत्री की पत्नी सुश्री सुनीता रावत की वास्तविक बहन हैं)
21071300696	ALLA0211873	2.	.

7 वें स्थान पर	एस. बी. आई. कुंदेश्वन	हरेंद्र सिंह (ध्यान देंवे मुख्यमंत्री के बहनोई और साली हैं।सुश्री सविता रावत	33115909228	एसबीआईएन0007398

		मुख्यमंत्री की पत्नी सुश्री सुनीता रावत की वास्तविक बहन हैं)		
8	बीओबी हरिद्वार देहरादून	प्रगतिशील डेयरी किसान कल्याण संघ (ध्यान दें- श्री हरेंद्र सिंह रावत इस इकाई के नियंत्रण में हैं)	41460100000596	बारबोर्डेह
9.	बीओबी हरिद्वार देहरादून	नवीन सिंह बिष्ट (ध्यान देंवह श्री T.S. का मित्र है। रावत)	41460100000056	बारबोर्डेह
10.	एसबीआई जोगीवाला देहरादून	राजेंद्र कौशल (ध्यान दें- व्यक्ति जानता है कि आप सीएम के करीब होंगे)	32958098114	एसबीआईएन 001615 8
11	एसबीआई उत्तरांचल ग्रामीण बैंक मोहकमपुर	रजनी (ध्यान दें- व्यक्ति जानता है कि आप सीएम के करीब होंगे)	76006607094	SBINORRUTGB

12.	एसबीआई उत्तरांचल ग्रामीण बैंक मोहकमपुर	रामू धीमान (ध्यान दें- व्यक्ति जानता है कि आप सीएम के करीब होंगे)	4113022734	SBINORRUTGB
13.	आईडीबीआई बैंक नेहरू कॉलोनी	विक्की शर्मा (ध्यान दें- व्यक्ति जानता है कि आप सीएम के करीब होंगे)	1032102000004657	आईबीकेएल 0001032
14.	एसबीआई-आईआईपी	चंद्र शोभा डब्ल्यू/ओ सुरेश चंद ध्यान दें- व्यक्ति जानता है कि आप सीएम के करीब होंगे)	10075140072	एसबीआईएन 0002359

क्रम संख्या	बैंक का नाम	नाम.	खाता संख्या	आईएफएससी कोड
समाज	ए.	/	सी.	-
	पाँचवाँ	एल. ए. सी.	एक.	समय
तक		एस -		
1.	केनरा बैंक मियांवाला देहरादून (बचत)	उषा सोसाइटी फॉर ह्यूमन अफेयर्स ध्यान देंएम श्री हरेंद्र	4463101000795	CNRB0004463

		सिंह रावत इस इकाई के नियंत्रण में हैं)		
	2.	बी. ओ. बी. हरिद्वार देहरादून (बचत)	शिक्षा ध्यान दें- श्री हरेंद्र सिंह रावत	नालंदा कॉलेज इस इकाई के नियंत्रण में है)
41460100000168	बारबोर्डेह	3.	BOB हरिद्वार देहरादून (P.D.F.A.) (वर्तमान)	संगठन ध्यान दें- श्री हरेंद्र सिंह रावत

बैंक जमा रसीदें

नोट-उपरोक्त सभी बैंक रसीदें देहरादून के एक पत्रकार श्री राजेश शर्मा द्वारा दी गई थीं और वही A.S. चौहान द्वारा उनके मोबाइल नंबर से भेजी गई थीं। 9431361039 व्हाट्सएप नंबर पर राजेश शर्मा को भेजें। 9897598151.संदेशों का विवरणः

A) फरवरी 2018-A.S. चौहान ने राजेश शर्मा को एक पक्ष के बारे में संदेश दिया कि उन्होंने सीएम टीएस रावत को उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक राशि दी है और सीएम उसी राशि को वापस नहीं कर रहे हैं।इसलिए, वह चाहते हैं कि राजेश शर्मा इसे मीडिया में प्रकाशित करें।(नोटः मात्र एक संदेश का आदान-प्रदान हुआ है जिसमें कहा गया है कि वह राजेश से बात करना चाहता है, जिसके बाद उसने राजेश को फोन किया और उससे बातचीत की)।

बी) 07.02.2018-इसके बाद, एएस चौहान ने CMT.S के साथ व्हाट्सएप वार्तालाप प्रदान किया। रावत से राजेश शर्मा तक।

सी) 07.02.2018-व्हाट्सएप पर राजेश ने चौहान से सीएम को पैसे देने का उद्देश्य पूछा।

D) 07.02.2018-A.S. चौहान ने जवाब दिया, कि जब सीएम टीएस रावत झारखंड के भाजपा के राज्य प्रभारी थे, तो मैंने खुद को अध्यक्ष गो सेवा, झारखंड के रूप में नियुक्त करने के लिए उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझसे चुनाव खर्च के लिए पैसे मांगे।तो A.S. चौहान ने सीएम के करीबी गठबंधनों और रिश्तेदारों के खातों में पैसा जमा किया।

ई) फरवरी के महीने के आसपास-एक ऑडियो रिकॉर्डिंग राजेश शर्मा द्वारा रिकॉर्ड की गई थी जब ए. एस. चौहान ने उन्हें अपने मोबाइल नंबर 09897598151 पर कॉल किया और उन्हें A.S. चौहान और T.S. के बीच अतीत में हुई घटनाओं का पूरा विवरण बताया। रावत।ऑडियो वार्तालाप की प्रतिलिपि की प्रति ऑडियो वार्तालाप की डीवीडी (AROUND FEBRUARY) के साथ संलग्न है और "अनुलग्नक-4 (COLLY)" के रूप में चिह्नित है।

एफ) 13.01.2019-अमरेश चौहान ने फेसबुक पर माननीय मुख्यमंत्री के वकील के साथ अपने आवास पर एक तस्वीर पोस्ट की, इसके पश्चात 22.01.2019 को अमरेश सिंह चौहान को उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर 39 एकड़ जमीन दी गई, जिसकी पुष्टि उनके फेसबुक पोस्ट से 22.01.2019 को सुबह 07.17 बजे उनके अकाउंट से ली गई थी, इस तथ्य की पुष्टि करता है कि रांची के अमरेश सिंह चौहान को एक अज्ञात व्यक्ति की सहायता से उत्तरांचल उत्तराखंड की सीमा पर 39 एकड़ खेत दिया गया था।

जी) 27.12.2016 (01:33 P.M.)-सीएम टीएस रावत ने अमरेश सिंह चौहान के साथ व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान किया, दिनांक 27.12.2016 को एक पाठ संदेश में, अमरेश चौहान ने कहा कि उन्होंने रजनी के खाते में Rs.50,000/-, रामू के खाते में 50,000/-, रु। 50, 000/- राजेश और अग्रेतर बताया कि रु। 3,00,000/- राजेंद्र कौशल के खाते में जमा किए जाएंगे। अमरेश चौहान और माननीय मुख्यमंत्री के बीच दिनांक 23.12.2016 और 27.12.2016 के व्हाट्सएप संदेशों की प्रति संलग्न है और "अनुलग्नक-5 (कोली)" के रूप में चिह्नित है।कि अमृतेश चौहान द्वारा दी गई रिश्वत राशि का भुगतान CM T.S. से जुड़े सभी व्यक्तियों के खाते में किया गया था। रावत।

एच) 29.12.2016 (03:36 P.M.)-अमृतेश द्वारा दी गई रिश्वत राशि का भुगतान सीएम टीएस रावत के गठबंधनों के खाते में किया गया था, यह न मात्र भुगतान किया गया था बल्कि सीएम T.S. रावत ने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम द्वारा A.S. चौहान द्वारा इस संबंध में फॉलो-अप लिया है, जिसमें उन्होंने रजनी के खाते में भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि की है और अग्रेतर पुष्टि की है कि रामू और राजेंद्र के खातों में भुगतान अभी भी इंतजार कर रहे हैं।माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29.12.2016 को अमरेश चौहान को भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है और "अनुलग्नक-6" के रूप में चिह्नित है।

I) 30.12.2016 (03:34p.m)-अमरेश चौहान ने सीएम टीएस रावत को राजेंद्र के खाते में रु 3,00,000/- नकद जमा पर्ची।अमरेश चौहान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 30.12.2016 को भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है और "अनुलग्नक-7" के रूप में चिह्नित है।

J) 15.01.2017 (11.04 A.M.)-A.S. चौहान ने अपने संदेश में CM T.S को अवगत कराया था। रावत ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद एकल खाते में 2 लाख से अधिक की राशि जमा नहीं की जा सकती है और इसलिए उनके सीए ने एक खाते में 2 लाख जमा करने का सुझाव दिया है, इसलिए कल 15 लाख जमा किए जाएंगे और अग्रेतर पांच अन्य बैंक खाता संख्या प्रदान करने का अनुरोध किया है।अमरेश चौहान द्वारा दिनांक 15.01.2017 को माननीय CM T.S. रावत को भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न किया गया है और "अनुलग्नक-8" के रूप में चिह्नित किया गया है।

के) 16.01.2017 (11:17 P.M.)-सीएमटीएस रावत ने अपने करीबी गठबंधनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के 12 बैंक खाता नंबरों का विवरण वाली एक शीट अमरेश सिंह चौहान को भेजी ताकि रु अमरेश द्वारा विभिन्न बैंक खातों में 2 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं।दिनांक 16.01.2017 CM T.S. रावत द्वारा अमरेश चौहान को भेजे गए WhatsApp संदेशों की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न किया गया है और "अनुलग्नक-9" के रूप में चिह्नित किया गया है।

L) 01.02.2017 (07:11 AM)-अमरेश चौहान ने CM T.S. रावत से पूछा उन्हें नकदी जमा करने के लिए चालू खाते के नंबर भेजे ताकि वे भुगतान भाग को पूरा कर सकें।अमरेश चौहान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 01.02.2017 को भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है और "अनुलग्नक-10" के रूप में चिह्नित है

एम) 01.02.2017

(10:54 PM) सीएम टीएस रावत ने उन्हें उषा सोसाइटी, नालंदा कॉलेज और प्रोग्रेसिव डेयरी नामक 3 खातों का चालू खाता विवरण प्रदान किया-सभी तीन खाते सीएम के करीबी रिश्तेदार हरेंद्र रावत के हैं, जो T.S. रावत के सलाहकार थे। 5 साल के लिए जब T.S. रावत U.K. सरकार में कृषि मंत्री थे।

एन) 06.02.2017 (08:41 P.M.)-A.S. चौहान ने CM T.S. रावत को मैसेज किया. उपरोक्त चालू खातों में प्रत्येक में 5 लाख रुपये जमा करने के संबंध में और मुख्यमंत्री झारखंड को गौ सेवा आयोग पद की अधिसूचना जारी करने के लिए कहने के लिए कहा, जिसे वह अपने खाते में जमा करेंगे।अमरेश चौहान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 06.02.2017 को भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है और "अनुलग्नक-11" के रूप में चिह्नित है।

O) 12.02.2017-A.S. चौहान ने T.S. रावत को सूचित किया। कहा कि वह अग्रेतर कोई भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि उनका परिवार बहुत परेशान है और अग्रेतर तर्क दिया कि वह गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद अग्रेतर भुगतान करेंगे।A.S. चौहान ने अपने खाते अक्की के कृषि खाता संख्या सीए 792993573, इंडियन बैंक, कद्रू रोड, रांची में पैसे वापस करने की शर्त भी रखी।अमरेश चौहान द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 12.02.2017 को भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों की प्रति इसके साथ संलग्न है और "अनुलग्नक-12" के रूप में चिह्नित है।

9. कि, याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए खातों में से एक नं।2 शिकायतकर्ता से संबंधित है और शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसके खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता के से धोखाधड़ी, जालसाजी और कई अन्य अपराध किए हैं, जबकि प्रतिवादी संख्या.2 द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया था, जिसे सितंबर, 2019 में "फेसबुक" पर डाल दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता

ने मात्र प्रतिवादी संख्या. 2 द्वारा प्रदान किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है और इसे जाली बनाने के लिए एक भी दस्तावेज नहीं बनाया गया है।
10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक दस्तावेज और बैंक खाते जो वर्तमान शिकायत का आधार हैं, इस माननीय न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (आपराधिक) सं. 2018 का 2113 "उमेश शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य" शीर्षक से और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा सीबीआई द्वारा जांच की मांग की गई है।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित शिकायत उन आरोपों पर जांच शुरू करने का प्रयास करती है जो पहले से ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष जांच का विषय हैं और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में एक स्पष्ट हस्तक्षेप है।
11. याचिकाकर्ता को भेजी जा रही प्रश्नावली से यह स्पष्ट है कि इसे याचिकाकर्ता से उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा गया है ताकि शिकायत में सुधार किया जा सके और बाद की प्राथमिकी में धाराओं को जोड़ा जा सके। उक्त प्रश्नावली स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि याचिकाकर्ता को उन दस्तावेजों के लिए जालसाजी के अपराध के से फंसाने के लिए जांच की जा रही है जो याचिकाकर्ता के सार्वजनिक डोमेन (सोशल मीडिया) में हैं।
12 कि याचिकाकर्ता पेशे से एक पत्रकार और बांग्ला भारत समाचार चैनल का सी. ई. ओ. है और अपने पेशेवर दायित्व का निर्वहन करते हुए उसने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदारों के विरुद्ध उनके द्वारा अवैध रूप से रिश्वत लेने के संबंध में स्टिंग ऑपरेशन किया है।यह वह पद है जिस पर याचिकाकर्ता को उत्तराखंड सरकार के उच्च सार्वजनिक पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सताया जा रहा है।

उस समय याचिकाकर्ता "समाचार प्लस" समाचार चैनल के मुख्य संपादक थे।11. याचिकाकर्ता के समाचार चैनल संवाददाता द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में, याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तराखंड सरकार में भ्रष्टाचार श्रृंखला पर एक विशेष कहानी के संबंध में, जहां शीर्ष अधिकारी, उनके रिश्तेदार, दोस्त और उनके सहयोगी गुप्त प्रथाओं में शामिल थे, पं. अयुस गौर (संक्षेप में "पहले मुखबिर") ने याचिकाकर्ता से कहानी की मंजूरी के साथ-साथ 17.04.2018 (याचिका के पैरा 17 (0)) को नकद अनुरोध किया।पहले मुखबिर ने अपने ई-मेल के माध्यम द्वारा बताया कि वह टी. एस. आर. सी. एम. के एक करीबी सहयोगी द्वारा मुलाकात करेगा, जिसके साथ पहला मुखबिर निर्माण के अनुबंधों के बारे में बात करेगा।विशेष कहानी बनाने के आदेश, पहले सूचना देने वाले ने इस प्रकार आगे बढ़ना शुरू किया (जवाबी हलफनामे में विवरण):
11.1.18.04.2018 को, पहला मुखबिर उत्तराखंड में एक होटल/रिसॉर्ट बनाने के लिए जमीन खरीदने के इरादे से होटल समूह के प्रतिनिधि के रूप में एक संजय गुप्ता से मिला।संजय गुप्ता

पहले मुखबिर को रानीपोखरी में अपनी जमीन पर ले गए और उनकी बातचीत को पहले मुखबिर ने रिकॉर्ड किया।(अनुलग्नक आरए -9)

11.2.इस बातचीत में संजय गुप्ता ने खुलासा किया कि टी. एस. आर. सी. एम. के भतीजे छोटे अधिकारियों को प्रभावित करके पैसा कमाते हैं।(अनुबंध आरए-10 और आरए-11)

11.3.याचिकाकर्ता के अनुसार, संजय गुप्ता टी. एस. आर. सी. एम. के वाहक थे। उसी दिन पहला मुखबिर मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी से एक होटल में रात्रिभोज पर मिला।उनकी बातचीत को पहले मुखबिर ने भी रिकॉर्ड किया था।(अनुलग्नक आरए-12)

11.4.19.04.2018 को, पहले मुखबिर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के कारण संजय गुप्ता को Rs.5,00,000/- का नकद दिया और यह तय किया गया कि बैठक आयोजित होने पर बाद में Rs.10,00,000/- दिया जाएगा।इस बातचीत को पहले मुखबिर ने भी रिकॉर्ड किया था। (अनुलग्नक आरए-13)

11.5.अन्य बैठकों का भी विवरण है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 05.05.2018 को पहले मुखबिर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संजय गुप्ता एक हिस्सा थे।

उसी दिन शाम को पहले मुखबिर ने संजय गुप्ता को Rs.2,00,000/- दिए।इस बातचीत को भी पहले मुखबिर ने रिकॉर्ड किया था।(अनुलग्नक आरए-15)

11.6.05.05.2018 की शाम को, पहले मुखबिर ने संजय गुप्ता को Rs.2,00,000/- का भुगतान किया और बातचीत को अग्रेतर रिकॉर्ड किया गया।(अनुलग्नक आरए-21)

11.7.याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संजय गुप्ता को जवाबी कार्रवाई में उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान दें आदेश के लिए Rs.5,00,000/- में से 2,00,000/- दिए गए थे, क्योंकि दी गई राशि प्रतिबद्ध राशि से कम थी।(अनुलग्नक आरए-22)

11.8.इसके बाद संजय गुप्ता ने अपनी पत्नी का खाता नंबर दिया जिसमें 08.05.2018 को पहले मुखबिर द्वारा Rs.2,40,000/- जमा किए गए थे।(अनुलग्नक रा-22) 11.9.02.06.2018 को, पहले मुखबिर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के भाई वीरेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और उन्होंने उत्तराखंड के स्कूलों में रोबोटिक विज्ञान को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री को बाध्य करने के बारे में बात की और उत्तराखंड राज्य में खनन से संबंधित मुद्दा भी चर्चा के लिए आया।बैठक उसी दिन टीएसआरसीएम के घर एस-3/सी-130, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून में आयोजित की गई थी।पूरी बातचीत को पहले मुखबिर अग्रेतर रिकॉर्ड किया गया था।(अनुलग्नक रा-23) 11.10.05.05.2018 को मुख्यमंत्री के साथ बैठक के पश्चात पहले मुखबिर ने सुरक्षा अधिकारी से अपना जासूसी कैमरा लिया और जो भी बातचीत हुई उसे पहले मुखबिर ने रिकॉर्ड किया।मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं।(अनुलग्नक आरए-17 और आरए-18)

11.11.विशेष कहानी के संबंध में अन्य छोटे विवरण, जो पहले मुखबिर द्वारा किए गए थे, याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में भी विस्तृत हैं।

12. यह सब होने पश्चात 10.08.2018 को, पहले मुखबिर ने याचिकाकर्ता और चार अन्य लोगों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज की, जो कि प्राथमिकी नं 2018 के 100, भा.दं.सं. की धारा 386,388,120 बी, पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून ("प्राथमिकी नं 2018 के100 ") यह प्राथमिकी नं. 2018 से 100 इस प्रसेर है (अनुवाद);

सेवा में,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून, उत्तराखंड।महोदय
मैं, पंडित आयुष गौर, उत्तराखंड में न्यू चैनल समाचार प्लस के संपादक, जांच के पद पर कार्यरत, इस चैनल के प्रधान संपादक/सीईओ श्री उमेश कुमार शर्मा, आर/ओ टॉवर नं. 19, फ्लैट नं. 19241, इंद्रपुरम, P.S. इंद्रपुरम, गाजियाबाद, पिन 20104.कार्यालय का पताःH-74, सेक्टर 63, नोएडा, P.S. सेक्टर 58 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।वहाँ मैं पिछले ढाई साल से काम कर रहा हूँ।मेरे अलावा उमेश शर्मा की भतीजी प्रवीण साहनी और सौरभ साहनी और राहुल भाटिया भी चैनल के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं।स्टिंग ऑपरेशन में ये लोग जासूसी कैमरे के माध्यम द्वारा मंत्रियों और अधिकारियों को फंसाते हैं।लेकिन, उमेश शर्मा अपने चैनल पर समाचार प्रसारित नहीं करता है और एक पूर्व नियोजित साजिश से वह उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे कमाता है।इसी इरादे से उन्होंने मधु और राहुल भाटिया को देहरादून, उत्तराखंड भेजा है।इस दौरान उमेश लगातार मुझ पर मंत्रियों, नौकरशाहों और अधिकारियों को फंसाने के लिए फोन पर दबाव डालता रहा।जिनका क्रमवार विवरण नीचे दिया गया हैः
(1) 12.01.2018 को सीईओ ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ फर्जी और नकली पार्टियां तैयार की हैं और अपर मुख्य सचिव के साथ टक्कर में निविदा के बहाने वास्तविकता की जांच का आदेश दिया है और कहा है कि उन्होंने इस सूचना की पुष्टि की है कि उत्तराखंड में कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कुछ मंत्री धोखाधड़ी में शामिल हैं।
(2) 19.01.2018 को श्री उमेश कुमार ने मुझे फोन पर बताया कि आप दिल्ली स्थित उत्तराखंड गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और मृत्युंजय मिश्रा से मिलेंगे और आगे कहा कि मृत्युंजय मिश्रा आपको अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश जी से परिचित कराएंगे और कहा कि आप क्रमिक रूप से कुछ पैसे लेकर वहां पहुंचेंगे, जासूसी कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार करें।मैं 08.02.2018 को श्री उमेश कुमार शर्मा के निर्देश के अनुपालन में उत्तराखंड सदन (चाणक्यपुरी दिल्ली) पहुंचा और मृत्युंजय मिश्रा से मुलाकात की।
(3) 10.02.2018 को उत्तराखंड सदन में मृत्युंजय मिश्रा से मुलाकात की।16.02.2018 को मृत्युंजय मिश्रा ने 4:00 P.M. CM, उत्तराखंड राज्य के साथ बैठक के लिए शाम का समय।

उमेश कुमार ने मुझे कुछ पैसे ओम प्रकाश जी को सौंपने और उसे जासूसी कैमरे में अभिलेख करने का भी निर्देश दिया है और उसके बाद आपको सीएम से मिलना होगा और कोशिश करनी होगी कि सीएम खुद अपने मुंह से कहें कि वह हमारे साथ हैं।

(4) 16.02.2018 से 18.03.2019 तक, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या कोई अधिकारी किसी पैसे की मांग कर रहा है या गलत काम कर रहा है।जबकि उमेश कुमार अपनी योजना से लगातार मुझ पर दबाव बना रहे थे, जिसके कारण मैं परेशान था लेकिन सीएम तक नहीं पहुंच सका और इस तरह उनकी योजना विफल हो गई।उमेश ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम द्वारा देहरादून बुलाया और कहा कि फिर आपरेशन करना है।यह घटना 30.03.2018 की है, इसके क्रम में 16.04.2018 और 27.04.2018 को मैं देहरादून आया था।इस घटना की जानकारी राहुल भाटिया को दी गई थी।राहुल भाटिया ने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया, जिनके सीएम के साथ संबंध हैं। 18.04.2018 को रिकॉर्डिंग ऑपरेशन पूरा करने के पश्चात राहुल भाटिया ने उमेश शर्मा को फोन किया, फिर उमेश शर्मा ने हरक सिंह के परिवार के विवाह स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया।फिर मैं एक साथी और राहुल भाटिया के साथ हरक सिंह के परिवार के विवाह समारोह स्थल पर पहुँचा और वहाँ

चिप (मेमोरी कार्ड) उमेश कुमार को सौंप दी।

(5) 28.04.2018 और 29.04.2018 को मैं देहरादून में था।29.04.2018 को उमेश कुमार ने देहरादून के टेनिस कोर्ट में अपने घर पर राहुल भाटिया और उनकी भतीजी प्रवीण और दो अन्य लोगों से कहा कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है।हमारी योजना विफल हो जाती है, अगर मात्र एक बार, हम मुख्य सचिव को फंसाते हैं, तो यह हमारे लिए फायदेमंद होगा और फिर हमारा कोई भी काम नहीं रुकेगा और जो हम चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा क्योंकि राज्य में राजनीतिक अक्षमता होगी।यह सुनकर, मैं हैरान और हैरान था और मैं बहुत परेशान था क्योंकि उमेश कुमार और उनके सहयोगी मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और मेरा इस्तेमाल करके, वे राज्य में अशांति और अस्थिरता पैदा करने की योजना बना रहे थे।

(6) 05.05.2018 को मैं राहुल भाटिया और तीन जासूसी कैमरों के साथ सीएम के घर पर था और मुझे सीएम का स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए कहा गया था। चूंकि मुझे साजिश के बारे में पता था, इसलिए मैं अंदर से बहुत परेशान और अस्वस्थ था और मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं उनकी साजिश में सलाखों के पीछे नहीं जाऊंगा इसलिए मैंने जासूसी कैमरे बाहर छोड़ दिए और कोई रिकॉर्डिंग नहीं की।जब राहुल भाटिया को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उमेश शर्मा को पूरी बात बताई।इस वजह से उमेश शर्मा ने मुझे व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भेजे कि अगर आप स्टिंग आपरेशन में नाकाम रहे तो मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा और आपको उस जगह पर मार दूंगा जहां कोई आपको नहीं बचा पाएगा।

(7) सीईओ उमेश शर्मा बहुत नाराज थे और उन्होंने कहा कि वह स्टिंग के परिणाम चाहते हैं और इसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।

उन्होंने कहा कि धन की व्यवस्था की गई है, जो अधिकारियों को सरकार को अस्थिर करने के लिए रिश्वत के रूप में दी जाएगी और राहुल भाटिया ने भी इसका समर्थन किया था।राहुल भाटिया पैसे की व्यवस्था करने में अपना बराबर हिस्सा देते थे।वे कह रहे थे कि यह काम करना ही होगा।राहुल भाटिया इस साजिश में पूरी तरह से उमेश शर्मा के साथ थे।

(8) उमेश शर्मा अपने सहयोगियों के साथ आम तौर पर देहरादून आता है और उसका देहरादून, पुरुकुल में एक निवास है और वह गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है।उमेश शर्मा ने मुझे धमकी भी दी कि मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भेज दूंगा और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो।इतने सारे मंत्री और नेता मेरा पीछा कर रहे थे।मैंने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों के डंक मारे हैं।मैंने आपको मात्र एक छोटा सा काम दिया था और आप ऐसा नहीं कर सकते।सरकार मेरे हाथ में है।क्या आपने नहीं देखा कि सरकार ने मेरे विरुद्ध सभी मामले वापस ले लिए हैं।

(9)

उमेश कुमार ने एक गहरी साजिश रची है जिसमें उमेश कुमार, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, राहुल भाटिया, अन्य कर्मचारी, स्थानीय नेता और व्यवसायी शामिल हैं, जो राज्य में अशांति और हिंसा फैलाना चाहते हैं और मुझे यह पता है।समाज के सामने लाने के लिए इन सभी को सामने लाना मेरा कर्तव्य है।मुझे आशंका है कि उमेश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी भी अप्रिय घटना का कारण बन सकता है और मुझे पूरे जीवन के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है।उमेश कुमार अपने दोस्तों के साथ अपने लाभ के लिए अपने सहयोगियों के साथ अपने सहयोगियों को रिश्वत देने के लिए जांच कर रहा था।उमेश कुमार ने सभी उपकरण, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग उपकरण, मेमोरी कार्ड अपने निवास स्थान, अभिमन्यु टेनिस अकादमी मालसी ग्रीन के पास, मैक्स अस्पताल, डायवर्जन रोड, देहरादून और इंद्रपुरम के सामने, एटीएस इंद्रपुरम टॉवर नंबर. 19, फ्लैट नं. 19241, गाजियाबाद और कार्यालय एच 174, सेक्टर 63, समाचार प्लस नोएडा (7) गौतम बुद्ध नगर और राहुल भाटिया के आवास, आवास पनाश वैली, सहस्रधारा रोड, देहरादून।वह इन सभी चीजों को नष्ट करने और छिपाने की कोशिश कर रहा है।मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ये सारी जानकारी दे रहा हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आवेदक की रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जाए।

(जोर दिया गया)

प्राथमिकी नं. 2018 का 100 में विकास

13. इस प्राथमिकी नं. 2018 के 100 महत्वपूर्ण विकास हैं।यह प्राथमिकी 10.08.2018 को दर्ज की गई थी।याचिकाकर्ता के अनुसारः

13.1.

14.08.2018 को या उसके आसपास, जांच अधिकारी (आईओ) ने प्राथमिकी नं. 2018 के 100 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 70 और 91 से अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और तलाशी वारंट की मांग की गई थी।लेकिन, इसे 14.08.2018.13.2 को खारिज कर दिया गया था।18.08.2018 को, गिरफ्तारी और तलाशी वारंट की मांग करने वाला एक अन्य आवेदन अदालत के समक्ष आईओ द्वारा दायर किया गया था, लेकिन यह भी अदालत द्वारा यह देखते हुए खारिज कर दिया गया था कि भा.दं.सं. की खंड 386,388 और 120 बी से कथित अपराधों की जांच के लिए, मांगे गए दस्तावेज अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट में कोई कंसीम. 13.3 नहीं है।24.08.2018 को, आईओ द्वारा गिरफ्तारी और तलाशी वारंट के लिए दायर एक अन्य आवेदन को खारिज कर दिया गया था. 13.4.मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिनांक 24.08.2018 को पारित इस आदेश को आईओ द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी, जिसे याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना 12.10.2018 को अनुमति दी गई थी और इसके अनुसार, 22.10.2018 को संबंधित मजिस्ट्रेट ने तलाशी और गिरफ्तारी वारंट जारी किए। 13.5.28.10.2018 को, याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा प्राथमिकी नं 2018.13 का 100.6. आपराधिक मामला नं. 2017 का 207 एफ. आई. आर. सं. 2017 का 16, पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून ("2017 की प्राथमिकी संख्या 16") याचिकाकर्ता के विरुद्ध लंबित था।पुलिस ने प्राथमिकी संख्या में याचिकाकर्ता की हिरासत भी प्राप्त की। 30.10.2018 को 2017 का 16, न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करके जो उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. सं. 2010 की धारा 818 ने 03.06.2014 को मामले में स्थगन स्थगन आदेश पारित किया।

13.7.16.11.2018 को, याचिकाकर्ता को प्राथमिकी नं 2018 का 100 लेकिन किसी अन्य मामले में उत्पादन जमानत के कारण उन्हें रिहा नहीं किया गया और उन्हें रांची, झारखंड ले जाया गया।अंत में, याचिकाकर्ता को नवंबर, 2018. के महीने में हिरासत से रिहा कर दिया गया। 13.8.बीच में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अन्य प्राथमिकियां भी दर्ज की गईं, जिनका उल्लेख बाद के चरण में किया जाएगा।

13.9.उनकी रिहाई पश्चात याचिकाकर्ता ने टीएसआरसीएम से जुड़े भ्रष्टाचार के संबंध में दिल्ली में 28.01.2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो याचिकाकर्ता के अनुसार राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था और इस मुद्दे को state. 13.10 की विधानसभा में भी उठाया गया था।यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राथमिकी की प्रगति के दौरान नं। 2018

की 100, प्राथमिकी नं. 2018 का 100 और याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113, जो अभी भी लंबित है।यह बाद में चरण में कुछ सीमा तक चर्चा की जाएगी। 13.11.प्राथमिकी नं. 2018 का 100, में आरोप पत्र सं 2019 का 32 दिनांक 25.03.2019 (अनुलग्नक 34) को दाखिल किया गया था।आई. ओ. ने आरोप पत्र में निम्नानुसार अभिलिखित किया है (अनुवाद):

.पूरी जांच और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह तथ्य साबित होता है कि आरोपी उमेश कुमार शर्मा ने जनवरी, 2018 के महीने में आरोपी राहुल भाटिया के साथ मिलकर वर्तमान स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई थी और उसी के निष्पादन की प्रक्रिया भी शुरू की थी और मई, 2018 के महीने तक कार्यान्वयन की कार्यवाही लगातार चल रही थी।लेकिन जानबूझकर स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण नहीं किया गया।10.08.2018 को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात और उसके पश्चात 28.10.2018 को उमेश कुमार शर्मा की गिरफ्तारी के पश्चात और 16.11.2018 को आरोपी की जमानत के पश्चात और 27.01.2019 को आरोपी उमेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उपरोक्त स्टिंग का प्रसारण प्रकाश में आया।यह स्पष्ट है कि स्टिंग दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था और इसे अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए जानबूझकर उस समय इसे प्रसारित नहीं किया गया था।इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रजत प्रसाद बनाम सीबीआई मामले में वर्ष 2014 में अपने निर्णय में कहा है कि उक्त स्टिंग के संचालन और प्रसारण में बारह दिनों का अंतराल एक लंबा अंतराल है।इसके अलावा, आरोपी उमेश कुमार ने सी. आर. P. नं. 2018 के 2113/07 नैनीताल में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की में स्टिंग ऑपरेशन करने के तथ्य को स्वीकार किया है।उपरोक्त तथ्यों और जांच खंड यह साबित होता है कि आरोपी उमेश कुमार शर्मा और राहुल भाटिया शिकायत को नुकसान पहुंचाने के इरादे खंड पं. आयुष गौर ने उखंड खतरे में डालकर स्टिंग करवाई और उखंड कंपनी ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और सभी स्थानों पर शोबोटिक्स एजुकेशनल नेटवर्क के प्रतिनिधि के रूप में शिकायतकर्ता को अलग-अलग नामों खंड पेश किया, जो संहिता की धारा 419 के से आता है।इसके अलावा, इस मामले में आरोपी व्यक्तियों उमेश कुमार शर्मा, राहुल भाटिया ने शिकायतकर्ता पं. आयुष गौड़ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उससे बेईमानी से स्टिंग कराई और उस चिप का इस्तेमाल करके उसे एक कीमती सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया।

जैसा कि पीड़ित संजय गुप्ता आदि के बयान से स्पष्ट है। यह अपराध भा.दं.सं. की धारा 385 और 387 के दायरे में आता है। इसलिए, जांच से, भा.दं.सं. की धारा 386 और 388 से अपराध का पता नहीं चला है।इस प्रकार भा.दं.सं. की धारा 386 और 388 को हटा दिया गया है और भा.दं.सं. की धारा 385,387,419 और 504 को जोड़ा गया है।....

(जोर दिया गया)

रिट याचिका (आपराधिक) सं. 2018 का 2113

14. प्राथमिकी में नं. 2018 का 100, याचिकाकर्ता को 28.10.2018 को गिरफ्तार किया गया था।हिरासत में रहते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 की 2113 को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां.याचिकाकर्ता ने टी. एस. आर. सी. एम. और उसके रिश्तेदारों के भ्रष्टाचार के मामले में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की भी मांग की (डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113 संलग्नक 26 है)।वास्तव में डब्ल्यूपीसीआरएल नं. 2018 का 2113, याचिकाकर्ता ने प्राथमिकी नं. 2018 का 100 और अदालत के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की जिसके द्वारा उसके विरुद्ध तलाशी और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. में याचिकाकर्ता नं. 2018 के 2113 में भी प्राथमिकी आर. सं. 2018 की धारा 100 और स्वतंत्र और सक्षम व्यक्तियों की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त एक स्वतंत्र विशेष जांच दल द्वारा प्रथम मुखबिर द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन, जो उत्तराखंड राज्य के प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ नहीं हैं या जांच के वैकल्पिक हस्तांतरण में डी. आई. जी. स्तर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.)।

15. प्रारंभ में, डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113, याचिकाकर्ता ने खुद को प्राथमिकी नं. 2018 का 100 और पहले मुखबिर द्वारा किया गया स्टिंग।लेकिन, डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. में दायर अपने जवाबी शपथ पत्र में। 2018 का 2113, याचिकाकर्ता ने स्वयं को प्राथमिकी आर. सं. 2018 का 100, इस प्रकार और पहले मुखबिर द्वारा अप्रैल, मई और जून, 2018 के महीनों में किया गया स्टिंग।लेकिन, दिनांक 09.03.2019 के प्रत्यर्थी शपथ पत्र के पैरा 12-ए में, याचिकाकर्ता ने वास्तव में उन सभी कथनों का खुलासा किया है (यह लगभग शाब्दिक पुनरुत्पादन है), जो उसने तत्काल रिट याचिका के पैरा 8 में किया है, जो टीएसआरसीएम के करीबी व्यक्तियों के खातों में अमरेश सिंह चौहान द्वारा रिश्वत के बयान से संबंधित है (तत्काल याचिका के पैरा 8 को इस निर्णय के पैरा No.10 में उद्धृत किया गया है, जैसा कि पहले किया गया है)।

उन्होंने अमरेश सिंह चौहान और टी. एस. आर. सी. एम. के बीच आदान-प्रदान किए गए खातों और व्हाट्सएप संदेशों का विवरण दिया है। शीर्षक IV पर जवाबी शपथ पत्र में, याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से पहले मुखबिर द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच की भी मांग की।

16. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. से संबंधित कुछ तथ्य नं. 2018 की 2113 को तत्काल रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी।यह न्यायालय सतर्क है कि तथ्यों का वर्णन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन विवाद को समझने और निर्णय लेने के लिए इन तथ्यों का वर्णन आवश्यक है।

17. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113, प्रत्युत्तर शपथ पत्र दिनांक 09.03.2019 है।यह 25.03.2019 को अदालत में प्रस्तुत किया गया था।डब्ल्यूपीसीआरएल नं. 2018 की 2113 पर 25.03.2019 के बाद सुनवाई हुई, लेकिन यह 14.05.2019 को सुनवाई का हिस्सा बनी रही।यह ध्यान दिया जा सकता है कि वास्तव में, डब्ल्यूपीसीआरएल नं. 2018 का 2113, दिनांक 16.04.2018 को एक शपथ पत्र स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून द्वारा 22.04.2019 को प्राथमिकी किया गया था, जिसके द्वारा, न्यायालय को सूचित किया गया था कि आरोप पत्र में प्राथमिकी 2018 का 100 वां. किया गया है।

18. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113,28.05.2019 को, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं।जबकि याचिकाकर्ता को एक पूरक शपथ पत्र दायर करना चाहिए था, ताकि प्रतिवादी को एक पूरक जवाबी शपथ पत्र दायर करने में सक्षम बनाया जा सके, इन आरोपों की गंभीरता, हमारे विचार में, प्रतिवादी द्वारा खंडन की आवश्यकता होगी।श्री J.S. Virk, विद्वान A.G.A. के लिए राज्य प्रस्तुत करेगा कि एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर जाएगा, प्रत्युत्तर शपथ पत्र में विशिष्ट आरोपों के जवाब में, सुनवाई की तारीख तक; और आरोप-पत्र और उसके संलग्नक की एक प्रति, अंग्रेजी में अनुवादित प्रतियों के साथ कम से कम आरोप-पत्र और F.I.R में संदर्भित व्हाट्सएप की, सुनवाई की तारीख तक इस न्यायालय के समक्ष भी रखी जाएगी।"

(जोर दिया गया)

19. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113,27.06.2019 को, राज्य ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र में खंडन हलफनामा (28.09.2020 को तत्काल मामले में दायर राज्य के अतिरिक्त शपथ पत्र के लिए अनुलग्नक 1) दायर किया।

राज्य ने अपने शपथ पत्र में कहा कि जवाबी शपथ पत्र के पैरा 12 (ए), 1,2,3,4,5,6,7,8 की सामग्री जांच का हिस्सा नहीं थी और न ही जांच के दौरान दस्तावेज जांच अधिकारी (प्रतिनिधि) को सौंपे गए थे।टी. एस. आर. सी. एम. भी डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113 लेकिन न तो उन्होंने और न ही राज्य ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब अपने जवाबी शपथ पत्र में दिया।यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने 28.05.2019 को प्रत्यर्थी शपथ पत्र में विशिष्ट आरोपों का खंडन/जवाब अपेक्षित किया था।

20. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. पर सुनवाई सं. 2018 का 2113 अभी भी जारी है।अभिलेख याचिका अभी भी लंबित है (इस अदालत ने डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. तत्काल याचिका के तर्क के समय 2018 का 2113, ताकि संदर्भ दिए जा सकें, जब भी आवश्यक हो और यह वही है जो न्यायालय कर रहा है)।

<u>प्राथमिकी नं. 2014 का 354</u>

21. अमरेश सिंह चौहान, जिसने कथित तौर पर टीएसआरसीएम द्वारा दिए गए विभिन्न बैंक खातों में Rs.25 लाख जमा करके टीएसआरसीएम को रिश्वत दी थी, ने भी प्राथमिकी नं याचिकाकर्ता के विरुद्ध 12.11.2018 को पुलिस स्टेशन अरगोडा, रांची में 04.11.2018 को भा.दं.सं. की खंड 124 ए, 387,389,506 के से 2018 का 354 (संक्षेप में "प्राथमिकी नं 2018 का 354)।प्राथमिकी आर. की एक प्रति याचिका के लिए संलग्नक 25 है, जो नीचे (अनुवाद) के रूप में है;

दिनांकः04.11.2018

सेवा में,

स्टेशन प्रभारी, अर्गोडा, P.S. रांची।

विषयःउत्तराखंड सरकार के विरुद्ध साजिश रचने के इरादे से सरकार के बारे में जानकारी देने के लिए उमेश कुमार शर्मा द्वारा गाली - गलौज की भाषा का उपयोग करने, झूठे मामलों में फंसाने, जान से मारने की धमकी देने की शिकायत।

साहब,

यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि मैं 48 वर्षीय अमृतेश सिंह चौहान, स्वर्गीय राम नंदन सिंह का पुत्र, 49, New A.G का निवासी हूं। सहकारी कॉलोनी, कादरू, P.S. अरगोडा, रांची। 10 जुलाई 2018 और उसके बाद लगातार पिछले कुछ दिनों तक उमेश कुमार शर्मा नाम का एक व्यक्ति टावर नंबर 19 के फ्लैट नंबर 19 के निवासी समाचर प्लस चैनल के मालिक के रूप में अपना परिचय दे रहा था। 1924, इंदिरापुरमा ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश मुझे उनके मोबाइल नंबर द्वारा फ़ोन कर रहा है। मेरे मोबाइल नंबर 9457708505 पर भेजें। 9431361039 और 7004780439 और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम द्वारा कह रहा है कि मैं उत्तराखंड सरकार को ध्वस्त करने की साजिश में उनकी मदद करता हूं और इस सभा के लिए और वहां के कुछ राजनेताओं की गुप्त जानकारी प्रदान करता हूं, ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सके और वहां की लोकतांत्रिक सरकार को अस्वीकार किया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड में पार्टी स्तर पर मेरे अच्छे संबंध हैं।

मेरे इनकार करने पर वह मुझे धमकी देता है कि वह मुझे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के झूठे मामलों में फंसा देगा।इसके अलावा उमेश शर्मा ने मेरे साथ गाली - गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि वह मेरा अपहरण कर हत्या करा देगा।उन्होंने मुझ पर उनसे मिलने के लिए दिल्ली या देहरादून आने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और अगर मैं ऐसा करने में विफल रहा तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा।जब मेरी पत्नी ने फोन उठाया तो उसने यहां गाली-गलौज की और धमकी दी कि वह मुझे घर से अपहरण कर लेगा और यह भी कहा कि गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें और धमकी दी कि वह मुझे प्रवर्तन

निदेशालय (ईडी) के झूठे मामले में फंसा देगा।जब मैंने व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाया तो उसने मुझे मैसेज भेजकर धमकी दी।मैं और मेरा परिवार डर के माहौल में रह रहे हैं।हाल ही में समाचार स्रोतों के माध्यम द्वारा मुझे उमेश कुमार की कहानी के बारे में पता चला।मुझे पता चला कि वह मूल रूप से एक पेशेवर ब्लैकमेलर है और चैनल की आड़ में वह पैसे वसूलता है। उमेश कुमार शर्मा के बारे में पूरी जानकारी मिलने और उनके विरुद्ध मामले दर्ज होने के बारे में जानने पश्चात मैं अपनी और अपने परिवार की सम्पति बचाने के लिए, उत्तराआदेश सरकार को बचाने के लिए और सरकार से जुड़े लोगों की साजिश से बचने के लिए उमेश कुमार शर्मा के इस कृत्य के विरुद्ध यह प्रथम सूचना दर्ज करा रहा हूं।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे आवेदन का संज्ञान लें और उमेश कुमार शर्मा और उनके दोस्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करें और उचित कानूनी कार्रवाई करें।
आपका।
Sd/- अमरेश सिंह चौहान
49, नई A.G. सहकारी कॉलोनी
Kadru, P.S. अर्गोडा।
रांची-834002, झारखंड
(जोर दिया गया)
22. 10.11.2018 को, झारखंड की अदालत ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी नं 2018 का 354 क्योंकि प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता प्राथमिकी संख्या में न्यायिक हिरासत में था। देहरादून, उत्तराखंड में 2018 का 100.22.11.2018 को, आरोप पत्र सं. 2018 की 261, दिनांक 22.11.2018 को प्राथमिकी आर. सं. मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भा.दं.सं. की धारा 389,506,509 के से 2018 का 354 और 26.11.2018 को अदालत द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया था।इस मामले में याचिकाकर्ता को 26.11.2018 को जमानत भी दी गई थी।

लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया क्योंकि वह एक अन्य मामले में वांछित था। 2018 का 128, पुलिस स्टेशन राजपुर, देहरादून और इस मामले में उत्पादन प्राथमिकी जेल में 01.11.2018 को ई-मेल द्वारा प्राप्त किया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा कुछ और प्राथमिकियों का उल्लेख किया गया है, उनका संक्षिप्त उल्लेख भी आवश्यक हो सकता है।
प्राथमिकी नं. 2017 का 16
23. 09.02.2007 को ए. वीर कृष्ण शर्मा ने प्राथमिकी नं. 2007 का 16, श्रीमती के विरुद्ध पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून में याचिकाकर्ता सहित मनोरंजन शर्मा और सात अन्य (प्राथमिकी नं 2007 का 16)।इस प्राथमिकी के अनुसार, वीर कृष्ण शर्मा के पिता की जमीन को उनकी सौतेली मां श्रीमती शर्मा ने गलत तरीके से दर्ज किया था। इसे हड़पने के लिए मनोरंजनी शर्मा और याचिकाकर्ता भी इसमें शामिल थे।

24. प्राथमिकी में नं. 2007 का 16, आरोप पत्र प्रारंभ में 15.04.2007 को और पूरक आरोप पत्र 13.03.2009 को दाखिल किया गया था।01.05.2007 को, संज्ञान लिया गया और केस नं। 2007 का 207, राज्य बनाम मनोरंजनी शर्मा और अन्य को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीबीआई, देहरादून की अदालत में स्थापित किया गया था।मामले में प्राथमिकी नं. 2007 का 16, सी482 नं. 2010 का 818 इस न्यायालय में फाइल किया गया था, जिसमें प्रारंभ में 01.09.2010 को स्थगन मंजूर किया गया था अग्रेतर बाद में इसे 03.06.2014 को अग्रेतर नवीनीकृत किया गया था।अंत में सी482 नं. 2010 का 818 26.11.2018 को खारिज कर दिया गया था, इसके विरुद्ध, विशेष अवकाश याचिका (अपराधिक) नं 2018 का 10714 फाइल किया गया था, जिसमें 14.12.2018 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी।

25. इस प्राथमिकी का संदर्भ याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाते हुए किया गया है कि जब वह प्राथमिकी नं. 2018 का 100,30.10.2018 को न्यायालय को गुमराह करके उसकी स्थगन आदेश प्राथमिकी सं. 2017 का 16 और ऐसा करते समय, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2014 को सी-482 सं. 2010 का 818 दबा दिया गया था।

<u>प्राथमिकी नं. 2018 का 128</u>

26. यह प्राथमिकी एक विनय मलिक द्वारा 01.11.2018 को पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून में धारा 147,148,149,386,427,452 और 506 आईपीसी के से दर्ज की गई थी (संक्षेप में "2018 की प्राथमिकी संख्या. 128"), इसके अनुसार, याचिकाकर्ता और अन्य लोगों ने उसकी सम्पति हड़पने की कोशिश की, उस पर हमला किया आदि। इस प्राथमिकी में, 25.05.2019 को आरोप पत्र दायर किया गया था और संज्ञान लिया गया था, जो आपराधिक मामला नं। 2019 का 3588, राज्य बनाम उमेश कुमार और अन्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 3, देहरादून की अदालत में।इस संबंध में, डब्ल्यूपीसीआरएल नं. इस न्यायालय में 2018 का 2148 दायर किया गया था।इस प्राथमिकी का संदर्भ दिया गया है कि जब 26.11.2018 को याचिकाकर्ता को प्राथमिकी नं 2018 के 354 में, उन्हें रिहा नहीं किया गया था क्योंकि देहरादून की अदालत ने प्राथमिकी संख्या में रांची जेल में पेशी जमानत भेजा था। 2018 का 128.बाद में इस उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. सं. 29.11.2012 को 2018 का 2148.

अलग याचिकाएं

27. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2020 का 1182 याचिकाकर्ता दिनांक 07.07.2020 के संचार को रद्द करने का अनुरोध करता है।
28. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2020 का 1187 याचिकाकर्ता तत्काल प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करता है।
29. डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2020 का 1285 याचिकाकर्ता, (याचिकाकर्ता के अनुसार वह एक पत्रकार है और एक समाचार पोर्टल "परवतजन" का संपादक है) दिनांक 07.07.2020 के संचार, दिनांक 30.07.2020 की जांच रिपोर्ट और तत्काल प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा है।
30. इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई है।डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2020 का 1182 और 1187, अमरेश सिंह चौहान प्रतिवादी नं. 3.07.10.2020 को, अदालत ने यह देखते हुए कि अमरेश सिंह चौहान को नोटिस जारी नहीं किए गए थे, प्रतिवादी संख्या को हटाने का निर्देश दिया। पार्टियों की सरणी से 3।
लेकिन, तथ्य यह है कि डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2020 का 1285, प्रतिवादी सं 2, अमरेश सिंह चौहान को 07.09.2020 को डाक के माध्यम द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए।डाक के माध्यम द्वारा भेजा गया लिफाफा द्वारावा निवृत्त नहीं हुआ था, इसलिए, अमृता सिंह चौहान पर पहले द्वारा ही द्वारावा पर्याप्त थी, इसद्वारा पहले कि उनका नाम पार्टियों द्वारा हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

स्थानांतरण याचिका

31. 23.08.2019 को, याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण याचिका (सीआर) दायर की। नं. 2019 का 534-536, प्राथमिकी संख्या के आधार पर मामलों के हस्तांतरण की मांग। 2007 का 16, प्राथमिकी नं. 2018 का 100 और प्राथमिकी नं. 2018 की धारा 128 और 21.10.2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तीनों प्राथमिकियों में अग्रेतर की कार्यवाही पर रोक लगा दी। स्थानांतरण याचिका (सीआर) नं. 2019 का 534-536 16.10.2020 को खारिज कर दिया गया है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से स्पष्ट है।

आधार

32. तत्काल याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर दायर की गई हैः
32.1.दिनांक 07.07.2017 के संचार पर जांच बिना किसी वैधानिक प्रावधान के है।दिनांक 07.07.2020 के संचार पर अपनाई गई प्रक्रिया कानून. 32.2 में खराब है।सोशल मीडिया प्रकाशन का आधार बनाने वाला प्रत्येक दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में था, क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2019 को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आधार था और यह प्रतिवादी की जानकारी के भीतर था जैसा कि आरोप पत्र संख्या में परिलक्षित होता है। 2019 का 32 प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां.तीन एफ. आई. आर. एस. में अतिव्यापी और सामान्य धागा है, अर्थात् एफ. आई. आर. नं. 2018 का 100, प्राथमिकी नं. 2018 की 354 और तत्काल प्राथमिकी और इसलिए, प्राथमिकी नं। 2020 का 265 पंजीकृत नहीं किया जा सकता था.
32.3.प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता है।याचिकाकर्ता ने एक जौमलिस्ट के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और जो कुछ भी उन्होंने प्रकाशित किया, उसे पहले ही अमरेश सिंह चौहान द्वारा सार्वजनिक कर दिया गया था।
32.4.यह एक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है।
33. राज्य ने अपने जवाबी शपथ पत्र में सभी आरोपों का खंडन किया।राज्य के अनुसार, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य के मामले में निर्णय, (2014) 2 एस. सी. सी. 1, उपयुक्त मामलों में एफ. आई. आर. प्राथमिकी करने से पहले प्रारंभिक जांच करने की संभावना को अपने दायरे में लेता है।राज्य ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने कानून के जनादेश का उल्लंघन करते हुए जांच की।मुखबिर ने अपने जवाबी शपथ पत्र में इस मुद्दे पर ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में फैसले का भी उल्लेख किया।
34. राज्य के अनुसार, प्रथमदृष्टया अपराधों का पता चला है।प्राथमिकी नं. 2018 का 100 इससे दूर से भी जुड़ा नहीं है।प्राथमिकी नं. 2007 का 16 और एफ. आई. आर. सं. 2018 का 128 भूमि हड़पने के प्रयास और एफ. आई. आर. सं. 2018 का 100 जबरन वसूली की धमकियों से संबंधित है।याचिका झूठ से भरी हुई है और जबकि याचिकाकर्ता बार-बार दावा करता है कि तत्काल प्राथमिकी की जांच का विषय इस न्यायालय को गुमराह करने के लिए पहले से ही किसी अन्य मामले का विषय है, याचिकाकर्ता द्वारा अपने तर्क का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
35. राज्य ने इस बात से भी इनकार किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण है और अधिकारियों का आचरण मनमाना और मनमानी है।
36. मुखबिर के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया प्रकाशन में किया गया दावा गलत है, जिसका अर्थ है कि उसके कब्जे में बैंक रसीदें/जमा पर्ची जाली हैं और उसके द्वारा गढ़ी गई हैं।जाँच में संज्ञेय अपराध, विशेष रूप से जालसाजी के अपराध का पता चलता है।पहले के

प्राथमिकी आर. एस. के संबंध में, मुखबिर के अनुसार, पहले की प्राथमिकी आर. अलग-अलग विषयों पर हैं और किसी भी तरह से वर्तमान प्राथमिकी आर. से जुड़ी नहीं हैं।

प्रक्रिया

37. इस याचिका में, शुरू में, जब मामले की सुनवाई 06.08.2020 को हुई थी, तो याचिकाकर्ता को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की गई थी।इसके बाद, दिनांक 06.08.2020 के आदेश में तथ्यात्मक गलतियों को सुधारने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था।राज्य ने इसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई।राज्य ने दिनांक 06.08.2020 के आदेश में निहित अंतरिम निर्देशों को हटाने के लिए एक आवेदन भी दायर किया।

38. 14.09.2020 को, राज्य की ओर से, ठहराव अवकाश आवेदन पर तर्क दिए गए हैं।मुख्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि अंतरिम संरक्षण को निम्नलिखित कारणों से हटा दिया जाना चाहिएः

38.1.प्राथमिकी नं. में कोई समानता नहीं है। 2018 का 100, प्राथमिकी नं. 2018 का 354 और एफ. आई. आर. सं. 2020 का 265 (तत्काल प्राथमिकी)।

38.2.दिनांक 06.08.2020 का आदेश याचिकाकर्ता द्वारा गलत दावों द्वारा प्राप्त किया गया हैः

38.2.----------प्राथमिकी नं. 2018 की 354 पहली प्राथमिकी थी। 38.2.2.प्राथमिकी नं. 2018 का 354 एक साजिश रचकर उत्तराखंड सरकार को ध्वस्त करने के बहाने जबरन वसूली के संबंध में था।

38.3.याचिकाकर्ता ने सुधार आवेदन में अग्रेतर गलत दावे किए अर्थात्ः-

38.3.----------सुनवाई ऑनलाइन होने और सभी मामलों के लिए प्रदान किए गए सामान्य लिंक के कारण, सुनवाई के दौरान लगातार गड़बड़ी होती रही।

38.3.2.प्राथमिकी नं. 2018 की 100 स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित पहली प्राथमिकी थी।प्राथमिकी नं. 2010 की 354 पहली एफ़. आई. आर. नहीं थी, बल्कि अमरेश सिंह चौहान और टी. एस. आर. सी. एम. के बीच अदान-प्रदान किए गए आरोपों और व्हाट्सऐप संदेशों पर दूसरी एफ़. आई. आर. थी।

38.3.-कि दोनों मामलों में, आरोप आगे बढ़े और जांच का दायरा संदेश और बैंक खाते थे जो वर्तमान प्राथमिकी का आधार बने।

38.4.अंतरिम आदेश से पहले याचिकाकर्ता का आचरण भी उसे किसी भी सुरक्षा से वंचित करता है क्योंकि उसने दिनांक 07.07.2020 के संचार में जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और अंतरिम आदेश के बाद, जब आईओ ने उससे जांच में सहयोग करने का अनुरोध किया, तो उसने सहयोग नहीं किया, इसके बजाय उसने पुलिस को धमकी दी।विभिन्न दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया है।

38.5.याचिकाकर्ता द्वारा अपने सोशल मीडिया प्रकाशन में मुखबिर के खाते में धन जमा करने और मुखबिर की पत्नी के टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी के साथ संबंध के संबंध में किया गया दावा गलत है।याचिकाकर्ता निर्दोष नहीं है।

39. 14.09.2020 को ही अदालत के पास मामले की सुनवाई के लिए सभी सामग्री थी।बाद की तिथि को, राज्य की ओर से, यह तर्क दिया गया कि स्थगन अवकाश आवेदन पर मामले की सुनवाई की जा सकती है और यदि अदालत को लगता है कि अंतरिम आदेश गलत दावों पर प्राप्त किया गया था तो मुख्य याचिका को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है।लेकिन, चूंकि सभी दलीलों का आदान-प्रदान हो चुका था, इसलिए अदालत मुख्य याचिका पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ी।

40. अंतरिम आदेश की छुट्टी के लिए आवेदन पर अलग आदेश की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला अपने अंतिम निपटान की ओर बढ़ रहा है।जहाँ तक सुधार आवेदन का संबंध है, तथ्य यह है कि याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता एक पत्रकार है और पहली प्राथमिकी प्राथमिकी नं। 2018 का 100 वां.दिनांक 06.08.2020 के आदेश को इन कथनों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।न्यायालय यह आवश्यक नहीं समझता है कि सुधार आवेदन के किसी भी अलग निपटान की आवश्यकता है।सुधार आवेदन पर निर्णय लेने से पहले यहाँ की गई टिप्पणियाँ।

41. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

<u>दलीलें</u>

<u>याचिकाकर्ताओं के स्वयं पर</u>

42. याचिकाकर्ता के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया सोशल मीडिया प्रकाशन कुछ नया नहीं है।वास्तव में, अमरेश सिंह चौहान ने एक पत्रकार राजेश शर्मा को इसका खुलासा किया और उन्होंने याचिकाकर्ता को इसका खुलासा किया। व्हाट्सएप संदेशों के लेखक अमरेश सिंह चौहान और टीएसआरसीएम हैं। व्हाट्सएप संदेशों से बैंक खातों का पता चला, जिसमें अमरेश सिंह चौहान द्वारा पैसे जमा किए जाने थे।बैंक रसीदें अमरेश सिंह चौहान द्वारा प्रदान की गई थीं।वे याचिकाकर्ता द्वारा लिखित नहीं थे, लेकिन यह तर्क दिया जाता है किः

42.1.राज्य ने व्हाट्सएप संदेशों के लेखकों से कुछ नहीं पूछा है।यह तर्क दिया जाता है कि सूचना देने वाले के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया था और भले ही सूचना देने वाले की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की बहन न हो, यह कोई मामला नहीं बनाता है।

याचिकाकर्ता एक पत्रकार है।उन्होंने वह जानकारी सार्वजनिक की, जो उन्हें दी गई थी।इसके लिए उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।उन्होंने कोई जाली दस्तावेज नहीं बनाया।

यदि एफ. आई. आर. में बताई गई सभी बातें सत्य मानी जाती हैं, तब भी याचिकाकर्ता के बनाम कोई अपराध नहीं बनता है और यह हरियाणा राज्य और अन्य प्राथमिकी भजन लाल और अन्य, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए मामला बनाता है।

42.2.यह कथन कि राशि प्रथम सूचना देने वाले के खाते में जमा की गई थी और प्रथम सूचना देने वाले की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की वास्तविक बहन है, यदि गलत है, तो मानहानि का अधिकतम मामला हो सकता है, जिसके लिए मात्र एक शिकायत प्राथमिकी की जा सकती है लेकिन FIR. 42.3 प्राथमिकी नहीं की जा सकती है।दिनांक 07.07.2020 के संचार पर अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं है।लीम्ड वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क होगा कि अगर मुखबिर के अनुसार, दिनांक 07.07.2020 का संचार किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं कर रहा था, तो ऐसे मामले में प्रारंभिक जांच करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।यदि दिनांक 07.07.2020 के संचार में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है, तो ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित सिद्धांत ऐसी जांच की अनुमति नहीं देते हैं जैसा कि तत्काल मामले में किया गया है।यदि दिनांक 07.07.2020 का संप्रेषण एक प्राथमिकी नहीं है, जैसा कि राज्य द्वारा कहा गया है, तो जांच के पश्चात भी, तत्काल मामले में प्राथमिकी को किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दिनांक 31.07.2020 की प्राथमिकी में, मात्र जोड़ जांच रिपोर्ट है।यह तर्क दिया जाता है कि दिनांक 31.07.2020 की प्राथमिकी, वास्तव में, संहिता की खंड 162 के से बयान है।यह कोई प्राथमिकी नहीं है। 42.4.याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक किए गए संदेशों को अमरेश सिंह चौहान और टी. एस. आर. सी. एम. द्वारा लिखा गया था। याचिकाकर्ता को 10.08.2020 को नोटिस दिया गया था।जिस पर उन्होंने 12.08.2020 को तुरंत जवाब दिया।याचिकाकर्ता ने पूछताछ की पेशकश की, वह पूरे समय आईओ के साथ सहयोग कर रहा था। यह तर्क दिया जाता है कि वास्तव में, अमृतेश सिंह चौहान द्वारा भेजे गए संदेशों से पता चलता है कि वह परेशान था क्योंकि उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था।

इसलिए, उन्होंने टी. एस. आर. सी. एम. के साथ आदान-प्रदान किए गए अपने व्हाट्सएप संदेशों और टी. एस. आर. सी. एम. के मीडिया वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ रिकॉर्ड की गई अपनी बातचीत का खुलासा किया। लीम्ड सीनियर काउंसल ने उन दस्तावेजों और बातचीत का भी उल्लेख किया।याचिकाकर्ता के पास सोशल मीडिया प्रकाशन करने का कोई कारण नहीं था।

42.5।अभियोजन शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण है।यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता एक पत्रकार है।जिस तरह से किया जा रहा है, उसे राज्य द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है।व्हाट्सएप संदेशों के लेखकों से पूछताछ नहीं की जा रही है; कोई भी व्हाट्सएप संदेशों की प्रामाणिकता से इनकार नहीं करता है।राज्य का कहना है कि यह अप्रासंगिक है और यह स्वयं दुर्भावनापूर्ण है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दिनांक 07.07.2020 के संचार का भी उल्लेख किया जिसमें पहले मुखबिर ने स्वीकार किया है कि उसके बैंक खाते के नंबर का खुलासा किया गया था और इसके आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि यह एक स्वीकारोक्ति है कि व्हाट्सएप संदेशों में उसके खाते के नंबर का खुलासा किया गया था, जो तर्क दिया जाता है, टीएसआरसीएम द्वारा अमरेश सिंह चौहान को दिया गया था। 42.6.याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पूरी प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण है।दिनांक 07.07.2020 के संचार पर सूचना देने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी से जांच चाहता है।पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) ने 20.07.2020 तक रिपोर्ट मांगी है।यह वह 19.07.2020 को करता है।जांच रिपोर्ट 30.07.2020 को तैयार की गई थी।सूचना देने वाले की आरटीआई का जवाब 31.07.2020 को दिया गया था और उसी तिथि को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी रात राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क होगा कि यह सब उस जल्दबाजी को दर्शाता है जिसके साथ राज्य आगे बढ़ा है।यह तर्क दिया जाता है कि मुखबिर एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछताछ कैसे कर सकता है और इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है?इस बारे में भी तर्क दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री को दिनांक 07.07.2020 का पत्र क्यों भेजा गया था।यह तर्क दिया जाता है कि यह एक त्रासदी है कि जो व्यक्ति गलत कामों को उजागर करना चाहता है, उसे राज्य द्वारा सताया जा रहा है और साथ ही यह एक कॉमेडी है कि व्हाट्सएप संदेशों के लेखकों की रक्षा की जा रही है।

42.7.लीम्ड वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क होगा कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सोशल मीडिया प्रकाशन की सामग्री पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थी।'तीसरी आंख का तहलका' ने इसे वर्ष 2019 में प्रकाशित किया था, जिस पर मुखबिर ने आपत्ति जताई थी, जिसमें बाद में मुखबिर द्वारा एक साक्षात्कार भी दिया गया था।डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113, अपने जवाबी शपथ पत्र में, याचिकाकर्ता ने उन सभी चीजों को वर्ष 2019 में बताया है, जो सोशल मीडिया प्रकाशन का हिस्सा है।याचिकाकर्ता द्वारा 28.01.2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया प्रकाशन की सभी सामग्री का खुलासा किया था।इसके बाद, इस मामला की विधानसभा में बहस हुई, जब विधानसभा में यह बताया गया कि मामला विचाराधीन है।यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल मामला एफ. आई. आर. नं. 2018 का 100, लेकिन इस पर नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।अपने तर्क के समर्थन में, वरिष्ठ अधिवक्ता ने अमितभाई ए नीलचंद्र शाह बनाम मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांतों पर भरोसा किया।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, (2013) 6 एस. सी. सी. 348.

राज्य की ओर से

43. राज्य के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता पत्रकार भी नहीं है।लेकिन वह पत्रकार बनने का नाटक कर रहा है।प्राथमिकी नं. का संदर्भ दिया गया है। 2018 का 100, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध विशेष रूप से निम्नलिखित पंक्तियों के विरुद्ध पहले मुखबिर द्वारा दायर किया गया थाः

43.1..... स्टिंग ऑपरेशन में, ये लोग जासूसी कैमरे के माध्यम द्वारा मंत्रियों और अधिकारियों को फंसाते हैं।लेकिन उमेश शर्मा इन खबरों को एक चैनल पर प्रसारित नहीं करता है और एक पूर्व नियोजित साजिश के से, वह उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे कमाता है।इसी इरादे से उन्होंने मधु और राहुल भाटिया को देहरादून, उत्तराखंड भेजा है।इस दौरान उमेश लगातार मुझ पर मंत्रियों, नौकरशाहों और अधिकारियों को फंसाने के लिए फोन या व्हाट्सएप पर दबाव डालता रहा।

जिनका क्रमवार विवरण इस प्रकार हैः-..... 43.2..अगर मात्र एक बार हम मुख्य सचिव को फंसा सकते हैं,● ● तब यह हमारे लिए फायदेमंद होगा और फिर हमारा कोई भी काम बंद नहीं होगा और हम जो भी चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा क्योंकि राज्य में राजनीतिक अक्षमता (बीमारी) होगी।

43.3..... मेरा उपयोग करके, वे राज्य में अशांति और अस्थिरता पैदा करने की योजना बना रहे थे।.....

43.4.....उन्होंने कहा कि पैसे की व्यवस्था की गई है, जो सरकार को अस्थिर करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत के रूप में दी जाएगी।--

43.5..... उमेश कुमार ने गहरी साजिश रची है जिसमें अनुज कुमार, प्रवीण साहनी, सौरभ साहनी, भाटिया, अन्य कर्मचारी, स्थानीय नेता और व्यवसायी शामिल हैं, जो राज्य में अशांति और हिंसा पैदा करना चाहते हैं।

43.6..... उमेश कुमार अपने सहयोगियों के साथ मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी भी अप्रिय कृत्य का कारण बन सकता है और मुझे पूरे जीवन के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है।

44. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्राथमिकी नं 2018 की 354, विशेष रूप से, निम्नलिखित पंक्तियों पर जोर दिया विद्वान हैः

44.1.....और व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से कह रहा है कि उत्तराखंड की सरकार को गिराने की साजिश में उसकी मदद करने के लिए और इस सभा के लिए और वहां के कुछ राजनेताओं की गुप्त जानकारी प्रदान करने के लिए .....

44.2... मुझे पता चला कि वह मूल रूप से एक पेशेवर ब्लैकमेलर है और चैनल की आड़ में, वह पैसे लूटता है.....।

45. राज्य की ओर से यह भी तर्क दिया जाता है कि तत्काल मामले में प्राथमिकी दो आरोपों के संबंध में संकीर्ण और विशिष्ट क्षेत्र के भीतर है अर्थात्ः
45.1.कि पैसा मुखबिर के खातों में जमा किया गया था, जो टीएसआरसीएम 45.2 को रिश्वत के रूप में था।कि मुखबिर की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की बहन है।
46. राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी अपने तर्क में निम्नलिखित बिंदु उठाएः- 46.1। याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि ये आरोप सही नहीं हैं और वह खुद को निर्दोष होने का दावा करता है, लेकिन मात्र इन बयानों के आधार पर संहिता की खंड 482 से कार्यवाही में जांच को रोका नहीं जा सकता है।जाँच जारी रखनी चाहिए।याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथ पत्र के पैरा 3 उपखंड (घ) (ङ) और (छ) का भी यह तर्क देने के लिए संदर्भ दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि यह दिखाने के लिए एक भी दस्तावेज नहीं है कि सूचना देने वाले या उसकी पत्नी के खातों में कोई राशि जमा की गई थी. 46.2.याचिकाकर्ताओं की ओर से भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों को सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।वे अप्रासंगिक हैं; व्हाट्सएप संदेश दो लोगों के बीच थे, जो अदालत के समक्ष नहीं हैं; व्हाट्सएप संदेशों की वास्तविकता, विश्वसनीयता या सच्चाई पर अभी भी सवाल उठाया जाता है; यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है; उनकी प्रामाणिकता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं है।वास्तव में, कुछ व्हाट्सएप संदेशों को संदर्भित किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि जाहिरा तौर पर वे संदिग्ध प्रतीत होते हैं। 46.3.प्राथमिकी नं. 100/2018 और प्राथमिकी नं. 2018 के 354 अलग हैं।वे सूचना देने वाले से संबंधित नहीं हैं।मुखबिर का पहले शपथ पत्र से कोई लेना-देना नहीं था। वे तत्काल दर्ज की गई प्राथमिकी से दूर से भी जुड़े नहीं हैं। यह तर्क दिया जाता है कि डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113, समानता स्वीकार नहीं की जा सकती है।

यहां तक कि डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113, राज्य की ओर से, याचिकाकर्ता के प्रत्युत्तर शपथ पत्र में एक खंडन हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रत्युत्तर शपथ पत्र की सामग्री प्राथमिकी नं 2018 का 100 वां.आरोप एक जैसे नहीं हैं।
46.4.संहिता की खंड 482 के क्षेत्राधिकार, दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाता है, जब स्थिति आवश्यक होती है।जिन मामलों में जाँच की आवश्यकता होती है, उनमें जाँच को विफल करने के लिए क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं किया जाता है।तत्काल मामले में, यह तर्क दिया जाता है कि प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध बनाए जाते हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए भा.दं.सं. की खंड 415 को पढ़ा कि वास्तव में, सोशल मीडिया प्रकाशन द्वारा याचिकाकर्ता ने आम जनता को टिप्पणियां करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सूचना देने वाले के शरीर, मन, प्रतिष्ठा आदि को नुकसान पहुंचा। मेन्स

रिया है।सोशल मीडिया प्रकाशन में, याचिकाकर्ता ने कुछ जमा रसीदें दिखाईं और माफ कर दीं और बताया कि राशि मुखबिर के खाते में जमा की गई थी और दावा किया कि उसके पास बैंक रसीदें थीं, जिसका अर्थ है कि उसने रसीदें जाली बनाई थीं, इसलिए जांच जारी होनी चाहिए।
46.5.ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय, भ्रष्टाचार के मामलों में प्रारंभिक जांच करना अनुमेय और वास्तव में अनिवार्य बनाता है।पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. बनाम तपन कुमार सिंह, (2003) 6 एस. सी. सी. 175 के मामले में निर्णय का भी यह तर्क देने के लिए संदर्भ दिया गया है कि वास्तव में, यह प्रारंभिक जांच की भी अनुमति देता है।
46.6.भले ही यह माना जाता है कि प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर यह प्रक्रिया में तकनीकी है।इसका कार्यवाही में तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि याचिकाकर्ता के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो।

यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया है और पूर्वाग्रह के बिना, भले ही कोई अनियमितता हो, तो न तो प्राथमिकी और न ही जांच को रद्द किया जा सकता है. 46.7.अभियोजन पक्ष दुर्भावनापूर्ण नहीं है।याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध एक मामला बनाया गया है, जिसकी जांच के दौरान गहरी जांच की आवश्यकता है।दुर्भावनापूर्ण मामलों में, यह तर्क दिया जाता है कि जिस व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण इरादे को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे कार्यवाही में एक पक्ष होना चाहिए।संहिता की धारा 482 से कार्यवाही में, न्यायालय उस सामग्री के बाद नहीं जा सकता है, जो पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा है या जो आईओ को उपलब्ध अभिलेख में थी। इस बिंदु पर, खंडवानिवृत्त वकील ने बिहार राज्य और एक अन्य बनाम P.P. के मामले में निर्णय का उल्लेख किया। शर्मा और एक अन्य, 1992 सप।1 एस. सी. सी. 222, विशेष रूप से इसका पैरा 22।यह नीचे की तरह है;
"22. शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का प्रश्न तमात्र महत्व रखता है जब आपराधिक अभियोजन बाहरी विचारों और अनधिकृत उद्देश्य के लिए शुरू किया जाता है।इस मामले में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि जिस तिथि को R.K. सिंह द्वारा FIR प्राथमिकी की गई थी, वह पूर्वाग्रह से सक्रिय था या दुर्भावनापूर्ण कार्य करने का कोई कारण था।प्रतिवादी के विरुद्ध मामला दर्ज करने का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिकी में निहित आरोपों की जांच करना और अदालत के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री होने की स्थिति में जांच करना था।यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मामला दर्ज करने का प्रमुख उद्देश्य प्रतिवादी का चरित्र हनन या उन्हें परेशान करना और अपमानित करना था।बिहार राज्य बनाम J.A.C. सल्धाना 1 ने अभिनिर्धारित किया है कि जब सूचना थाने में दर्ज की जाती है और कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो सूचना देने वाले की दुर्भावना गौण महत्व की होगी।यह जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री है जो अभियुक्त व्यक्ति के भाग्य का फैसला करती है।हरियाणा

राज्य बनाम चौ. में यह न्यायालय। भजन लाल 2 ने राज्य सरकार को सीएच के विरुद्ध नए सिरे से जांच करने की अनुमति दी। भजन लाल इस तथ्य के बावजूद कि धर्म पाल के कहने पर अभियोजन दर्ज किया गया था जो भजन लाल के प्रति शत्रुतापूर्ण था "

47. यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल मामले में, सूचना देने वाले द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है क्योंकि यह वही है जिसे याचिकाकर्ता की कार्रवाई से नुकसान पहुंचा है।सोशल मीडिया प्रकाशन पर याचिकाकर्ता ने झूठे बयान दिए, जिसे उन्होंने अब स्वीकार कर लिया है।

मुखबिर की ओर से

48. सूचना देने वाले की ओर से, स्वतंत्र वकील राज्य की ओर से दिए गए तर्कों को अपनाएंगे। इसके अलावा, वैध वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्रकाशन में कुछ रसीदें दिखाई और दावा किया कि सूचना देने वाले के खाते में पैसे जमा किए गए थे।इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता ने ऐसी रसीदें जाली और गढ़ी थीं।

49. याचिकाकर्ता और राज्य की ओर से विस्तृत लिखित प्रस्तुतियाँ भी प्रस्तुत की गई हैं जिनमें विभिन्न अन्य मामले कानूनों का उल्लेख किया गया है, जो जब आवश्यक होगा, चर्चा के दौरान जगह पाएगा।

चर्चा

50. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ पठित संहिता की खंड 482 से याचिकाएं हैं। क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है, लेकिन बहुत कुछ तय किए गए कानूनी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।अन्य कारकों के अलावा, कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने की मांग की जाती है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है और अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है।

51. भजनलाल (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 से दायरे और पैरा एन. ओ. एस. में चर्चा की। 102 और 103 को इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

"102.अध्याय 14 से संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 से असाधारण शक्ति के प्रयोग खंड संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायाधीशालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 से अंतर्निहित शक्तियों, जिन्हें हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के रूप में निम्नलिखित

श्रेणियों के मामले देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी सटीक, स्पष्ट रूप खंड परिभाषित और पर्याप्त रूप खंड चैनलाइज़ किए गए और कठोर दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।
(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की खंड 156 (1) के से पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।
(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के विरुद्ध मामला बनाते हैं।
(4) जहां, प्राथमिकी आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन मात्र एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की खंड 155 (2) के से मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।
(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।
(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था को और कार्यवाही जारी रखने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और/या जहां संहिता या कल्पित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।
(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त से बदला लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने की दृष्टि से शुरू की जाती है।
103. हम इस बात पर भी ध्यान दें बरतते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम और ध्यान दें से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि न्यायालय प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या

वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू करने में न्यायोचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।
(जोर दिया गया)
52. बाद के मामलों में इन सिद्धांतों का पालन किया गया है।यह भी तय कानून है कि इस स्तर पर, वह सामग्री जो जांच का हिस्सा नहीं है, आम तौर पर याचिकाकर्ता की संलिप्तता की जांच करने के लिए नहीं मानी जाती है।प्राथमिकी आर. की सामग्री और जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री प्रासंगिक है।

बेशक, जब दुर्भावना पश्चात बात आती है, तो शायद कुछ अन्य सामग्रियों पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि आखिरकार दुर्भावना कोई कार्रवाई नहीं है, यह एक कार्रवाई के पीछे का इरादा है।यह भी बहुत तय है कि यदि प्राथमिकी में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और एक वैध अभियोजन को इसकी सीमा पर विफल नहीं किया जाना चाहिए।लेकिन, यह भी उतना ही सच है कि यदि प्रथमदृष्टया भी मामला नहीं बनता है, तो किसी व्यक्ति को विचारण की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें बहुत समय और अन्य संसाधन लगते हैं।
53. याचिकाकर्ता के अनुसार वह एक पत्रकार है।राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता एक जौमलिस्ट नहीं था, बल्कि वह एक जौमलिस्ट होने का नाटक कर रहा था। प्राथमिकी नं. 2018 का 100 याचिकाकर्ता के विरुद्ध पहले मुखबिर द्वारा दर्ज किया गया था। उस एफ़. आई. आर. में पहले मुखबिर ने अपना परिचय एक टीवी चैनल की जाँच के संपादक के रूप में दिया, जिसमें याचिकाकर्ता मुख्य संपादक/सी. ई. ओ. था। न्यायालय इस मामले में सामग्री की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या 2018 की प्राथमिकी आर. 100 या 2018 की प्राथमिकी आर. संख्या 354 में लगाए गए आरोप सही थे या नहीं।इसलिए याचिकाकर्ता के पेशे के संबंध में दिए गए तर्क राज्य की मदद नहीं करते हैं।

<u>समानता का सिद्धान्त</u>

54. संहिता में प्राथमिकी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।संज्ञेय मामलों में जानकारी, जब एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी जाती है, तो इसे लिखित कर दिया जाता है। संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एक पूरी प्रक्रिया दी गई है कि इस तरह की जानकारी को कैखंड संसाधित किया जाता है।संहिता की खंड 154 के से दी गई यह रिपोर्ट प्राथमिकी है। T.T. के मामले में। एंटनी बनाम केरल राज्य और अन्य, (2001) 6 एस. सी. सी. 181, अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने के प्रभारी

द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई स्टेशन हाउस डायरी में पहले दर्ज की गई जानकारी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट है, बशर्ते कि यह अस्पष्ट या गुप्त न हो।यदि प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात अपराध के संबंध में कुछ और जानकारी प्राप्त हो जाती है तो क्या स्थिति होगी?अगर कुछ और जानकारी प्राप्त होती है, जो एफआईआर की सामग्री को जोड़ सकती है तो क्या होगा?

क्या पुलिस को एक और प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए या पहले से दर्ज प्राथमिकी में मामले की जांच करनी चाहिए?"T.T. के मामले में एंटनी (ऊपर), माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "यह बहुत संभव है और ऐसा कभी-कभी नहीं होता है कि एक या एक खंड अधिक संज्ञेय अपराध खंड संबंधित एक ही घटना के संबंध में एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी को एक खंड अधिक जानकारी दी जाती है, ऐखंड मामले में, उखंड स्टेशन हाउस डायरी में उनमें खंड प्रत्येक को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यह संहिता की धारा 154 में निहित है।इसे अग्रेतर पैरा एन. ओ. एस. में देखा गया। निर्णय के 19 और 20, कि;
19. सी. आर. पी. सी. की योजना यह है कि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के होने का पता चलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रविष्टि के आधार पर सी. आर. पी. सी. की खंड 156 या 157 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करनी होगी। जाँच पूरी होने पर और एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर, उखंड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 या 170 के से एक मत बनानी होगी, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (2) के से मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। यद्यपि ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात भी, यदि वह अग्रेतर की जानकारी या सामग्री के कब्जे में आता है, तो उखंड एक नई प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है; उखंड अग्रेतर की जांच करने का अधिकार है, सामान्य रूप खंड अदालत की अनुमति के साथ, और जहां अग्रेतर की जांच के दौरान वह अग्रेतर के साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी एकत्र करता है, वह एक या अधिक अग्रेतर की रिपोर्ट के साथ इखंड अग्रेतर बढ़ाने के लिए बाध्य है; यह धारा 173 सीआरपीसी की उप-धारा (8) का आयात है।
20. उपर्युक्त चर्चा खंड यह निष्कर्ष निकलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154,155,156,157,162,169,170 और 173 के उपबंधों की स्कीम से संज्ञेय अपराध के किए जाने के संबंध में मात्र आरंभिक या प्रथम सूचना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की अपेक्षाओं को पूरा करती है। इस प्रकार कोई दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती है और परिणामस्वरूप एक ही संज्ञेय अपराध या एक ही घटना या एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म देने वाली घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है।एक संज्ञेय अपराध या एक संज्ञेय अपराध या अपराध को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और स्टेशन हाउस डायरी में प्राथमिकी दर्ज करने पर, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न मात्र प्राथमिकी में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होती है, बल्कि एक ही

लेनदेन या एक ही घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होती है और खंड 173 सीआरपीसी में प्रदान की गई एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है।
(जोर दिया गया)
55. कारी चौधरी वी के मामले में Mst. सीता देवी और अन्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 714, न्यायालय ने कहा कि "निश्चित रूप से कानूनी स्थिति यह है कि एक ही मामले के संबंध में एक ही अभियुक्त के विरुद्ध दो एफ. आई. आर. नहीं हो सकती हैं।"

बाबूभाई के मामले में। गुजरात राज्य और अन्य (2010) 12 एस. सी. सी. 254, न्यायालय ने दूसरी एफ. आई. आर. प्राथमिकी नहीं करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया। यह समानता की कसौटी है, इसे पैरा नं.निर्णय का 21, जो इस प्रकार हैः
"21. ऐसे मामले में अदालत को दोनों प्राथमिकियों को जन्म देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होती है और यह पता लगाने के लिए समानता की कसौटी लागू की जानी चाहिए कि क्या दोनों प्राथमिकियां एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही लेन-देन के दो या अधिक भाग हैं।यदि उत्तर सकारात्मक है, तो दूसरी प्राथमिकी रद्द की जा सकती है।यद्यपि यदि इसके विपरीत साबित होता है, जहां दूसरी प्राथमिकी में संस्करण अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, तो दूसरी प्राथमिकी की अनुमति है।यदि एक ही घटना के संबंध में पहली प्राथमिकी में आरोपी एक अलग संस्करण या जवाबी दावे के साथ आगे आता है, तो दोनों प्राथमिकी की जांच की जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)
56. निर्मल सिंह काहलों के मामले में। पंजाब राज्य और अन्य, (2009) 1 एस. सी. सी. 441, न्यायालय ने कहा कि "दूसरी प्राथमिकी आर., हमारी मत में, न मात्र इसलिए बनाए रखने योग्य होगी क्योंकि विभिन्न संस्करण थे, बल्कि जब तथ्यात्मक आधार पर नई खोज की जाती है।बाद के चरण में पुलिस अधिकारियों द्वारा खोज की जा सकती है।एक बड़ी साजिश के बारे में खोज एक अन्य कार्यवाही में भी सामने आ सकती है, उदाहरण के लिए, इस प्रकृति के मामले में।
(जोर दिया गया)
57. सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 567 के मामले में यह पाया गया कि यदि एक और एक ही घटना से संबंधित दो एफ. आई. आर. अलग से दर्ज की जाती हैं, तो ऐसे मामलों में उन्हें जोड़ा जा सकता है और एक आरोप-पत्र दायर किया जा सकता है।चिरशिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2010) 14 एस. सी. सी. 444 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अन्य एफ. आई. आर. जो प्रथम प्राथमिकी की गई घटना के परिणामस्वरूप प्राथमिकी की गई है, अनुज्ञेय नहीं है।इस तरह के मामलों की जांच पहली प्राथमिकी में ही की जानी चाहिए।

सुरेन्द्र कौशिक और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2013) 5 एस. सी. सी. 148 के मामले में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "संहिता से मामला दर्ज किए जाने के पश्चात् उसी शिकायतकर्ता और अन्य लोगों द्वारा उसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई और शिकायत करना निषिद्ध है, क्योंकि इस संबंध में जाँच पहले ही प्रारंभ हो चुकी होगी और अग्रेतर की शिकायत दर्ज करने की अनुमति देना मूल शिकायत में उल्लिखित तथ्यों में सुधार के बराबर होगा।"
58. अमितभाई (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून पर चर्चा की और समानता और परिणामी परीक्षण के परीक्षण को मंजूरी दी।न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः
"58.3।ऐसी रिपोर्ट दाखिल करने के पश्चात भी, यदि वह अग्रेतर की जानकारी या सामग्री के कब्जे में आता है, तो एक नई प्राथमिकी दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उखंड अदालत की अनुमति के साथ सामान्य रूप खंड अग्रेतर की जांच करने का अधिकार है और जहां अग्रेतर की जांच के दौरान, वह अग्रेतर साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी एकत्र करता है, वह एक या अधिक अग्रेतर की रिपोर्ट के साथ इखंड अग्रेतर बढ़ाने के लिए बाध्य है जो संहिता की धारा 173 की उप-धारा (8) खंड स्पष्ट है।संहिता की खंड 154,155,156,157,162,169,170 और 173 के उपबंधों की स्कीम के अधीन, संज्ञेय असोध के किए जाने के संबंध में मात्र आरंभिक या प्रथम सूचना संहिता की खंड 154 की अपेक्षाओं को पूरा करती है।इस प्रकार, कोई दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप, एक ही संज्ञेय अपराध या एक या अधिक संज्ञेय अपराध को जन्म देने वाली एक ही घटना या घटना के संबंध में प्रत्येक बाद की जानकारी प्राप्त होने पर कोई नई जांच नहीं हो सकती है।
58.4.इसके अग्रेतर संज्ञेय अपराध या संज्ञेय अपराध या अपराध को जन्म देने वाली घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर और स्टेशन हाउस डायरी में प्राथमिकी दर्ज करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को न मात्र प्राथमिकी में दर्ज संज्ञेय अपराध की जांच करनी होगी, बल्कि उसी लेनदेन या उसी घटना के दौरान किए गए अन्य संबंधित अपराधों की भी जांच करनी होगी और संहिता की खंड 173 में दिए गए एक या अधिक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। संहिता की खंड 173 की उपखंड (8) पुलिस को अग्रेतर की जांच करने, अग्रेतर साक्ष्य (मौखिक और दस्तावेजी दोनों) प्राप्त करने और मजिस्ट्रेट को अग्रेतर की रिपोर्ट (रिपोर्ट) भेजने का अधिकार देती है।उसी लेन-देन के दौरान कथित रूप खंड किए गए एक ही या संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर की गई दूसरी या लगातार प्राथमिकियों के आधार पर नए सिरे खंड जांच का मामला और जिसके संबंध में पहली प्राथमिकी के अनुसार या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के से अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, संहिता की धारा 482 से या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के शक्ति का प्रयोग करके उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए उत्तरदायी है।

58.6.मामले में, जैसा कि पहले के पैराग्राफ में समझाया गया है, हमारी मत में, दूसरी प्राथमिकी 25-11-2005/26-11-2005 को हुई घटना का परिणाम थी।

हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि इस अदालत ने सीबीआई में विश्वास जताते हुए उनकी इस दलील को स्वीकार कर लिया है कि तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ उसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें सोहराबुद्दीन और कौसरबी मारे गए थे।
(जोर दिया गया)
59. एक और प्रश्न उठ सकता है कि अगर पहली प्राथमिकी में पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उसके बाद कुछ नई खोज की गई है तो क्या होगा?ऐसी स्थिति में, पुलिस अधिकारी निस्संदेह, संहिता की खंड 173 (8) के अनुसार अग्रेतर की जांच के लिए अग्रेतर बढ़ सकता है। विनूभाई हरिभाई मालवीय और अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य (2019) एससीसी ऑनलाइन 1346 के मामले में, माननीय सर्वोच्च विचारण ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया कि न मात्र आईओ, बल्कि विचारण भी, संज्ञान लेने के पश्चात सुनवाई शुरू होने तक अग्रेतर की जाँच का आदेश दे सकता है।
60. मुख्य रूप से प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां.तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, यदि एफ. आई. आर. नं. 2018 की 100 और तत्काल प्राथमिकी एक ही संज्ञानात्मक अपराध के संबंध में है या उन अपराधों के संबंध में है जो एक ही लेनदेन में किए गए थे, निश्चित रूप से प्राथमिकी नं 2020 के 265 को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था।लेकिन, क्या ऐसा है?बाबू भाई (उपर्युक्त) के मामले में समानता की परीक्षा दी गई है; बाबू भाई (उपर्युक्त) के मामले में जो देखा गया वह यह है कि समानता की परीक्षा यह पता लगाने के लिए लागू की जानी चाहिए कि क्या दोनों प्राथमिकियां एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में जो एक ही लेनदेन के दो या अधिक भाग हैं।मुनियप्पन के मामले (ऊपर) में परिणामी परीक्षण लागू किया जाता है कि यदि दूसरी प्राथमिकी की सामग्री पहली प्राथमिकी की सामग्री का परिणाम है, तो ऐसे मामलों में, दूसरी प्राथमिकी अलग से दर्ज नहीं की जानी चाहिए और पहली प्राथमिकी पर जांच आगे बढ़ सकती है। वास्तव में, अमित भाई (उपर्युक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि बाद की प्राथमिकी की सामग्री घटनाओं की उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो पहली प्राथमिकी का आधार बनती है, तो ऐसे मामले में दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए।
61. प्राथमिकी नं. 2018 का 100 प्रथम मुखबिर द्वारा दर्ज किया गया था अग्रेतर मोटे तौर पर अभिकथन थे कि उन्हें "ब्लैकमेलिंग", "राजनीतिक अस्थिरता" "राज्य में अशांति अग्रेतर अस्थिरता पैदा करने" "सरकार को अस्थिर करने के लिए रिश्वत", "राज्य में अशांति अग्रेतर हिंसा पैदा करने" आदि के उद्देश्यों के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने की धमकी दी गई थी। यह न्यायालय बाद के चरण में इस प्राथमिकी पर थोड़ी अग्रेतर चर्चा करेगा।

कहने के लिए पर्याप्त है, प्राथमिकी नं 2018 का 100 राज्य सरकार को अस्थिर करने और राज्य में अशांति और हिंसा पैदा करने की साजिश थी।पूर्व नियोजित षड्यंत्र शब्द का उपयोग प्राथमिकी संख्या में भी किया गया है। 2018 का 100 वां.

62. प्राथमिकी नं. अमरेश सिंह चौहान द्वारा 2018 का 354 दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्हें उत्तराखंड सरकार को ध्वस्त करने की साजिश में याचिकाकर्ता की मदद करने की धमकी दी जा रही थी।प्राथमिकी में नं. अपराध की घटना के कॉलम में 2018 की धारा 354 में कहा गया है कि "साजिश रचकर उत्तराखंड सरकार को ध्वस्त करने के बहाने जबरन वसूली" वास्तव में, प्राथमिकी सं. 2018 का 354।लेकिन, यह तर्क प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां.

63. प्राथमिकी नं. 2018 के 100 को याचिकाकर्ता द्वारा डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113।शुरू में, टी. एस. आर. सी. एम. को रिश्वत के रूप में पैसे के बयान के संबंध में आरोप नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जवाबी शपथ पत्र में, याचिकाकर्ता ने वही आरोप लगाए हैं, जो सोशल मीडिया प्रकाशन का आधार हैं।क्या इसे समानता की जांच करने के लिए माना जा सकता है?

64. वास्तव में, अमित भाई (उपरोक्त) के मामले में, सीबीआई द्वारा पहले डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2007 की धारा 115 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, जिसमें सी. बी. आई. ने कहा था कि यह घटना उसी शपथ पत्र का हिस्सा थी।अमित भाई (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैरा 28 और 29 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया गया है और इसे पैरा 31 में भी निर्दिष्ट किया गया है।इसका मतलब है कि डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. सं. में प्रत्युत्तर शपथ पत्र में क्या तर्क दिया गया है। 2018 के 2113 को भी समानता की जांच करने के लिए कुछ सीमा तक माना जा सकता है।न मात्र डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. के जवाबी शपथ पत्र में नं. 2018 का 2113, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 28.01.2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन सभी चीजों का खुलासा किया, जो सोशल मीडिया प्रकाशन का आधार बनाते हैं।यह अकेले याचिकाकर्ता नहीं है, जिन्होंने दिनांक 28.01.2019 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या में दायर जवाबी शपथ पत्र के बारे में बताया है। 2018 का 2113, लेकिन प्राथमिकी नं. 2018 के 100 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाबी शपथ पत्र पर भी ध्यान दिया।

प्राथमिकी में दायर आरोप पत्र में नं. 2018 के 100, आई. ओ. ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113।

65. प्राथमिकी नं. 2018 का 100 बार-बार लिखता है कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई हिंसा, अशांति आदि पैदा करने के लिए राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए थी। तत्काल एफ. आई. आर. में, मुखबिर कहता है कि उसे नुकसान पहुंचाया गया है और याचिकाकर्ता की कार्रवाई से जनता को धोखा दिया गया है।लेकिन, अपने जवाबी शपथ पत्र में राज्य ने पैरा 4 में (पैरा वार जवाब में) लिखा है कि तत्काल प्राथमिकी में भा.दं.सं. खंड धारा 124 ए को जोड़ा गया था,

एक बार सामग्री सामने आने के बाद, जिससे पता चला कि याचिकाकर्ता उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध निरंतर और बेईमान शिकायत के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में अशांति पैदा करने के इरादे से गतिविधियों में लिप्त था।इसका मतलब है कि राज्य के अनुसार, याचिकाकर्ता राज्य को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है।यह वही है जो प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां.अब राज्य यही कहता है।इसका मतलब है कि राज्य के अनुसार याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी।अधिनियम अलग हैं, उदाहरण के लिए, पहले मुखबिर के माध्यम द्वारा स्टिंग करना, जिसने प्राथमिकी नं 2018 का 100 और सोशल मीडिया प्रकाशन का उपयोग करके सूचना देने वाले के विरुद्ध झूठे आरोप लगाना।लेकिन, राज्य के अनुसार, बड़ी छतरी राज्य सरकार के विरुद्ध साजिश है।इससे पूरा लेन-देन एक हो जाता है।सोशल मीडिया प्रकाशन का यह हिस्सा राज्य सरकार के संज्ञान में था जब प्राथमिकी नं 2018 के 100 को डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113।इसलिए, समानता का सिद्धान्त तत्काल मामले में लागू होता है।एक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, विभिन्न कृत्य किए गए।प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां में कुछ कृत्यों की जांच की गई थी। अन्य कार्य जो अब तत्काल प्राथमिकी आर. का आधार हैं, राज्य के संज्ञान में थे, जब प्राथमिकी आर. नं. 2018 के 100 को चुनौती दी गई थी।प्राथमिकी नं. 2018 की 100 और तत्काल प्राथमिकी उन अपराधों से संबंधित है जो कथित रूप से एक ही लेन-देन में एक साजिश के से किए गए थे।ऐसी स्थिति में, आरोपों के संबंध में कोई भी शिकायत, जो सोशल मीडिया प्रकाशन का हिस्सा हैं और जो डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. सं. 2018 की 2113 की जाँच शपथ पत्र FIR नं. 2018 का 100 वां.

आई. ओ. अग्रेतर प्राथमिकी आर. नं. 2018 का 100 वां.लेकिन दूसरी FIR i.e. प्राथमिकी नं. 2018 के 265 को इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत नहीं किया जा सकता था।कानून के से इसकी अनुमति नहीं है।तत्काल प्राथमिकी पर अलग से जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती है।केवल इसी आधार पर प्राथमिकी नं. 2020 का 265 रद्द किए जाने के योग्य है।

प्रथमदृष्टया

66. तत्काल मामले में प्राथमिकी भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469,471 और 120-बी के से दर्ज की गई है। मुख्य रूप से, यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित झूठी जानकारी को प्रचारित किया गया था।

66.1.कि विमुद्रीकरण के दौरान अमरेश सिंह चौहान ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अमरेश सिंह चौहान को नियुक्त करने के लिए टीएसआरसीएम को रिश्वत के रूप में भुगतान करने के लिए मुखबिर, उसकी पत्नी और प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन के विभिन्न बैंक खातों में पैसे जमा किए और;

66.2.कि मुखबिर की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की वास्तविक बड़ी बहन है।

67. न्यायालय सतर्क है कि इस स्तर पर, तत्काल कार्यवाही में, किसी भी सामग्री का गहरा विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए।जिस बात का तर्क दिया जा रहा है वह यह है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर-कानूनी मामला बनाया गया है।उस सीमा तक मात्र सामग्री की जांच की जा रही है।
68. निस्संदेह, सोशल मीडिया प्रकाशन का आधार बनने वाली सामग्री को याचिकाकर्ता द्वारा डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. नं. 2018 का 2113।याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 28.01.2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर भी उन्होंने इन सभी चीजों का खुलासा किया।जिसके बाद, याचिकाकर्ता के अनुसार, इस मामले पर राज्य की विधानसभा में बहस हुई।याचिकाकर्ता का यह भी स्पष्ट मामला है कि अमरेश सिंह चौहान परेशान थे क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला जो उनसे वादा किया गया था, इसलिए उन्होंने इन सभी तथ्यों को एक पत्रकार राजेश शर्मा को बताया, जिन्होंने याचिकाकर्ता को इसका खुलासा किया।

69. वास्तव में, याचिकाकर्ता ने 29.09.2020 को तत्काल कार्यवाही में एक अतिरिक्त शपथ पत्र भी दायर किया और इसके माध्यम से, याचिकाकर्ता ने खुलासा किया कि, वास्तव में, वही आरोप पहले एक वेब पोर्टल 'तीसरी आंख का तहलका' पर प्रकाशित किए गए थे।इसके बाद, मुखबिर ने वेब पोर्टल के विरुद्ध भारतीय प्रेस परिषद में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।जहां वेब पोर्टल को जवाब दाखिल करना था, लेकिन पश्चात में, सूचना देने वाले का एक साक्षात्कार वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था, "तीसरी आंख का तहलका", जिसमें, सूचना देने वाले ने वर्ष 2019 में ही कहा था कि विमुद्रीकरण के पश्चात उसके या उसके रिश्तेदारों के खाते में कोई पैसा जमा नहीं किया गया था।सूचना देने वाले ने हालांकि जवाबी हलफनामा दायर किया था, लेकिन 29.09.2020 के इस शपथ पत्र का सूचना देने वाले ने खंडन नहीं किया है। मौखिक रूप से, मुखबिर की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि वेब पोर्टल "तीसरी आंख का तहलका" ने कुछ अन्य लेनदेन के बारे में समाचार प्रकाशित किया था।वे क्या हैं?वेब पोर्टल पर क्या खबर छपी थी?यह सूचना देने वाले की ओर से भी नहीं कहा गया है।साक्षात्कार की प्रतिलिपि, जिसे याचिकाकर्ता के दिनांक 29.09.2020 के शपथ पत्र के संलग्नक संख्या 6 के रूप में दायर किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि लेनदेन झारखंड, विमुद्रीकरण और सूचना देने वाले के खाते में धन जमा करने से संबंधित है।यह कथन के समान और समान है, जो अब तत्काल प्राथमिकी आर. में किए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों के खाते में पैसे जमा करने के आरोप बहुत पहले, वर्ष 2019 में भी सार्वजनिक क्षेत्र में थे।
70. राज्य की ओर खंड, यह तर्क दिया जाता है कि भा.दं.सं. की धारा 415 के से अपराध बनाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक सोशल मीडिया प्रकाशन के माध्यम खंड आम जनता

को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया, जिसखंड सूचना देने वाले के शरीर, दिमाग और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।भा.दं.सं. की खंड 415 का संदर्भ दिया गया है, जो इस प्रकार हैः"

415.Cheating- जो कोई भी, किसी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई सम्पति देने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर इस तरह से धोखा दिए गए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है या ऐसा करने के लिए छोड़ देता है जो वह नहीं करेगा या छोड़ देता है यदि वह धोखा नहीं होता है, और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या सम्पति को नुकसान या नुकसान पहुंचाता है या होने की संभावना है, उसे "धोखा" कहा जाता है।
71. इस स्तर पर कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए व्हाट्सएप संदेशों और बातचीत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि सूचना देने वाले या उसके परिवार के सदस्यों के खाते में राशि जमा नहीं की गई थी।लेकिन पैसा कुछ अन्य खातों में जमा किया गया था।तर्क यह है कि भले ही सूचना देने वाले की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की रिश्तेदार न हो, यह कोई अपराध नहीं बनाता है।
72. भा.दं.सं. की खंड 415 दो भागों में है।पहला भाग किसी व्यक्ति को धोखे से और बेईमानी से धोखा देने, किसी सम्पति आदि को देने से संबंधित है, और दूसरा भाग जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित है जिसे धोखा दिया गया है या कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसे वह नहीं करेगा या छोड़ देगा, अगर उसे धोखा नहीं दिया गया था और जो कार्य या चूक उस व्यक्ति को नुकसान या नुकसान पहुंचाती है या होने की संभावना है।भा.दं.सं. सी. की खंड 415 की परिभाषा दो व्यक्तियों को संदर्भित करती है, अर्थात् (i) प्रलोभन देने वाला व्यक्ति और (ii) धोखा खाने वाला व्यक्ति।भा.दं.सं. की धारा 415 के अनुसार, नुकसान उस व्यक्ति को होना चाहिए, जिखंड धोखा दिया गया है।यदि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, जिखंड धोखा नहीं दिया जाता है, तो भा.दं.सं. की धारा 415 का प्रावधान लागू नहीं हो सकता है।
73. याचिकाकर्ता की ओर से, G.V. के फैसले में अवलम्ब रखी गई है। राव बनाम L.H.V. प्रसाद और अन्य, (2000) 3 एससीसी 693 और शीला सेबेस्टियन बनाम आर. जवाहराज और एक अन्य, (2018) 7 एससीसी581।G.V. के मामले में। राव (उपर्युक्त), माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः
"6. यह भाग जानबूझकर धोखे की बात करता है जिसका उद्देश्य न मात्र धोखा दिए गए व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करना या कुछ करने से बचना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या सम्पति को नुकसान या नुकसान पहुंचाना भी होना चाहिए। जानबूझकर किया गया धोखा प्रलोभन देने वाले व्यक्ति के एक प्रमुख उद्देश्य के अस्तित्व का

अनुमान लगाता है।इस तरह के प्रलोभन से व्यक्ति को धोखा दिया जाना चाहिए था या ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए था या कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था जो उसने नहीं किया होता या अगर उसे धोखा नहीं दिया जाता तो उसे करने से छोड़ दिया जाता।

अग्रेतर की आवश्यकता यह है कि इस तरह के कार्य या चूक से शरीर, मन, प्रतिष्ठा या सम्पति को नुकसान या नुकसान होना चाहिए।

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खंड 415 के दो भाग हैं।जबकि पहले भाग में, व्यक्ति को शिकायतकर्ता को किसी भी संपत्ति को देने के लिए "बेईमानी से" या "धोखाधड़ी से" प्रेरित करना चाहिए; दूसरे भाग में, व्यक्ति को जानबूझकर शिकायतकर्ता को कुछ करने या करने से रोकने के लिए प्रेरित करना चाहिए।कहने का मतलब है, पहले भाग में, प्रलोभन बेईमानी या धोखाधड़ी होना चाहिए।दूसरे भाग में प्रलोभन जानबूझकर होना चाहिए।जैसा कि जसवंतराय मणिलाल अखाने बनाम बॉम्बे राज्य में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, एक दोषी इरादा धोखाधड़ी के अपराध का एक अनिवार्य घटक हैइसआदेश, धोखाधड़ी के अपराध के आदेश किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के आदेश, उस व्यक्ति की ओर से "पुरुष अधिकार" स्थापित किया जाना चाहिए।महादेव प्रसाद बनाम W.B.4 राज्य में यह भी कहा गया है कि धोखाधड़ी के अपराध का गठन आदेश के लिए छल आदेश का इरादा उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जब प्रलोभन दिया गया था।

74. शीला सेबेस्टियन (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि "किसी ऐसे व्यक्ति पर जालसाजी का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जो इसे बनाने वाला नहीं है।"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी की अवधारणा की व्याख्या की कि किसे धोखा दिया गया माना जा सकता है।माननीय न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"23. मोहम्मद में अदालत।इब्राहिम ने देखा किः

"16. .... एक बिक्री विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच एक मौलिक अंतर है जो दावा करता है कि दी गई सम्पति उसकी सम्पति है, और एक व्यक्ति जो मालिक का प्रतिरूपण करके या मालिक द्वारा अधिकृत या सशक्त होने का झूठा दावा करके बिक्री विलेख निष्पादित करता है, मालिक की ओर से विलेख को निष्पादित करने के लिए।जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को निष्पादित करता है जो उसे अपनी सम्पति बताता है, तो दो संभावनाएँ होती हैं। पहला यह है कि वह ईमानदारी से मानता है कि सम्पति वास्तव में उसकी है।दूसरा यह है कि हो सकता है कि वह बेईमानी से या धोखाधड़ी से इसे अपना होने का दावा कर रहा हो, भले ही वह जानता हो कि यह उसकी सम्पति नहीं है।लेकिन "झूठे दस्तावेजों" से पहली श्रेणी के अंतर्गत

आने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि किसी दस्तावेज़ को बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाया या निष्पादित किया गया हो।एक अग्रेतर आवश्यकता है कि यह विश्वास दिलाने के इरादे से बनाया जाना चाहिए था कि ऐसा दस्तावेज़ किसी व्यक्ति द्वारा या उसके प्राधिकरण द्वारा बनाया या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था या निष्पादित किया गया था।
17. जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी सम्पति का दावा करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है जो उसकी नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है।इसलिए, ऐखंड दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ सम्पति को व्यक्त करने के लिए जिसका वह मालिक नहीं है) संहिता की धारा 464 के से परिभाषित किए गए झूठे दस्तावेज़ का निष्पादन नहीं है।यदि जो निष्पादित किया जाता है वह एक झूठा दस्तावेज नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है।

यदि कोई जालसाजी नहीं है, तो न तो खंड 467 और न ही संहिता की खंड 471 को आकर्षित किया जाता है।75. बाबू खान भा.दं.सं. राज्य, ए. आई. आर. 1961 इलाहाबाद 639 के मामले में, आई. पी. सी. की धारा 415 के उपबंध पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट रूप खंड अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 415 का अपराध तमात्र पूर्ण होता है जब ठगे गए व्यक्ति को मात्र नुकसान पहुँचाया जाता है।न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः
"6. राजपाल के शरीर को नुकसान या क्षति पहुंचाई गई है, जिसका ऑपरेशन किया गया था; लेकिन ऊपर बताई गई परिभाषा के अनुसार यह आवश्यक है कि नुकसान उस व्यक्ति को हो, जिसने किसी और को धोखा नहीं दिया हो, और इस मामले में धोखा देने वाला व्यक्ति राजपाल नहीं बल्कि जालिम था।हालाँकि मन में क्षति या हानि माना जाना बाकी है; यद्यपि मुझे ऐसा लगता है कि ज़लीम को स्वयं उस कार्य से मन में नुकसान पहुंचा था, जो उसे करने के लिए प्रेरित किया गया था-अभियुक्त द्वारा किया गया धोखा, क्योंकि उसने अपने बेटे की आंख पर ऑपरेशन करने की अनुमति दी थी, अनिवार्य रूप से उसे बहुत मानसिक पीड़ा का कारण बना होगा।
दंड संहिता में "मन में क्षति या हानि" को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें मानसिक क्षमताओं को चोट और मानसिक दर्द दोनों शामिल हैं (शरीर में क्षति या नुकसान घावों या अन्य चोटों और शारीरिक दर्द को भी कवर करता है)।संक्षेप में, मुझे संतोष है कि शिकायतकर्ता जालिम को अभियुक्त द्वारा धोखा दिया गया था और इस तरह उसे एक ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया था (अपने बेटे को ऑपरेशन करने की अनुमति दी गई थी) जो वह नहीं करता अगर ऐसा धोखा नहीं होता; और यह कि इस कार्य ने मानसिक पीड़ा में जालिम के मन को नुकसान पहुंचाया।इसलिए यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी के अपराध के सभी

तत्व, धारा में परिभाषित किए गए हैं। 415, I.P.C., वर्तमान मामले में बनाया गया है और धारा के से आरोपी की सजा। 419, I.P.C. इसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है "।

76. तत्काल मामले में, राज्य की ओर से जो तर्क दिया जा रहा है, वह यह है कि याचिकाकर्ता ने गलत बयान देकर जनता को धोखा दिया और बाद में, इसने मुखबिर को नुकसान पहुंचाया। मुखबिर द्वारा शिकायत की गई है।सूचना देने वाले को धोखा नहीं दिया गया था, इसलिए, सूचना देने वाले को भा.दं.सं. की धारा 415 के से अपराध नहीं माना जाता है, भले ही उखंड नुकसान पहुंचा हो।ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके साथ धोखा नहीं हुआ था।और धोखाधड़ी के अपराध को आकर्षित करने के लिए, जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 415 के से परिभाषित किया गया है, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए, जिखंड धोखा दिया गया था।जनता के किसी भी सदस्य ने शिकायत नहीं की थी कि याचिकाकर्ता ने उसे धोखा दिया है, जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है।तदनुसार, यहां तक कि प्रथम दृष्टया, भा.दं.सं. की खंड 415 के से अपराध नहीं माना जाता है।

77. भा.दं.सं. की धारा 467,468,469,471 और 120-बी के से भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

78. राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्रकाशन में कुछ बैंक जमा रसीदें दिखाई और बताया कि राशि मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों के खातों में जमा की गई थी, इसका मतलब है कि उसने जाली रसीदें बनाई थीं।याचिकाकर्ता ने अमरेश सिंह चौहान और टी. एस. आर. सी. एम. के बीच कथित रूप से की गई कुछ व्हाट्सएप चैट दायर की है। इसमें कुछ बैंक जमा रसीदें भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सूचना देने वाले के नाम पर नहीं है।इन व्हाट्सएप संदेशों की विश्वसनीयता के बारे में राज्य की ओर से तर्क दिए गए हैं।याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि सूचना देने वाले के खाते में राशि जमा करने के संबंध में कोई रसीद नहीं है और वह अग्रेतर स्वीकार करता है कि सूचना देने वाले और उसके परिवार के सदस्यों के खाते में राशि जमा नहीं की गई थी।बहस के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि सोशल मीडिया प्रकाशन में दिखाई गई रसीदें रजनी, रामू धीमान और राजेंद्र कौशल के खातों में जमा राशि से संबंधित हैं।यह न्यायालय इस पहलू पर कोई टिप्पणी अभिलेख नहीं कर सकता है।

79. सूचना देने वाला अपने जवाबी-हलफनामे में जो लिखता है वह यह है कि चूंकि, बैंक अभिलेख से पता चलता है कि उसके खाते में कोई जमा नहीं किया गया था; इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा बैंक रसीदें/जमा पर्ची जाली हैं।याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष इस बात से इनकार किया है कि सूचना देने वाले के खाते में कोई राशि जमा की गई थी। याचिकाकर्ता ने सूचना देने वाले के खाते से संबंधित किसी भी जमा पर्ची से भी इनकार किया। कथित व्हाट्सएप संदेशों में भी सूचना देने वाले से संबंधित कोई जमा रसीदें नहीं हैं।राज्य या सूचना देने वाले की ओर से यह भी नहीं दिखाया गया है कि सूचना देने वाले और उसके परिवार के सदस्यों के खाते से संबंधित बैंक जमा रसीद की प्रकृति का कोई दस्तावेज है।जालसाजी का

प्रश्न कहां है?कोई दस्तावेज नहीं है।यह अधिक से अधिक गलत बयान देने का मामला है, लेकिन इसमें जालसाजी का प्रावधान नहीं है।यहां तक कि प्रथम दृष्टया खंड 467,468,469 और 471 के से कोई मामला नहीं बनता है।

80. याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं.सं. की खंड 124-ए के से अपराध भी जोड़ा गया है। अपने जवाबी हलफनामे में राज्य ने पैरा नं. 4, (पैरा वार उत्तर में) इस आधार पर कि एक बार सामग्री प्रकाश में आई, जिसखंड पता चला कि याचिकाकर्ता उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध एक निरंतर और बेईमान अभियान के माध्यम खंड उत्तराखंड राज्य में अशांति पैदा करने के इरादे खंड गतिविधियों में लिप्त था और उसकी कार्रवाई उसके विरुद्ध कथित अन्य अपराधों के अलावा भा.दं.सं. की धारा 124-ए के मापदंड के भीतर आती है।लिखित तर्क में, राज्य की ओर से, उनके बिंदु पर निम्नलिखित कहा गया है।

"6. आईपीसी की खंड 124 एःयह सामने आया है कि याचिकाकर्ता घृणा और अवमानना लाने और उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के इरादे से उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध एक बड़ी साजिश और दुर्भावनापूर्ण साजिश का हिस्सा है, जैसा कि जांच का हिस्सा और केस डायरी में दर्ज सामग्री से पता चलता है।इसलिए, भा.दं.सं. की खंड 124-ए को विवादित प्राथमिकी में जोड़ा गया था। इस प्रकार खंड 124 ए को मात्र आरोपी द्वारा उसके 24.06.2020 के फेसबुक वीडियो में दिए गए बयानों पर नहीं जोड़ा गया था।यद्यपि इस स्तर पर जाँच के हर पहलू का खुलासा करना न मात्र जाँच के पाठ्यक्रम को बल्कि कुछ गवाहों को भी खतरे में डाल देगा। पुलिस रिमांड और मुकदमे के दौरान सक्षम क्षेत्राधिकार की विचारणों के समक्ष उचित सबूत पेश करेगी।यदि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में कुछ भी सच्चाई होती, तो निश्चित रूप खंड भा.दं.सं. की धारा 124 ए को आकर्षित नहीं किया जा सकता था।लेकिन एक बार जब जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता ने जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकार के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए और उसके बाद जानबूझकर झूठे आरोपों के आधार पर सरकार के विरुद्ध आम जनता को प्रोत्साहित किया, तो याचिकाकर्ता अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में अपने आपराधिक कार्यों के परिणामों से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता के फेसबुक वीडियो पर आम जनता के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के अवलोकन से भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने काउंटर के फेसबुक वीडियो @सीए 12 @पीजी. 108 पर आम जनता द्वारा उत्तराखंड सरकार की टिप्पणियों के विरुद्ध नफरत भड़काने के इरादे से काम किया।यह भी ध्यान दें योग्य है कि पश्चिम बंगाल राज्य में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।याचिकाकर्ता पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली, प्रतिरूपण और भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न अपराधों का आरोप है।दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल राज्य में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज कुछ प्राथमिकियों में, याचिकाकर्ता पर इसी तरह रिकॉर्ड बनाने, जबरन वसूली, ब्लैकमेल करने और ब्लैकमेल करने के इरादे से सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को लुभाने का प्रयास करने का आरोप लगाया

गया है।यह ध्यान दें योग्य है कि ये सभी प्राथमिकियां वर्तमान में जांच के लिए लंबित हैं और इस संबंध में कोई रोक नहीं दी गई है।याचिकाकर्ता ने इन एफ. आई. आर. एस. के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है जिसमें जांच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने की मांग की गई है जो निर्णय के लिए लंबित है जबकि एफ. आई. आर. में जांच जारी है।

81. बहस के दौरान, अदालत ने राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता खंड यह समझाने का अनुरोध विद्वान कि भा.दं.सं. की धारा 124-ए से अपराध कैखंड बनाया जाता है।

जवाब दिया गया था कि "यह जांच का विषय है"।यदि, प्रथमदृष्टया बिना किसी जांच के मामला बनता है, तो निश्चित रूप से मामले को जांच के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि, प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है, तो ऐसे मामलों में, तत्काल की तरह कार्यवाही में, हस्तक्षेप निश्चित रूप से आवश्यक है।यही भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का दायरा है।याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप दो गुना हैं कि उसने गलत बयान दिया कि कोई भी राशि मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों आदि के खाते में जमा की गई थी, और उसने एक और गलत बयान दिया कि मुखबिर की पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की पत्नी की असली बड़ी बहन है। ये आरोप आईपीसी की धारा 124-ए के प्रावधान को कैखंड आकर्षित कर सकते हैं?भले ही यह आरोप लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री ने रिश्वत ली है, लेकिन भा.दं.सं. की धारा 124-ए कैखंड आकर्षित होती है?याचिकाकर्ता की ओर खंड यह तर्क दिया जाता है कि भा.दं.सं. की धारा 124-ए के से अपराध दूर खंड भी नहीं बनाया गया है।केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 955 के मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

82. भा.दं.सं. की खंड 124-ए की कोई भी व्याख्या इस न्यायालय को इतिहास की गहराई में ले जाएगी।यह न्यायालय गहन चर्चा से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन तत्काल विवाद की सराहना करने के लिए इसकी उत्पत्ति और इसके जॉमी के कुछ संदर्भ आवश्यक हैं।यह तत्काल मामले में राज्य है जो सूचना देने वाले द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर याचिकाकर्ता पर मुकदमा चला रहा है।यह राज्य है जिसने भा.दं.सं. की खंड 124-ए जोड़ी थी। भा.दं.सं. की खंड 124-ए इस प्रकार हैः

"124-ए. राजद्रोह।- जो कोई भी, मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, या अन्यथा, कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है, या असंतोष को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास से जो तीन साल तक बढ़ सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1-"असंतोष" अभिव्यक्ति में बेवफाई और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं।

स्पष्टीकरण 2-घृणा, अवमानना या असंतोष को उत्तेजित किए बिना या भड़काने का प्रयास किए बिना, वैध साधनों द्वारा उनके परिवर्तन को प्राप्त करने खंड दृष्टि से सरकार के उपायों खंड अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के से अपराध नहीं हैं।
स्पष्टीकरण 3-घृणा, अवमानना या असंतोष को उकसाने या भड़काने का प्रयास किए बिना सरकार खंड प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई खंड अस्वीकृति व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के से अपराध नहीं हैं।83. भा.दं.सं. की धारा 124-ए में 'घृणा', 'अवमानना', 'उकसाने', 'असंतोष' जैसे कई भारी शब्दों का उपयोग किया गया है। यह उसके तहत दिए गए कार्यों को परिभाषित करने के साथ-साथ दंडित भी करता है।
इस खंड का शीर्षक "राजद्रोह" है।खंड में इस तरह के शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।एक प्रावधान, जो प्रारंभिक भारतीय दंड संहिता 1860 में नहीं था और बाद में वर्ष 1870 में जोड़ा गया।कहा जाता है कि भारतीय दंड संहिता के मसौदे में यह प्रावधान था, लेकिन गलती के कारण इसे जोड़ा नहीं जा सका।वर्ष 1870 में, भारत स्वतंत्र नहीं था, इद्वारा क्राउन द्वारा राज्य सचिव के माध्यम द्वारा शासित किया जा रहा था।उस समय शासन में भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी।वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे।उस समय हम खुद पर शासन नहीं कर रहे थे।हम बाहरी लोगों द्वारा शासित थे।शासन में कोई आवाज नहीं है।आज भारत, एक संप्रभु देश, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।
84. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ और एक अन्य (2018) 8 एस. सी. सी. 501 के मामले में, लोकतांत्रिक भारत की अवधारणा पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है।इसके शासन, इसके घटक और इसके संवैधानिक दर्शन की व्याख्या की जाती है।न्यायालय ने पैरा नं. 305.1 कि "पहला यह है कि एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में, संविधान लोगों की संप्रभुता की अभिव्यक्ति है।अब, लोग संप्रभु हैं।जनता ही अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम द्वारा खुद पर शासन करती है।भारत के शासन में लोगों की अपनी राय है।भारत के लोगों की रुचि देश के शासन में है।वे सरकार में भाग लेते हैं।संप्रभुता लोगों के पास है।संविधान इसकी अभिव्यक्ति है।
85. भारत का संविधान संविधान के अनुच्छेद 19 से दिए गए उचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।बहुत पहले, जब बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था, तब वे खड़े हुए और कहा, "कानून कठोर हो सकता है; कानून कठोर हो सकता है।मेरे और कानून के बीच खड़े रहें और मेरी रक्षा करें क्योंकि मैं प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता हूं।महात्मा गांधी जब श्री सी. एन. ब्रूमफील्ड, भा.दं.सं. एस., जिला के समक्ष आई. पी. सी. की खंड 124-ए के से आरोपों के लिए मुकदमा चलाया गया और सम्राट बनाम बाल गंगाधर तिलक, 1908 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 48:

(1908) 8 सी. आर. एल. जे. 281 खंडशन जज, अहमदाबाद ने 18.03.1922 को कहा था, "मेरी मत में, कानून का प्रशासन इस प्रकार शोषक के लाभ के लिए, जानबूझकर या अनजाने में, वेश्यावृत्ति है.....। धारा 124 ए, जिसके से मुझे खुशी-खुशी आरोपित किया गया है, शायद भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं में खंड एक है जो नागरिक की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाई गई है।स्नेह को कानून द्वारा निर्मित या विनियमित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी को किसी व्यक्ति या व्यवस्था के लिए कोई स्नेह नहीं है, तो उसे अपने असंतोष को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक कि वह हिंसा पर विचार नहीं करता, बढ़ावा नहीं देता या उकसाता नहीं
है.....
.....●

86. संविधान सभा में, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा की जा रही थी, विधानसभा ने संविधान के मसौदे से राजद्रोह शब्द को हटाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया था।विचार-विमर्श के दौरान श्री.एम. अनंतसायनम अय्यंगार ने 02.12.1948 को कहाः

उन्होंने कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में हमने खंड (2) में लगाए गए प्रतिबंधों में सुधार किया है।राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है।यदि हम पाते हैं कि सरकार को कुछ समय के लिए खुद को घेरने की आदत है, यद्यपि उसका प्रशासन हो सकता है, तो यह देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होना चाहिए कि वह बिना हिंसा के, लोगों को राजी करके, प्रशासन में उसके दोषों, उसके काम करने के तरीके आदि को उजागर करके उस सरकार को उखाड़ फेंके।'राजद्रोह' शब्द पिछले शासन में अप्रिय हो गया है।इसलिए हमने संशोधन को मंजूरी दी थी कि 'राजद्रोह' शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां पूरे राज्य को उखाड़ फेंकने या बल द्वारा या अन्यथा कमजोर करने की कोशिश की जाती है, जिससे सार्वजनिक अव्यवस्था होती है, लेकिन सरकार पर किसी भी हमले को कानून से अपराध नहीं बनाया जाना चाहिए।हमने वह स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और हमने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक भाषणों से राज्य को पूरी तरह से उखाड़ फेंका न जाए, तब तक कोई भी सरकार संभवतः खुद को घेर न सके।

(जोर दिया गया)

87. जब केदार नाथ सिंह (उपर्युक्त) के मामले में धारा 124-ए की संवैधानिक वैधता की जांच की गई थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "कोई भी कानून, जो सार्वजनिक आदेश के हित में अधिनियमित किया जाता है, उखंड संवैधानिक अयोग्यता की आवाज खंड बचाया जा सकता है।दूसरी ओर, यदि हम यह मानते हैं कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कानून के कुछ प्रावधान एक तरह से उन्हें संविधान के अनुरूप बनाते हैं, तो एक अन्य व्याख्या उन्हें प्रस्तुत करेगी

7 https:. constitutionofindia.net/constitution assembly_debates/volume/ 7/1948-12-02 unconstitutional, , न्यायालय पूर्व निर्माण के पक्ष में झुकाव होगा.

स्पष्टीकरणों के साथ समग्र रूप से पठित धाराओं के प्रावधान से यह यथोचित रूप से स्पष्ट होता है कि धाराओं का उद्देश्य मात्र ऐसी गतिविधियों को दंडित करना है जिनका उद्देश्य हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या अशांति पैदा करना है।जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, धारा के मुख्य भाग से जुड़े स्पष्टीकरणों से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक उपायों खंड आलोचना या सरकारी कार्रवाई पर टिप्पणी, चाहे कितनी भी जोरदार हो, उचित सीमाओं के भीतर होगी यद्यपि भाषण यद्यपि अभिव्यक्ति खंड स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अनुरूप होगी।
(जोर दिया गया)
88. केदार नाथ सिंह (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधि स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि जब तक ऐसी गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी या अशांति पैदा नहीं करती हैं या हिंसा का सहारा नहीं लेती हैं, तब तक यह अपराध नहीं है।
89. किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आरोप लगाना कभी भी राजद्रोह नहीं हो सकता है, जब तक कि यह केदार नाथ सिंह (ऊपर) के मामले में निर्धारित परीक्षा को योग्य नहीं बनाता है।यदि प्रतिनिधियों के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं, तो यह अकेले देशद्रोह नहीं हो सकता है।सरकार की आलोचना करना कभी भी राजद्रोह नहीं हो सकता।जब तक सार्वजनिक पदाधिकारियों की आलोचना नहीं की जाती, लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता है।लोकतंत्र में असहमति का हमेशा सम्मान किया जाता है और माना जाता है, अगर इसे राजद्रोह कानूनों के से दबाया जाता है, तो शायद यह लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास होगा।तत्काल मामले में भा.दं.सं. की खंड 124-ए जोड़ना यह दर्शाता है कि यह राज्य का, आलोचना की आवाज को दबाने का, शिकायत/असहमति को दबाने का प्रयास रहा है।इसकी कभी अनुमति नहीं दी जा सकती।कानून इसकी अनुमति नहीं देता है।तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध जो भी आरोप हैं, वे दूर खंड भा.दं.सं. की धारा 124-ए खंड नहीं जुड़ते हैं। भा.दं.सं. की धारा 124-ए के से अपराध, प्रथम दृष्टया, नहीं बनाया गया है।इस खंड को क्यों जोड़ा गया है, यह समझ के बाद है।इस पहलू पर राज्य की ओर से जो कुछ भी कहा गया है, उसका कोई औचित्य नहीं है।
90. तत्काल मामले में प्राथमिकी भा.दं.सं. की धारा 120-बी के से भी है, लेकिन यह दिखाने के लिए भी कोई सामग्री नहीं है कि क्या आपराधिक साजिश की गई थी, इखंड प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है।
प्रथम दृष्टया, भा.दं.सं. की खंड 120-बी से कोई अपराध नहीं बनाया गया है।

91. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाता है और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाता है, प्रथम दृष्टया, कोई अपराध नहीं है या याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मामला नहीं बनाता है।इसलिए, केवल इसी आधार पर, तत्काल मामले में प्राथमिकी रद्द की जा सकती है।

दिनांक 07.07.2020 को संप्रेषण पर अपनाई गई प्रक्रिया

92. क्या दिनांक 07.07.2020 के संचार पर अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुसार थी।माना जाता है कि सूचना देने वाले द्वारा दिनांक 07.07.2020 को एक संदेश डी. आई. जी. पुलिस को संबोधित किया गया था और यह 09.07.2020 को दिया गया था।इस पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री के निजी सचिव को भेजी गई थी।15.07.2020 को, मुखबिर ने प्रभारी, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी को एक पत्र दिया जिसमें अनुरोध किया गया कि एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की जाए।19.07.2020 को, डी. आई. जी. देहरादून ने जांच करने के लिए सीओ की नियुक्ति की।30.07.2020 को सीओ द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। 31.07.2020 को, सूचना देने वाले ने आरटीआई के माध्यम द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति मांगी और उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की।याचिकाकर्ता की ओर से तर्क यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में कानून को जानकारी नहीं है।

93. राज्य की ओर से, जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि दिनांक 07.07.2020 का संचार किसी भी संज्ञेय मामले का खुलासा नहीं कर रहा था, इसलिए, ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर जांच की गई थी।

94. यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि दिनांक 07.07.2020 के पत्र में मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के संबंध में संदर्भ दिया गया था, इसलिए पर्याप्त एहतियात के तहत प्रारंभिक जांच की गई थी और यह किसी को भी प्रभावित नहीं करता है।

95. तपन कुमार सिंह (ऊपर) के मामले में फैसले का संदर्भ दिया गया है।ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था किःचाहे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के से, एक पुलिस अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है, जब कोई संज्ञेय अपराध बनता है या उसके (पुलिस अधिकारी) पास प्राथमिकी दर्ज करने खंड पहले किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच करने का विकल्प, विवेकाधिकार या अक्षांश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर व्यापक रूप खंड चर्चा की और पैरा नं. फैसले के 72 में कहा गया है कि "यह स्पष्ट रूप खंड स्पष्ट है कि प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।"पैरा नं. अपने निर्णय के 79वें भाग में, माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचना की तर्कसंगतता या

विश्वसनीयता किसी मामले के पंजीकरण के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है।"प्रारंभिक जाँच के संबंध में, माननीय न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"85. संहिता की खंड 154 की व्याख्या में "एक वस्तु की अभिव्यक्ति दूसरी वस्तु का अपवर्जन है" की अधिकतम अभिव्यक्ति लागू होती है, जहां लिखित रूप में सूचना अभिलिखित करने का अधिदेश विशेष रजिस्टर में संज्ञेय अपराध की सूचना अभिलिखित नहीं करने की संभावना को बाहर करता है।

86. इसलिए, संहिता की खंड 154 के से प्राथमिकी दर्ज करने के पश्चात किसी अपराध की जांच करना "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के से आरोपी के अधिकार की रक्षा की जाती है यदि पहले प्राथमिकी दर्ज की जाती है और फिर कानून के प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है।

96. अग्रेतर इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के कुछ अपवाद भी बनाए, जिनमें समय के साथ अपराधों की उत्पत्ति अग्रेतर नवीनता में परिवर्तन के कारण प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है।पैरा एनओएस में। 115 और 116 चिकित्सा लापरवाही के मामलों और पैरा संख्या में अपवाद स्वीकार किया गया था। भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध के संदर्भ में भी 117 अपवाद बनाए गए थे।निर्णय का निष्कर्ष पैरा संख्या 120. में तैयार किए गए हैं। पैरा 120.1 में निम्नलिखित विधि का उल्लेख किया गया हैः

"120.1।यदि सूचना संज्ञेय अपराध करने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है, तो संहिता की खंड 154 से प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है।

97. पैरा नं. 120.2 उपबंध करता है, यदि संज्ञेय अपराध नहीं किया जाता है और प्रारंभिक जांच की जा सकती है, जो कि निम्नानुसार हैः

"120.2।यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक जांच मात्र यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

98. पैरा नं. 120.6 उन मामलों को अपवाद बनाता है, जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है, जो इस प्रकार हैः

"120.6।किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार हैः

(a) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

(b) वाणिज्यिक अपराध

(c) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

(d) भ्रष्टाचार के मामले

(ई) ऐसे मामले जहां आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य विलम्ब/अड़चनें हैं, उदाहरण के लिए, विलम्ब के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की विलम्ब।

उपर्युक्त मात्र दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों का संपूर्ण विवरण नहीं है जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

99. ललिता कुमारी (उपरोक्त) के मामले में निर्णय में कहा गया है कि संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन, यदि जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, तो यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की अनुमति है कि क्या संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।इसपश्चात ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों सहित अपवाद बनाए गए हैं।पी. सिराजुद्दीन बनाम मद्रास राज्य, (1970) 1 एस. सी. सी. 595 के मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता थी।पी. सिराजुद्दीन (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय न्यायालय ने पैरा नं.17 ने अभिनिर्धारित किया कि "एक लोक सेवक के समक्ष, उसकी स्थिति जो भी हो, सार्वजनिक रूप से बेईमानी के कृत्यों का आरोप लगाया जाता है, जो इस मामले में कथित प्रकार के गम्भीर दुराचार या कदाचार के बराबर है और उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आरोपों की कुछ उपयुक्त प्रारंभिक जांच होनी चाहिए।एक व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट दर्ज करना, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो अपीलकर्ता को पसंद करता है, एक विभाग में शीर्ष पद पर है, भले ही वह आधारहीन हो, न मात्र विशेष रूप से अधिकारी के लिए, बल्कि उस विभाग के लिए भी जो वह सामान्य रूप से संबंधित है, अपूरणीय क्षति करेगा।

ललिता कुमारी (ऊपर) के मामले में इसे मंजूरी दे दी गई है।इखंड ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पैरा नं. 120.6, ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में इस मामले में निर्धारित सामान्य नियम के अपवाद हैं कि संहिता की धारा 154 से प्राथमिकी आर. का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है।

100 है। तत्सेल मामले में जांच किए जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या तत्सेल मामला ललिता कुमारी (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आता है (पैरा 120.2 या 120.6 में), जो प्रारंभिक जांच से समर्थन करता है।

101. सूचना देने वाले का दिनांक 07.07.2020 का संचार प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। पैरा नं.6 (सामान्य प्रस्तुतिकरण में) अपने जवाबी-हलफनामे में कहा गया है कि सूचना देने वाले ने दिनांक 07.07.2020 को अपने संचार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की मांग नहीं की थी।उन्होंने याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई की मांग नहीं की।

102. अब प्रश्न यह है कि यदि राज्य के अनुसार, दिनांक 07.07.2020 का संचार प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नहीं था और यह किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं कर रहा था, तो इस जानकारी को संहिता की खंड 154 के से जानकारी के रूप में नहीं कहा जा सकता है और उस मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज की जा सकती थी और न ही प्रारंभिक जांच की जा सकती थी।
103. तथ्य कुछ और ही कहते हैं।सूचना देने वाले के दिनांक 07.07.2020 के संचार में सबूत के साथ दो आरोप लगाए गए हैं।सूचना देने वाले ने यह दिखाने के लिए बैंक प्रमाण पत्र दिए थे कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित राशि उसके खातों में जमा नहीं की गई थी अग्रेतर उसने कहा है कि उसकी पत्नी टी. एस. आर. सी. एम. की रिश्तेदार नहीं है। जाँच पश्चात पुलिस द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की गई है।इसलिए, यह कहना कि दिनांक 07.07.2020 के संचार में संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए, जांच की गई थी, इसका कोई बल नहीं है क्योंकि प्राथमिकी भी उन्हीं आरोपों की बात करती है, जो दिनांक 07.07.2020 के संचार में लगाए गए थे।

जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र किया गया एकमात्र अतिरिक्त दस्तावेज़ सूचना देने मात्र की पत्नी का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र था, जिसे कथित प्रारंभिक जाँच के दौरान सूचना देने मात्र ने स्वयं उसे दिया था।
104. सूचना देने वाले द्वारा दिनांक 07.07.2020 को किए गए संचार की प्रकृति क्या थी?पैरा नं. जवाबी शपथ पत्र के 6 (सामान्य प्रस्तुतिकरण में) राज्य का कहना है कि सूचना देने वाला, "याचिकाकर्ता द्वारा सार्वजनिक रूप से उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए, मात्र एक जांच के लिए अनुरोध किया, ताकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उसके और कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध लगाए जा रहे आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित किया जा सके।एक व्यक्ति, पुलिस से जांच करने के लिए कैसे कह सकता है ताकि आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित किया जा सके?एक व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करने या अन्य कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस से संपर्क कर सकता है।क्या सूचना देने वाला साक्ष्य एकत्र करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने स्वयं दिनांक 07.07.2020 के संचार के साथ बैंक प्रमाण पत्र दिए थे और यह वह स्वयं है, जिसने कथित प्रारंभिक जांच के दौरान अपनी पत्नी का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया था।तब इस झूठ को प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता थी?यह संहिता की खंड 154 से जानकारी नहीं है।दिनांक 07.07.2020 के संचार पर अपनाई गई प्रक्रिया कानून के लिए अज्ञात है।पुलिस को केवल आरोप की असत्यता प्रदर्शित करने के लिए कैसे कहा जा सकता है?
105. यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि आरोप रिश्वत से संबंधित थे और मुख्यमंत्री को संदर्भित किया गया था, इसलिए पर्याप्त सावधानी के कारण प्रारंभिक जांच की गई थी।यदि यह

कथन सत्य होता तो ललिता कुमारी (उपर्युक्त) (पैरा सं. 120.6), लेकिन दुर्भाग्य से, यह निम्नलिखित कारणों से भी सच नहीं हैः

105.1.जांच, जो दिनांक 07.07.2020 के संचार के बाद की गई थी, मात्र दो चीजों तक सीमित थी, अर्थात् (i) सूचना देने वाले के बैंक रिकॉर्ड यह पता लगाने के लिए कि क्या उसके बैंक खाते में कोई राशि जमा की गई थी (हालांकि उसके संचार दिनांक 07.07.2020 के साथ, सूचना देने वाले ने स्वयं उन बैंक प्रमाणपत्रों को दिया था) और अग्रेतर सूचना देने वाले और टीएसआरसीएम के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए।

105.2.सोशल मीडिया प्रकाशन में, कई अन्य आरोप थे, टी. एस. आर. सी. एम. और अमरेश सिंह चौहान के बीच कथित रूप से व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान हुआ था।जाँच अधिकारी ने उन मुद्दों की जाँच नहीं की।उन्होंने व्हाट्सएप संदेशों की विश्वसनीयता, सत्यता या वास्तविकता या अमरेश सिंह चौहान और राजेश शर्मा के बीच कथित रूप से की गई टेलीफोनिक बातचीत के साथ-साथ टीएसआरसीएम और अमरेश सिंह चौहान के मीडिया सलाहकारों की भी जांच नहीं की।

105.3 है।यदि भ्रष्टाचार कथित प्रारंभिक जाँच का केंद्र मुद्दा होता; शायद, यह अनुमत था लेकिन जाँच अधिकारी द्वारा उस पहलू की जाँच बिल्कुल नहीं की गई थी।जाँच अधिकारी ने अन्य बैंक खातों की जाँच नहीं की; बैंक जमा रसीदों की जाँच नहीं की, जिन्हें याचिकाकर्ता ने कथित रूप से अपने सोशल मीडिया प्रकाशनों में लहराया या प्रदर्शित किया, जो कथित व्हाट्सएप संदेशों का हिस्सा थे।

106. इसलिए, इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि क्योंकि भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, इसलिए प्रारंभिक जांच की गई थी।कथित प्रारंभिक जाँच के लिए भ्रष्टाचार बिल्कुल भी केंद्र बिंदु नहीं था।दिनांक 07.07.2020 को संप्रेषित की गई प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं है।

107. कौन सी एफआईआर है?याचिकाकर्ता की ओर खंड, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल प्राथमिकी कुछ भी नहीं है, बल्कि संहिता की धारा 162 के से एक बयान है।उनके तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनती रामुलु और अन्य, 1994 सप्लीमेंट (1) एससीसी 590 और बॉम्बे राज्य बनाम रूसी मिस्त्री, एआईआर 1960 एससी 391 के मामले में निर्णय का उल्लेख किया।

108. पुनती रामुलु (उपरोक्त) के मामले में, अदालत ने एक रिपोर्ट पाई, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात तैयार किया गया था, जो वास्तविक और विश्वसनीय नहीं थी।

रूसी मिस्त्री (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा नं.निर्णय के 23 में कहा गया है कि "प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद दी गई जानकारी संहिता की खंड 161 और 162 द्वारा प्रभावित है"।
109. दिनांक 07.07.2020 के संचार और तत्काल प्राथमिकी की मूल सामग्री एक ही है।दिनांक 07.07.2020 का संचार भी सबूत के साथ था।जांच अधिकारी द्वारा अग्रेतर के सबूत के पश्चात तत्काल मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई।तपन कुमार सिंह (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा नं. फैसले के 23 में कहा गया है कि "जहां दो जानकारी दर्ज की जाती है और अदालत के समक्ष यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्राथमिकी के रूप में पेश की गई जानकारी वास्तव में प्राथमिकी नहीं है, बल्कि पहले दर्ज की गई कुछ अन्य जानकारी प्राथमिकी है, यह एक ऐसा मामला है, जिसे आरोपी पर मुकदमा चलाने वाले न्यायालय को तय करने का क्षेत्राधिकार है।पीठ ने कहा, "तत्काल मामले में भी यह विचारण न्यायालय यह ठहराने के लिए अग्रेतर बढ़ने का इरादा नहीं रखती है कि किस संचार को प्राथमिकी के रूप में माना जाना चाहिए, या तो दिनांक 07.07.2020 का संचार या तत्काल प्राथमिकी। यदि यह मामला बना रहता है, तो शायद निचली विचारण न्यायालय को, यदि ऐसा अवसर आता है, तो इस पहलू की जांच और जांच करने का अवसर मिल सकता है।यह न्यायालय इसे अपने ऊपर छोड़ देता है।

<u>दुर्भावनापूर्ण</u>

110 है। याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि पूरी प्रक्रिया, शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण है।यह याचिकाकर्ता के विरुद्ध शुरू किया गया एक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है।
111. दुर्भावना का शाब्दिक अर्थ बुरा विश्वास या इरादा आदि है। यह मन की स्थिति है, जो किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।मन को पढ़ना सबसे कठिन अभ्यासों में से एक है, लेकिन उपस्थित होने वाले कारकों से न्यायालय को इरादे का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।गुलाम मुस्तफा और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (1976) 1 एस. सी. सी. 800 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "सार्वजनिक निकायों और अधिकारियों के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण आरोप अधिक आसानी से बनाया जाता है।
यह एक हारे हुए वादकारी का अंतिम इनकार है।112. P.P. के मामले में। शर्मा (ऊपर), माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "शक्ति के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का प्रश्न तमात्र महत्व रखता है जब आपराधिक अभियोजन बाहरी विचारों और अनधिकृत उद्देश्य के लिए शुरू किया जाता है।"यह आगे देखा गया कि "यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि मामला दर्ज करने का प्रमुख उद्देश्य प्रतिवादी की चरित्र हत्या या उन्हें परेशान करना और अपमानित करना था।बिहार राज्य बनाम J.A.C. सल्धाना 3 ने अभिनिर्धारित किया है कि जब

सूचना थाने में दर्ज की जाती है और कोई अपराध दर्ज किया जाता है, तो सूचना देने वाले की दुर्भावना गौण महत्व की होगी।यह जाँच के दौरान एकत्र की गई सामग्री है जो अभियुक्त व्यक्ति के भाग्य का फैसला करती है।

113. P.P. के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुर्भावना की अवधारणा पर अग्रेतर चर्चा की गई है। शर्मा (ऊपर) और यह माना गया था कि;

"49. उपरोक्त पृष्ठभूमि से केंद्र बिंदु यह है कि क्या आरोप पत्र शिकायतकर्ता R.K. सिंह या जांच अधिकारी G.N.Sharma की ओर से कथित दुर्भावना से दूषित हैं।S.A. de Smith द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में, (3rd संस्करण।एटीपी।293 9 ने कहा किः

उन्होंने कहा, "वैधानिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में बुरे विश्वास की अवधारणा में बेईमानी (या धोखाधड़ी) और द्वेष शामिल हैं।एक शक्ति का प्रयोग धोखाधड़ी से किया जाता है यदि उसका भंडार उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने का इरादा रखता है जिसके लिए वह मानता है कि शक्ति प्रदान की गई है।उनका इरादा किसी अन्य सार्वजनिक हित या निजी हित को बढ़ावा देना हो सकता है।एक शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाता है यदि इसका भंडार उन लोगों के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता से प्रेरित होता है जो इसके अभ्यास से सीधे प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक विवेकाधिकार का अर्थ है प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण होने की शक्ति।इसका तात्पर्य किसी कार्य को करने या किसी मामले को विवेकाधिकार से तय करने का अधिकार है..... "

"50. माला फिडेस का अर्थ है अच्छे विश्वास की कमी, व्यक्ति पक्षपात, द्वेष, तिरछा या अनुचित उद्देश्य या गलत
उद्देश्य.....
....."

"51. इसलिए की गई कार्रवाई को इस तरह के विचारों के लिए दुर्भावनापूर्ण साबित किया जाना चाहिए केवल दावा या एक अस्पष्ट या गंजा बयान पर्याप्त नहीं है।इसे किसी दिए गए मामले में स्वीकार किए गए या सिद्ध तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

यदि यह स्थापित हो जाता है कि इस तरह के किसी भी विचार के लिए या सत्ता पर धोखाधड़ी या सत्ता के रंगीन प्रयोग के लिए कार्रवाई की गई है, तो इसे खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

114. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा और अन्य (2002) 3 एस. सी. सी. 89 के मामले में, माननीय न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"6. .....खंड के से शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।खंड के से अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप खंड संयम,

सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और मात्र तभी जब इस तरह का अभ्यास खंड में विशेष रूप खंड निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो।जिनका केवल न्यायाधीशालय ही अस्तित्व में हैं, उनके प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्यायाधीश करने के लिए इसका प्रयोग प्रत्यर्पित न्यायाधीश के रूप में किया जाना है।न्यायाधीश की उन्नति के लिए न्यायाधीशालय का प्राधिकरण मौजूद है और यदि अन्यायाधीश उत्पन्न करने के लिए उस प्राधिकरण का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो न्यायाधीशालय के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है।यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए न्यायाधीशालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्यायाधीश होगा और न्यायाधीश को बढ़ावा देने में बाधा आएगी।शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशालय किसी कार्यवाही को निरस्त करने के लिए न्यायाधीशोचित होगा यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता न्यायाधीशालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाही को रद्द करना अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करेगा।
115. एम. देवेंद्रप्पा (उपर्युक्त) के मामले में, माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि 'न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक उत्पीड़न का साधन नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध के रूप में निजी शिकायतकर्ता के हाथों में एक साधन होगा।116 है। चंद्रपाल सिंह और अन्य बनाम महाराज सिंह और अन्य (1982) 1 एस. सी. सी. 466 के मामले में, विद्वान न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया कि प्रतिवादी के विद्वत वकील ने हमें बताया कि झूठी गवाही देने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है और जब तक कि दृढ़ कार्रवाई अदालतें ऐसे व्यक्तियों पर भारी नहीं पड़ती हैं, तब तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया का उपहास किया जाएगा।हम प्रस्तुतीकरण में कुछ ताकत देखते हैं लेकिन यह भी उतना ही सच है कि दुखी और हताश वादियों को आपराधिक अदालत के क्षेत्राधिकार को सस्ते में लागू करके अपनी हताशा को दूर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
117. कर्नाटक राज्य बनाम मुनिस्वामी और अन्य, (1977) 2 एस. सी. सी. 699 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः
7.....।एक आपराधिक मामले में, एक लंगड़े अभियोजन के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर अभियोजन की संरचना टिकी हुई है और इसी तरह न्यायाधीश के हित में कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायाधीशालय को उचित ठहराएगा।न्यायाधीश के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक

हैं, हालांकि न्यायाधीश को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना है।इन टिप्पणियों को करने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता यह है कि उस प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को उचित रूप से साकार किए बिना, जो राज्य और उसके विषयों के बीच न्यायाधीश करने के लिए उच्च न्यायाधीशालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने का प्रयास करता है, उस मुख्य क्षेत्राधिकार के विस्तार और रूप को समझना असंभव होगा।"
(जोर दिया गया)
118. पंजाब राज्य बनाम V.K. खन्ना, ए. आई. आर. 2001 343, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास दुर्भावना की अवधारणा की व्याख्या करने का अवसर था।न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः
"25..... कानूनी वाक्यांश विज्ञान में 'दुर्भावनापूर्ण' अभिव्यक्ति का एक निश्चित महत्व है और यह संभवतः काल्पनिक कल्पना या यहां तक कि आशंकाओं से भी नहीं निकल सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह और कार्यों के मौजूदा निश्चित प्रमाण होने चाहिए जिन्हें अन्यथा वास्तविक नहीं माना जा सकता है-क्रियाएं अन्यथा प्रामाणिक नहीं हैं, यद्यपि अपने आप में दुर्भावनापूर्ण नहीं होगी जब तक कि यह कुछ अन्य कारकों के साथ असंगत न हो जो कार्य करने वाले की ओर से एक बुरे उद्देश्य या इरादे को दर्शाते हैं।119. विनीत कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2017) 13 एस. सी. सी. 369 के मामले में, पक्षों के बीच वित्तीय लेनदेन थे और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1882 (संक्षेप में "एन. आई. अधिनियम") की खंड 138 से एक शिकायत लंबित थी।

इस अवधि के दौरान, दूसरे पक्ष ने बलात्कार के लिए एक आपराधिक मामला दर्ज किया, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण करने में समाप्त हुआ, लेकिन विरोध याचिका पर, अभियुक्तों को तलब किया गया।उस मामले में भी तर्क दिए गए थे कि बलात्कार के लिए आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी और शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को एनआई अधिनियम की धारा 138 से अपराध के लिए बचाने के लिए गलत तरीके खंड शुरू की गई थी। उस मामले में कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः
"41. .... यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की मांग की जाती है, तो न्यायालय को इस प्रयास को बहुत हद तक विफल करना होगा।न्यायालय अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दे सकता है यदि मामला उन श्रेणियों में से एक में आता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1 0 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है।न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर कार्यवाही है जिसे संचालन या उत्पीड़न के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जब यह इंगित करने के लिए सामग्री है कि एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप खंड दुर्भावनापूर्ण तरीके खंड की जाती है और कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य खंड शुरू की जाती है, तो उच्च न्यायालय

सीआरपीसी की धारा 482 के से अपनी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा, जैसा कि हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1 1 11 में गणना की गई है, जो निम्नलिखित प्रभाव खंड हैः(एससीसीपी। 379, पैरा 102) "102.(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ उपस्थित किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।
उपरोक्त श्रेणी 7 वर्तमान मामले के तथ्यों में स्पष्ट रूप से आकर्षित है।हालांकि, उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 1 2 के फैसले को नोट किया है, लेकिन वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्यों का विज्ञापन नहीं किया है, जिन सामग्रियों पर आईओ द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार, हम पूरी तरह खंड संतुष्ट हैं कि वर्तमान एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 से अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए था और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था।" (जोर दिया गया)
120 है। आधार नियम, जैसा कि यहाँ पहले कहा गया है, यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से कार्यवाही में, तत्काल की तरह, एक वैध अभियोजन को विफल नहीं किया जाना चाहिए।

लेकिन, किसी भी दुर्भावनाआत्यन्तिक हस्तक्षेप के मामले में यह पूरी तरह से आवश्यक है।
121. तत्काल मामले में, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सोशल मीडिया प्रकाशन में पहली बार उनके द्वारा आरोप नहीं लगाए गए थे।यह उनका स्पष्ट कथन है कि जब अमरेश सिंह चौहान को वह नहीं मिला जो उनसे वादा किया गया था, तो उन्होंने एक पत्रकार राजेश शर्मा को इन तथ्यों का खुलासा किया और यह राजेश शर्मा हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ता को इन सभी बातों का खुलासा किया।वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सभी बातों को बताया।राज्य की विधानसभा में भी इसी विषय पर चर्चा हुई थी।इतना ही नहीं, एक वेब पोर्टल "तीसरी आंख का तहलका" ने इस खबर को प्रकाशित किया मात्र सूचना देने वाले ने भारतीय प्रेस परिषद में इसके विरुद्ध शिकायत की।इसके बाद, मुखबिर "तीसरी आँख का तहलका" के साथ साक्षात्कार में उपस्थित हुआ और आरोपों से इनकार किया।
122. 2018 की डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. संख्या. 2113 विरुद्ध याचिकाकर्ता, जो प्राथमिकी आर. नं. 2018 के 100 ने अपने जवाबी शपथ पत्र विरुद्ध इन सभी तथ्यों का खुलासा किया, जो सोशल मीडिया प्रकाशन का आधार है।राज्य को यह पता था।संक्षेप में, याचिकाकर्ता के अनुसार, सोशल मीडिया प्रकाशन में जो कुछ भी कहा गया था, वह वर्ष 2019 में बहुत पहले राज्य के साथ-साथ मुखबिर की जानकारी में था।जहां तक, 2018 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल.

संख्या. 2113 में जवाबी शपथ पत्र की कल्पना की गई है, निश्चित रूप से याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में इन सभी मुद्दों को उठाया।

123. फिर प्रश्न यह है कि तत्काल मामले में प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई?प्रश्न यहीं नहीं रुकता, यह थोड़ा गहरा है।मुखबिर 07.07.2020 को पुलिस को एक संचार देता है, जो राज्य के जवाबी शपथ पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया था।पुलिस को कुछ दिखाने के लिए कहा गया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह संहिता में एक अज्ञात प्रक्रिया है।लेकिन, पुलिस ने यह काम संभाल लिया।मुखबिर ने मुख्यमंत्री को दिनांक 07.07.2020 को भेजे गए अपने पत्र की एक प्रति भी अंकित की।याचिकाकर्ता ने पहले एक सलाहकार के रूप में टी. एस. आर. सी. एम. के साथ काम किया था।वे अनजान नहीं थे।

आरोप टी. एस. आर. सी. एम. को छू रहे थे। इसलिए, मुख्यमंत्री को दिनांक 07.07.2020 के पत्र को अंकित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।इसका कोई इरादा नहीं है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री को सूचित किया जाए कि ऐसा फिर से हुआ है या कोई सहायता मांगी जा सकती है, यह भी उन्हें चिह्नित किया गया था।लेकिन यह न्यायालय इसे यहां छोड़ देता है।

124. इसके बाद जो हुआ, वह आगे के इरादों को दर्शाता है।ऐसा प्रतीत होता है कि मुखबिर के दिनांक 07.07.2020 के संचार पर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।लेकिन, 15.07.2020 को, मुखबिर ने पुलिस से अनुरोध किया कि उसके मामले की जांच किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए।यह संचार सूचना देने वाले द्वारा दिनांक 10.09.2020 को अपने जवाबी शपथ पत्र में संलग्नक 2 के रूप में दायर किया गया है।याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से लगाए गए झूठे आरोपों को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष स्तर के अधिकारी से पूछने वाला मुखबिर कौन है?राज्य ने दिनांक 19.09.2020 के अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ इन दस्तावेजों को संलग्नक 1 के रूप में दाखिल किया है।जब 15.07.2020 को सूचना देने वाले ने पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी के राजपत्रित अधिकारी, एसआई नीमा रावत से जांच का अनुरोध किया, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।यह पत्र राज्य द्वारा दिनांक 19.09.2020 को दायर किए गए अतिरिक्त शपथ पत्र के संलग्नक 1 का भी हिस्सा है।इस पर, पुलिस के DIG ने 19.07.2020 को CO को मामले की जांच करने और 20.07.2020 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

125. तीन बातें हुईं।राज्य के अनुसार, सूचना देने वाले को दिनांक 07.07.2020 को अपने संचार के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी और राज्य के जवाबी शपथ पत्र के अनुसार, सूचना देने वाला याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करना चाहता था।पुलिस ने इसे अपने हाथ में लिया।सूचना देने वाला 15.07.2020 को लिखता है कि किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की जाए।पुलिस इसे स्वीकार करती है और 19.07.2020 को डी. आई. जी. ने सी. ओ. से जांच करने और 20.07.2020 को अत्यंत

जल्दबाजी में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की।तथ्य यह है कि इसे उस तिथि को प्रस्तुत नहीं किया गया था।जांच रिपोर्ट 30.07.2020 को तैयार की गई थी और एक आरटीआई के से, यह सूचना देने वाले को 31.07.2020 को दी गई थी।उसी दिन शाम को प्राथमिकी दर्ज की गई।यह न्यायालय अब इस कहानी के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता है।तथ्य यह है कि राज्य अत्यधिक तेजी से काम कर रहा था।

यह किया जा सकता है, लेकिन मुखबिर के अनुरोध पर जांच अधिकारी का परिवर्तन और जिस ईमानदारी के साथ डी. आई. जी. द्वारा इसे स्वीकार किया गया था और उसके एक दिन बाद रिपोर्ट मांगी गई थी, वह इरादे को दर्शाता है।क्या यह दुर्भावनापूर्ण है?

126 है। दिनांक 19.09.2020 के अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ, राज्य ने आरटीआई आवेदन से संबंधित दस्तावेज दाखिल किए, जो संलग्नक 4 है।वास्तव में, यह न्यायालय द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के संबंध में है कि 30.07.2020 को तैयार की गई एक रिपोर्ट को 31.07.2020 को अधिकतम गति के साथ कैसे दिया गया था ताकि उसी तिथि को प्राथमिकी दर्ज की जा सके। तर्कों के दौरान इस संलग्नक 4 पर चर्चा नहीं की गई है।लेकिन, इसके अनुसार, सूचना के लिए आवेदन मुखबिर द्वारा दिया गया था और जानकारी 31.07.2020 को प्रदान की गई थी।कुल नौ पृष्ठ दिए गए और Rs.10/-fee एकत्र किया गया।जाहिर है, यह शुल्क उचित नहीं लगता है। शायद किसी ने उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, सूचना के लिए आवेदन के साथ शुल्क जमा किया जाना है और उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2013 ("नियम") इखंड

आगे की प्रक्रिया प्रदान करता है।नियम 6 के अनुसार, आरटीआई के लिए आवेदन के साथ Rs.10/-fee का भुगतान किया जाना है, लेकिन नियम 6 के प्रावधान में दिए गए पृष्ठों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क भी आवश्यक है, जो कि Rs.2/-per पृष्ठ है।नियम 7 एक प्रक्रिया देता है कि आवेदन की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर, अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता आवेदक को सूचित की जानी चाहिए।

127. तत्काल मामले में, सीओ द्वारा 30.07.2020 को रिपोर्ट तैयार की गई थी।रिपोर्ट डी. आई. जी. को दी जानी थी, क्योंकि यह उनके आदेश के अनुसार है कि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, आरटीआई के से जानकारी के लिए आवेदन 28.07.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को दिया गया था और सीओ द्वारा जानकारी दी गई थी। दस्तावेज़ ने तेज गति से यात्रा की।यदि नियमों के नियम 6 और 7 के अनुसार 9 पृष्ठ दिए जाने थे, तो शुल्क थोड़ा अधिक होना चाहिए था, लेकिन राज्य द्वारा भी इसका दावा नहीं किया गया था।

128. याचिकाकर्ता के अनुसार, उसी दिन 11 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई और उसी दिन एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई।बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए आधी रात को 00 बजे।

तथ्य यह है कि मामले में गिरफ्तारी आधी रात को 11 बजे की गई थीः00.इस गति और इन तथ्यों के साथ-साथ इन तथ्यों के साथ कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप वर्ष 2019 में बहुत पहले राज्य के साथ-साथ मुखबिर के नोटिस में थे, निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण गंध करते हैं। असत्य को प्रदर्शित आदेश के लिए 09.07.2020 को आवेदन जमा आदेश में दुर्भावना दिखाई देती है अग्रेतर इसके बाद की गई कार्रवाइयों में दुर्भावना दिखाई देती है।

129 है। बार-बार यह तर्क दिया जाता है कि जांच के दौरान प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, याचिकाकर्ता ने सहयोग नहीं किया।जबकि याचिकाकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जांच के प्रत्येक चरण में सहयोग किया; उन्होंने प्रत्येक संचार का जवाब दिया और राज्य का यह बयान कि याचिकाकर्ता ने अपने आप में सहयोग नहीं किया, दुर्भावनापूर्ण है। इस संबंध में विभिन्न दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है।वास्तव में, लिखित बयान में, राज्य ने सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने वाले को किए गए संचार का विवरण दिया है।

130. आईओ का पहला संचार दिनांक 10.08.2020 है, जो जवाबी शपथ पत्र के लिए संलग्नक 3 है।इसका जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 11.08.2020 को दिया गया है और यह संचार राज्य द्वारा जवाबी शपथ पत्र के संलग्नक 4 में दायर किया गया है।दिनांक 11.08.2020 के इस संचार द्वारा, याचिकाकर्ता शिकायत की एक प्रति चाहता था जिस पर जांच की जा रही थी।ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है।आई. ओ. ने तुरंत याचिकाकर्ता को बताया होगा कि उसकी उपस्थिति की आवश्यकता क्यों है, जिस मामले की उसके द्वारा जांच की जा रही है।लेकिन, आईओ द्वारा 12.08.2020 को एक और संचार भेजा गया था जिसमें याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया प्रकाशन में उनके द्वारा किए गए दावे को साबित करने की आवश्यकता थी।

17.08.2020 को, याचिकाकर्ता ने आईओ को एक लंबा जवाब दिया, जो राज्य के जवाबी शपथ पत्र के लिए संलग्नक 6 है।इसमें प्रत्येक विवरण दिया गया है।

131. फिर जब 21.08.2020 को, आईओ ने याचिकाकर्ता को मूल दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता थी।फिर वही जवाब, जो याचिकाकर्ता द्वारा 17.08.2020 को पहले ही दिया जा चुका था, 26.08.2020 को याचिकाकर्ता द्वारा आईओ को दिया गया था।राज्य के जवाबी शपथ पत्र के लिए दिनांक 17.08.2020 के उत्तर, संलग्नक 6 पर बहस के दौरान चर्चा की गई है।

वास्तव में, यह आई. ओ. द्वारा किए गए प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर है। व्हाट्सएप संदेशों का विवरण और पैरा 2 में, याचिकाकर्ता का कहना है कि ये जानकारी अमरेश सिंह चौहान ने राजेश शर्मा को व्हाट्सएप के माध्यम द्वारा दी थी और अमरेश सिंह चौहान ने उन्हें सलाह दी थी कि सूचना देने वाला टीएसआरसीएम का बहनोई है। व्हाट्सएप संदेश, टेलीफोन वार्तालाप, सब कुछ याचिकाकर्ता द्वारा आईओ को प्रदान किया गया था और दिनांक 17.08.2020 को अपने संचार

में, याचिकाकर्ता ने आगे दोहराया कि सब कुछ उसके द्वारा 2018 के डब्ल्यूपीसीआरएल नंबर. 2113 में दायर किया गया था।इसे याचिकाकर्ता द्वारा असहयोग नहीं कहा जा सकता है।
132. राज्य की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने आईओ द्वारा दिए गए नोटिसों के जवाब में अप्रासंगिक और अप्रासंगिक दस्तावेज साझा किए। याचिकाकर्ता द्वारा आईओ को 11.08.2020,17.08.2020 और 26.08.2020 को दिए गए जवाबों को अप्रासंगिक और अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है।यह सच है कि तत्काल दर्ज प्राथमिकी में दो मुद्दे उठाए गए थे जो धन और संबंध का बयान है।लेकिन, याचिकाकर्ता ने विभिन्न बैंक खातों में टी. एस. आर. सी. एम. के कहने पर किए गए भुगतान के संबंध में भ्रष्टाचार के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए।व्हाट्सएप संदेश दिए गए थे।यहां तक कि आई. ओ. को टेलीफोन पर बातचीत भी दी गई। सी. ओ. की जांच रिपोर्ट ने उन्हें नहीं छुआ।वास्तव में, जांच रिपोर्ट ने उन बैंक जमा रसीदों को नहीं छुआ जो सोशल मीडिया प्रकाशन में दिखाए गए व्हाट्सएप संदेशों में स्पष्ट रूप से सुपाठ्य थे।राज्य ने इन तथ्यों के लिए आंखें क्यों बंद कर लीं?हो सकता है कि तत्काल प्राथमिकी में वे एकमात्र विचार नहीं थे, लेकिन उनका विचार महत्वपूर्ण था।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने जवाब नहीं दिया और जांच के दौरान सहयोग नहीं किया। याचिकाकर्ता ने सहयोग किया और निश्चित रूप से, यह कहना कि याचिकाकर्ता ने सहयोग नहीं किया, राज्य की ओर से भी दुर्भावनापूर्ण है।
133. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि वास्तव में, दिनांक 07.07.2020 का संचार और बाद में प्राथमिकी दर्ज करने और अन्य कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित हैं और केवल इसी आधार पर तत्काल प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए।

आगे के मुद्दे

134. इस न्यायालय ने माना है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध इस मामले में कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है और राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है।तत्काल मामले में प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है।लेकिन क्या अदालत को यहीं रुकना चाहिए?
135. प्राथमिकी में नं. 2018 के 100 में, पहले मुखबिर ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता द्वारा उस पर स्टिंग ऑपरेशन करने का दबाव डाला गया था और वह परेशान था।याचिकाकर्ता ने 2018 के डब्ल्यूपीसीआरएल नंबर.2113 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वास्तव में, पहले मुखबिर ने टीएसआरसीएम के रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के विभिन्न स्टिंग ऑपरेशन नहीं किए थे, बल्कि वास्तव में, जब वह 05.05.2018 को टीएसआरसीएम के कार्यालय गए थे, तो उन्होंने बातचीत रिकॉर्ड की थी।याचिकाकर्ता ने उन दस्तावेजों को 2018 के डब्ल्यूपीसीआरएल नंबर.2113 में दाखिल किया।2018 की एफ. आई. आर. 100 में आई. ओ., स्टिंग ऑपरेशन के

बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में प्राथमिकी करता है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। 01.2019 और 2018 के डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. संख्या. 2118 के बारे में भी, आरोप पत्र में।लेकिन अजीब बात यह है कि आई. ओ. द्वारा प्राथमिकी आर. नं. 2018 का 100 वां.सबसे मनोरंजक बात यह है कि आई. ओ. ने रजत प्रसाद बनाम सी. बी. आई. (2014) 6 एस. सी. सी. 495 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया।उन्हें कानून के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की जांच नहीं की।रजत प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में, वास्तव में, जिस व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन किया और रिश्वत की पेशकश की, वह भी एक आरोपी था।यहां याचिकाकर्ता के अनुसार, पहले मुखबिर ने स्टिंग करते समय विभिन्न व्यक्तियों को पैसे की पेशकश की, इस पहलू की कभी जांच नहीं की गई, इसे छोड़ दिया गया।लेकिन, याचिकाकर्ता को एक आरोपी बनाया गया, जिसने स्टिंग कराई।लेकिन, ये सभी मुद्दे प्राथमिकी नं. 2018 का 100, जो अब 2018 के डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या. 2113 में विचाराधीन है और उस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न राहतों का दावा किया गया है, जिसमें पहले मुखबिर द्वारा किए गए स्टिंग की जांच भी शामिल है।2018 के डब्ल्यूपीसीआरएल नंबर.2113 में दायर उनके जवाबी शपथ पत्र में भी यही प्रार्थना की गई थी।इसलिए, यह न्यायालय पहले मुखबिर द्वारा की गई डकैती के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से रोकता है।

136. तत्काल मामले में भी, सोशल मीडिया प्रकाशन में, याचिकाकर्ता ने टीएसआरसीएम के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बेशक, उन्होंने आरोप लगाए कि सूचना देने वाले और उसके रिश्तेदारों के खातों में टी. एस. आर. सी. एम. को रिश्वत के रूप में राशि जमा की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता स्वीकार करता है कि यह सच नहीं है।लेकिन, अन्य खाते थे।जमा पर्ची हैं जो पढ़ने योग्य हैं, उनकी जांच नहीं की गई है।क्या याचिकाकर्ता द्वारा टी. एस. आर. सी. एम. द्वारा अमरेश सिंह चौहान को कथित रूप से दिए गए विभिन्न खातों में धन जमा करने के संबंध में किया गया दावा सही है?किसी ने इसकी जांच नहीं की है।

137. राज्य के अनुसार, जब याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्रकाशन में आरोप लगाए, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने बहुत बुरी प्रतिक्रिया दी, जिससे मुखबिर को नुकसान पहुंचा।ये प्रतिक्रियाएँ राज्य द्वारा दायर जवाबी शपथ पत्र के संलग्नक 12 के साथ दायर की गई हैं।राज्य के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आम जनता के सदस्यों द्वारा की गई इन टिप्पणियों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध नफरत भड़काने के इरादे से काम किया।इन टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि टिप्पणी करने वाले लोग स्थिति से बहुत नाखुश थे।वे चाहते थे कि भ्रष्ट राजनेताओं को हटा दिया जाए।उन्होंने टिप्पणी की कि लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया है।क्या लोगों ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं?यदि ऐसा है, तो यह देश की संवैधानिक सरकार के इतिहास में सबसे खराब दिनों में से एक होगा, जहां कानून का शासन है।लोगों को इस

धारणा से नहीं रहना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि शुद्ध नहीं हैं।यदि कोई झूठे आरोप लगाता है जो कानूनी रूप से कार्रवाई योग्य हैं, तो कानून को अपना काम करना चाहिए।अगर उच्च पदों पर बैठे लोगों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप बिना उनकी जांच और सफाई के समाज में बने रहते हैं, तो इससे न तो समाज को विकास करने में मदद मिलेगी और न ही राज्य को कुशलता से काम करने में मदद मिलेगी।

138. मोहलत कोई नई बात नहीं है।

मनोज नरूला बनाम भारत संघ, (2014) 9 एस. सी. सी. 1 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "एक लोकतांत्रिक राजनीति जिसे सर्वोत्कृष्ट शुद्धता में समझा जाता है, वैचारिक रूप से भ्रष्टाचार और विशेष रूप से उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के लिए घृणित है, और राजनीति के अपराधीकरण के विचार के लिए घृणित है क्योंकि यह सामूहिक लोकाचार की वैधता को नष्ट करता है, नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को विफल करता है और इसमें कानून के शासन को बाधित करने की क्षमता है, यदि यह पटरी से नहीं उतरता है।लोकतंत्र, जिसे लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और पवित्रता की व्यापकता की उम्मीद करता है जो सुशासन का स्तंभ है। और अग्रेतर माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

"16. अपराध और भ्रष्टाचार साथ-साथ चलते हैं।उस तिथि से संविधान को अपनाया गया था i.e. 26-1-1950, भारत के इतिहास में एक लाल अक्षर दिवस, राष्ट्र उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के मूक गवाह के रूप में खड़ा था।भ्रष्टाचार कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट कर देता है।निरंजन हेमचंद्र साहितल बनाम महाराष्ट्र राज्य में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया हैः(एससीसी पीपी 654-655, पैरा 26)

"26. यह बिना किसी विरोधाभास के भय के कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार को मात्रा के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि यह माताओं की विकृति है, प्रगति के लिए सामाजिक इच्छा को नष्ट करता है, अवांछित महत्वाकांक्षाओं को तेज करता है, विवेक को मारता है, संस्थानों के गौरव को नष्ट करता है, देश के आर्थिक स्वास्थ्य को पंगु बनाता है, सभ्यता की भावना को नष्ट करता है और शासन के मज्जा को नष्ट करता है।यह ध्यान देने योग्य है कि धन का अनैतिक अधिग्रहण ईमानदारी में विश्वास करने वाले लोगों की ऊर्जा को नष्ट कर देता है, और इतिहास पीड़ा के साथ दर्ज करता है कि उन्होंने कैसे पीड़ित किया है। एकमात्र तथ्य यह मात्र कि सामूहिक संवेदनशीलता इस तरह की पीड़ा का सम्मान करती मात्र क्योंकि यह संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप मात्र।

139. भजनलाल (उपर्युक्त) के मामले में, भ्रष्टाचार पर माननीय न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-

"8. यद्यपि भ्रष्टाचार पश्चात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लक्ष्यों पश्चात समय-समय पर समीक्षा पश्चात जाती है, लेकिन परिभाषित और वैचारिक समस्याओं का पता लगाया जाता है और भ्रष्टाचार के विशाल कारणों और परिणामों पर दुनिया भर में लगातार बहस पश्चात जाती है, फिर भी भ्रष्टाचार पश्चात बुराइयाँ और उनका स्वतः-मादक प्रभाव समाज के कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा है और खतरनाक अनुपात में बढ़ता जा रहा है।इसलिए, यदि सभी मोर्चों पर और सभी स्तरों पर विषाक्तता को रोका और समाप्त नहीं किया जाता है, तो यह लोकतंत्र विरुद्ध नींव को ही अस्थिर और कमजोर कर देगा; नैतिक क्षय के माध्यम द्वारा कानून के शासन को थका देगा और पूरे प्रशासन को अप्रभावी और निष्क्रिय बना देगा।

9. भ्रष्टाचार की बुराइयों को सूचीबद्ध करने वाले अपोस्टोलिक उपदेशों का केवल अलंकारिक प्रचार और आकर्षक शब्दों के साथ नारे लगाने से उन्हें मिटाने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी कदमों की अनुपस्थिति में में कोई फायदा नहीं है; क्योंकि 'बर्दाश्त की गई बुराई का प्रचार किया जाता है'।140 का आंकड़ा। तत्काल मामले में याचिकाकर्ता ने टी. एस. आर. सी. एम. के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप संदेश दिए हैं, बातचीत रिकॉर्ड की है, बैंक जमा की रसीदें दी हैं और यह भी आरोप लगाया है कि कुछ जमीन अमरेश सिंह चौहान को दी गई थी, लेकिन इन मुद्दों की कभी जांच नहीं की गई।

141. भ्रष्टाचार एक ऐसा खतरा है जो जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।ऐसा लगता है कि समाज ने इसे सामान्य कर दिया है।लोक गीत लोगों की धारणा को दर्शाते हैं।उत्तराखंड में रहने वाले लोक गीत (नरेंद्र सिंह नेगी द्वारा लिखित और गाए गए) इस बात को दर्शाते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार जीवन का एक तरीका है।इनमें से दो गीतों के अंश इस प्रकार हैंः

1 ". मछू पानी पेंडू नी देखे
पंची दाल स्वेंडी नी देखे
लेंडू छे छा भाईजी घुस सबी जान दान लेंडू छे छा भाईजी घुस सबी जान दान
तू कुछ न कहे....

अनुवादः

14.

कोई भी कभी किसी मछली को पानी पीते या किसी पक्षी को पेड़ की शाखा पर सोते हुए नहीं देखता।सब जानते हैं कि हमारे अधिकारी भाई रिश्वत लेते हैं, लेकिन किसी ने उन्हें लेते नहीं देखा

यह.....●

2 ". कमीशन की मीट भात, ऋषभ को रेलोन कमीशन की मीट भात, ऋषभ को रेलोन ऋषभ को रेलोन रे
बस करो!!बिंदी ना सापोद अब कठगा ख़ेल्यो
काठगा जी खलेयो रे.....
15.
14https:. यूट्यूब।com/watch?v = q1kf _ lSPXq4 अनुवादः

सभी कमीशन का धन और रिश्वत की बारहमासी धारा।सभी कमीशन का धन और रिश्वत की बारहमासी धारा।
अभी रुकिए!!आप कितना खाने वाले हैं??अभी रुकिए...●
142. क्या इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच किए बिना लोगों की स्मृति में डूबने देना चाहिए या क्या न्यायालय स्वप्रेरणा ही मामले की जांच कराने के लिए कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके?

प्रतिद्वंद्वी संस्करण

143. इस अदालत ने निर्णय दिया है कि तत्काल प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की जांच प्राथमिकी सं. 2018 का 100 क्योंकि वे कथित रूप से उत्तराखंड राज्य में अशांति पैदा करने की बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, लेकिन याचिकाकर्ता का विरोधी संस्करण है, वह कहता है कि धन विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था, जैसा कि टीएसआरसीएम द्वारा अमरेश सिंह चौहान को प्रदान किया गया था।
144. एक ही अपराध या एक ही लेन-देन के से किए गए अपराधों के संबंध में क्रमिक एफआईआर की अनुमति नहीं है।इस संबंध में समानता का परीक्षण और/या परिणामी परीक्षण गाइड, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है।विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या एक ही अपराध में दूसरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है और किसी भी आकस्मिकता में इसकी जांच नहीं की जा सकती है।इसका उत्तर यह है कि एक ही अपराध पर लगातार प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, बशर्ते कि यह एक प्रतिद्वंद्वी संस्करण हो।
145. कारी चौधरी (उपरोक्त) के मामले में, अदालत ने कहा, "लेकिन जब एक ही प्रकरण के संबंध में प्रतिद्वंद्वी संस्करण होते हैं, तो वे दो अलग-अलग एफआईआर का आकार ले सकते हैं और जांच की जा सकती है।

151 https:. यूट्यूब।com/watch?v = Xpu-qSY S8-Y दोनों के से एक ही जांच एजेंसी द्वारा किया गया।उपकार सिंह प्राथमिकी वेद प्रकाश और अन्य (2004) 13 SCC 292 के मामले में, प्रतिद्वंद्वी संस्करण के इस पहलू पर अग्रेतर विचार किया गया है, वास्तव में, T.T के मामले में। एंटनी (ऊपर) ने स्वयं यह मत व्यक्त किया था कि "हमारे विचार में दूसरे या क्रमिक एफ. आई. आर. के आधार पर नए सिरे खंड जांच का मामला, जो एक ही लेन-देन के दौरान कथित रूप खंड किए गए एक ही या संबंधित संज्ञेय अपराध के संबंध में दायर किया गया है और जिसके संबंध में पहली एफ. आई. आर. के अनुसरण में या तो जांच चल रही है या धारा 173 (2) के से अंतिम रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के से या संविधान के अनुच्छेद 226/227 के से शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला हो सकता है।"इसका मतलब यह है कि एक जवाबी मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है और जांच की जा सकती है।

146. उपकार सिंह (उपर्युक्त) के मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि प्राथमिकी का एक अलग संस्करण एक अलग प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जा सकता है और इसकी जांच की जा सकती है।इसी प्रकार बाबूभाई (सुप्रा) और निर्मल सिंह काहलों (सुप्रा) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विभिन्न रूपों पर क्रमिक एफ. आई. आर. प्राथमिकी की जा सकती है और जाँच की जा सकती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226

147. इस याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से विचार किया जाता है।यह एक ऐसा क्षेत्राधिकार है जो काफी व्यापक है और प्रतिबंधित नहीं है।द्वारका नाथ बनाम आयकर अधिकारी, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 81 के मामले में, पैरा नं. 4 माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे की व्याख्या की, जो इस प्रकार हैः

"4. हम पहले प्रारंभिक आपत्ति लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे बनाए रखते हैं, तो कोई अन्य प्रश्न विचार के लिए नहीं उठेगा।संविधान का अनुच्छेद 226 कहता हैः

.....प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सभी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को उचित मामलों में किसी भी सरकार सहित उन प्रदेशों के भीतर दिशा-निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट भी शामिल है। परमादेश, निषेध अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण, या उनमें से कोई भी, भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी के प्रवर्तन के लिए और किसी भी उद्देश्य के लिए।"

यह लेख सर्वग्राही वाक्यांश में लिखा गया है और यह प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालयों को जहाँ भी अन्याय पाया जाए वहाँ पहुँचने की सर्वग्राही शक्ति प्रदान करता है।संविधान ने शक्ति की प्रकृति, किस उद्देश्य के लिए और किस व्यक्ति या प्राधिकरण के विरुद्ध इसका प्रयोग किया

जा सकता है, इसका वर्णन करने के लिए एक व्यापक भाषा का उपयोग किया।यह इंग्लैंड में समझे जाने वाले विशेषाधिकार रिटों की प्रकृति में रिट जारी कर सकता है; लेकिन उन रिटों का दायरा भी "प्रकृति" अभिव्यक्ति के उपयोग से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति उन रिटों की बराबरी नहीं करती है जिन्हें भारत में इंग्लैंड में जारी किया जा सकता है, लेकिन मात्र उनसे एक सादृश्य आकर्षित करता है।इसके अलावा, उच्च न्यायालय विशेषाधिकार रिट के अलावा अन्य निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकते हैं।यह उच्च न्यायालयों को देश की विशिष्ट और जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राहतों को ढालने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद के से उच्च न्यायालय की शक्ति के दायरे को बराबर करने का कोई भी प्रयास। इंग्लैंड जैसे तुलनात्मक रूप से छोटे देश में एकात्मक सरकार वाले भारत जैसे विशाल देश में, जो एक संघीय ढांचे के से कार्य कर रहा है, वर्षों से बढ़े हुए अनावश्यक प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों को लागू करना संविधान की धारा 226 के साथ अंग्रेजी न्यायालयों का विशेषाधिकार है।इस तरह का निर्माण लेख के उद्देश्य को ही विफल कर देता है।यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि उच्च न्यायालय इस अनुच्छेद से मनमाने ढंग से कार्य कर सकते हैं।लेख में कुछ सीमाएँ निहित हैं और अन्य को परिभाषित चैनलों के माध्यम द्वारा लेख को निर्देशित करने के लिए विकसित किया जा सकता है।

148. अग्रेतर रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम रोहतास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन और अन्य, 1976 (2) एस. सी. सी. 82 के मामले में, माननीय न्यायाधीशालय ने कहा कि कानून का संरक्षक न्यायाधीश है और एक शक्तिशाली दवा को विवेकपूर्ण तरीके से प्रशासित किया जाना चाहिए।पैरा 9 में न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

अनुच्छेद 226 के से उच्च न्यायालयों की विस्तारात्मक और असाधारण शक्ति उतनी ही व्यापक है जितना कि उपयोग की गई भाषा का विस्तार इंगित करता है और इसलिए किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है-यहां तक कि एक निजी व्यक्ति भी और किसी (अन्य) उद्देश्य के लिए उपलब्ध हो सकता है-यहां तक कि जिसके लिए एक अन्य उपाय मौजूद हो सकता है।1963 में अनुच्छेद 226 में संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 226 (1 -ए) ऐसे व्यक्ति के निवास के अभिव्यंजक संदर्भ द्वारा किसी भी व्यक्ति के समावेशी के रूप में रिट शक्ति के लक्ष्यों को दोहराता है।लेकिन क्षेत्राधिकार की पुष्टि करना एक बात है, दूसरा चीन की दुकान में बैल की तरह इसके स्वतंत्र अभ्यास को अधिकृत करना है।इस न्यायालय ने इस असाधारण उपाय के उपयोग पर विवेकपूर्ण और स्पष्ट प्रतिबंधों को स्पष्ट किया है और उच्च न्यायालय उन पूर्ण अवरोधों के बाद नहीं जाएंगे, सिवाय इसके कि स्थिति की राक्षसी या अन्य असाधारण परिस्थितियां समय पर न्यायिक हस्तक्षेप या जनादेश की मांग करती हैं।कानून का संरक्षक न्यायाधीश है और एक शक्तिशाली दवा को विवेकपूर्ण तरीके से प्रशासित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण पूर्वावलोकन और स्पष्ट संभावना में बोलते हुए, रिट शक्ति, मोटे तौर पर, लोगों के

लिए चौकस रही है और उस शक्ति को कम करने या समाप्त करने से मानवाधिकारों को खतरा हो सकता है।

हमारा मानना है कि यहां पुरस्कार अनुच्छेद 226 की कानूनी पहुंच के बाद बाहर नहीं है, हालांकि इस शक्ति को गंभीर रूप के बाद विवेकपूर्ण नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।
(जोर दिया गया)
149. एयर इंडिया सांविधिक निगम बनाम संयुक्त श्रम संघ, (1997) 9 एस. सी. सी. 377 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "संस्थापकों ने स्व-आरोपित सीमाओं को छोड़कर वैधानिक के अनुच्छेद 226 के से उच्च न्यायालय की शक्तियों पर कोई सीमा या बंधन नहीं लगाए।न्यायालय की भुजा कहीं भी पाए जाने पर अन्याय तक पहुँचने के लिए काफी लंबी है।इस पर प्रहरी के रूप में न्यायाधीशालय को दिए गए तथ्यों में न्यायाधीश करना है।
150। गुजरात स्टील ट्यूब लिमिटेड के मामले में। बनाम गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा और अन्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 593, अनुच्छेद 226 के दायरे की अग्रेतर जांच की गई है और न्यायालय ने इसके तहत टिप्पणी की हैः
"73. जबकि अनुच्छेद 226 के से उपचार असाधारण है और एंग्लो सैक्सन विंटेज का है, यह अंग्रेजी प्रक्रियाओं की कार्बन कॉपी नहीं है।अनुच्छेद 226 एक बख्शने वाली शल्य चिकित्सा है लेकिन जहाँ अन्याय होता है वहाँ लैंसेट काम करता है।जबकि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता जैसे पारंपरिक प्रतिबंध अदालत को रोकते हैं, और न्यायिक शक्ति को सामान्य रूप से वहां नहीं जाना चाहिए जहां अन्य दो शाखाएं चलने से डरती हैं, न्यायिक साहस परेशान नहीं होता है जहां स्पष्ट अन्याय सकारात्मक कार्रवाई की भी मांग करता है।अनुच्छेद 226 के व्यापक शब्दों को उनकी शिकायतों में कम संख्या के लोगों की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है यदि विषय अदालत के प्रांत से संबंधित है और उपाय न्यायिक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है।अनुच्छेद 226 के बारे में एक मूल रंग है, जो दृष्टिकोण में एंग्लोफिलिक या एंग्लोफोबिक नहीं है।इस न्यायशास्त्र के दृष्टिकोण से देखने पर, हमें इस बात को लेकर सतर्क रहना होगा कि अनुच्छेद 226 एक अपील के रूप में बड़ा है और जहां एक गंभीर त्रुटि हुई है, वहां हस्तक्षेप करने में विफल नहीं होना चाहिए।इसके अलावा, हम यहां उच्च न्यायालय के फैसले पर अपील करने के लिए बैठे हैं।और एक अपीलीय शक्ति तब हस्तक्षेप नहीं करती है जब अपील किया गया आदेश सही नहीं होता है, बल्कि मात्र तब होता है जब यह स्पष्ट रूप से गलत होता है।अंतर वास्तविक है, हालांकि ठीक है।
79. इस प्रस्तुतीकरण का आधार, जैसा कि हम इसकी कल्पना करते हैं, उच्च विशेषाधिकार रिटों के इर्द-गिर्द बुनी गई पारंपरिक सीमाएँ हैं।इस सीमा की शुद्धता की जांच किए बिना, हम इसकी अवहेलना करते हैं क्योंकि जबकि अनुच्छेद 226 शाही लेखन से प्रेरित है, इसका विस्तार और दायरा पहले की छिपी हुई ब्रिटिश प्रक्रियाओं से अधिक है।हम वही हैं जो हम हैं क्योंकि हमारे

संविधान निर्माताओं ने हमारी परिस्थितियों में गलतियों को सही करने के लिए उच्च न्यायपालिका में एक व्यापक आरक्षित शक्ति की आवश्यकता महसूस की है।जहां उपयोग की जाने वाली भाषा बुद्धिमानी से व्यापक है, विरासत न तो हैमस्ट्रिंग कर सकती है और न ही प्रथा को सीमित कर सकती है।भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश प्रतिमान आवश्यक रूप से आदर्श नहीं हैं।अनुच्छेद 226 में परिकल्पित रूप से उपयोग की गई अभिव्यंजक अभिव्यक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि कोई भी आदेश जो निचले प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था, उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता था।

जहां घोर अन्याय या घातक अवैधता और इस तरह की चीजें मौजूद हैं, उन्हें छोड़कर, हस्तक्षेप करने की शक्ति और अनिच्छा की बहुत व्यापकता, अभ्यास को बाधित करती है लेकिन शक्ति उत्सादित करना नहीं करती है।

(जोर दिया गया)

151. प्राथमिकी आदि को रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्रकाशन में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों, विशेष रूप से याचिका के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों की कोई जांच की मांग नहीं की है।प्राथमिकी में सह-अभियुक्त को इस अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे एसएलपी नं. 2020 का 4189.एसएलपी को खारिज कर दिया गया था लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि "हम, यद्यपि स्पष्ट कर सकते हैं कि मात्र इसलिए कि प्रतिवादी अंतरिम जमानत पर है, यह प्रतिवादी को याचिकाकर्ता द्वारा की गई जांच में सहयोग नहीं करने का अधिकार नहीं देगा क्योंकि आरोप गम्भीर हैं।"आरोपों की गंभीरता मात्र सूचना देने वाले से संबंधित झूठ के संबंध में नहीं है।गंभीरता भ्रष्टाचार के आरोपों की भी है।

152. प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय किसी भी जांच के लिए स्वतः आदेश दे सकता है। बैंगलोर विकास प्राधिकरण बनाम विजया लीजिंग लिमिटेड और अन्य, (2013) 14 एस. सी. सी. 737 के मामले में, चुनौती की अनुपस्थिति में में पारित एक आदेश को वैध ठहराया गया था। अब यदि यह न्यायालय किसी जांच के संबंध में कोई आदेश पारित करता है तो यह अमरेश सिंह चौहान और टी. एस. आर. सी. एम. को भी छूता है। टी. एस. आर. सी. एम. इन याचिकाओं में पक्षकार नहीं है।लेकिन फिर, यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज करने या जांच का आदेश देने से पहले, जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने या जांच का आदेश देने का प्रस्ताव है, उसे पक्षकार बनाया जाए।वास्तव में, ई. शिवकुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, (2018) 7 एस. सी. सी. 367 माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि "अभियुक्त को जाँच के स्तर पर सुने जाने की आवश्यकता नहीं है।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था या प्रति सुनवाई नहीं की गई थी, आक्षेपित निर्णय को वर्णित के रूप में लेबल करने का आधार नहीं हो सकता है।

153. स्थापित कानून को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय अनुच्छेद 226 के से क्षेत्राधिकार के दायरे में याचिका के पैरा 8 में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश दे सकता है।

इस अदालत का विचार है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, सच्चाई को उजागर करना उचित होगा।यह राज्य के हित में होगा कि शंकाओं को दूर किया जाए।इसलिए, याचिका को स्वीकार करते हुए, यह न्यायालय जांच का भी प्रस्ताव करता है।
154. आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि सीबीआई को तत्काल याचिका के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

155. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं मानता हूंः
155.1.तत्काल प्राथमिकी आर. में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ताओं. 155.2 के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं।दिनांक 07.07.2020 (i.e., सूचना देने वाले द्वारा 09.07.2020 को पुलिस को दिया गया आवेदन) पर अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं है। 155.3 .तत्काल प्राथमिकी आर. में लगाए अग्रेतर आरोपों की प्राथमिकी आर. नं. 2018 का 100 वां.यह, वास्तव में, एक ही लेनदेन (i.e.) पर दूसरी प्राथमिकी दर्ज करना है। उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध साजिश करना), जो कि प्राथमिकी नं. 2018 का 100 वां.कानून से तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं है। 155.4.दिनांक 07.07.2020 के संचार, बाद की जांच के साथ-साथ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और उसके बाद की अन्य गतिविधियों को दुर्भावना द्वारा प्रेरित किया गया है। 155.5 .तदनुसार, प्राथमिकी नं. 2020 का 265, भा.दं.सं. की धारा 420,467,468,469,471 और 120 बी के से, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून को इसके द्वारा रद्द कर दिया गया है। 155.6.सीबीआई देहरादून के पुलिस अधीक्षक को डब्ल्यूपीसीआरएल संख्या में याचिका के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। 2020 का 1187 और कानून के अनुसार, शीघ्रता के साथ मामले की जांच करें।
155.7 है।पूरी पेपर-बुक दो दिनों के भीतर ई-मेल और हार्डकॉपी दोनों के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सी. बी. आई. देहरादून को भेजी जाए।
155.8.याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता कल दोपहर तक पंजीकरण को सॉफ्ट कॉपी के साथ-साथ पेपर-बुक की हार्ड कॉपी प्रदान करेंगे।

156. तीनों याचिकाओं को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

(रवींद्र मैथानी, जे.)

27.10.2020

जितेंद्र